www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

17 फरवरी-23 फरवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467

अरविंद केजरीवाल

चुनाव से पहले चुनाव के बाद

2012 में मनोवैज्ञानिक डेविड थामस की एक चर्चित किताब आई. इस किताब का नाम है नार्सिसिज्म: बिहाइंड द मास्क. नार्सिसिज्म एक मनोवैज्ञानिक कुंठा है. कुछ लोग इसे व्यक्तित्व विकार भी मानते हैं. शब्दकोश में इस शब्द का अर्थ ढूंढने पर पता चलता है कि नार्सिसिज्म को हिंदी में आत्मकामी कहते हैं. इस किताब के शीर्षक का मतलब है, मुखौटे के पीछे का आत्मकामी. इस किताब में आत्मकामियों के कुछ लक्षण बताए गए हैं. बिना किसी बड़ी उपलब्धि और उत्कृष्ट निपुणता के बावजूद एक आत्मकामी व्यक्ति यह मानता है कि पूरी दुनिया उसे दूसरों से महान और विशेष मानती है. ऐसे लोगों को सत्ता और पावर से बहुत लगाव होता है, लेकिन उसे वे सामने नहीं आने देते. वे अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को रखते हैं, जो उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें महान मानते हैं. आत्मकामी व्यक्ति अपनी बुराई या विरोध को सहन नहीं कर सकता है. जो उसे महान नहीं मानते हैं, उन्हें वह भला-बुरा कहता है. वह लगातार पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ़ खींचने की फिराक में रहता है. वह हमेशा ख़बरों में बना रहना चाहता है. आत्मकामी व्यक्ति लोगों को इस्तेमाल करता है और काम निकल जाने के बाद उन्हें छोड़ देता है. वह हमेशा भविष्य की बड़ी सफलता, भारी आकर्षण, पावर, अपनी बुद्धि एवं विचारों की सफलता की कल्पनाओं में खोया रहता है. ऐसा व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है और समझता है कि पूरी दुनिया उससे ईर्ष्या करती है. ऐसा व्यक्ति खुद को सर्वगुण संपन्न और दूसरे को महामूर्ख समझता है. आत्मकामी व्यक्ति अपने नजरिए और व्यवहार में घमंडी होता है.

मनीष कुमार

अरविंद केजरीवाल की राजनीति और व्यक्तित्व को देखें, तो डेविड थामस की किताब याद आ जाती है. अरविंद केजरीवाल ने भी खुद की महानता का एक बड़ा आडंबर बना रखा है. केजरीवाल ने खुद को एक सुपर इंटेलिजेंट आईआईटी का इंजीनियर, जिसने आईएएस की नौकरी को समाज सेवा के लिए लात मार दी, ऐसे क्रांतिकारी के रूप में प्रोजेक्ट किया है. जबकि वह एक आईआरएस अधिकारी थे. वह खुद को महान और दूसरों को तुच्छ समझते हैं. जब कभी संयम टूटता है, तो सार्वजनिक रूप से तू-तड़ाक करने लगते हैं और साथ ही खुद को एक संत भी बताते हैं. वह कहते हैं कि अगर पैसे कमाने होते, तो इनकम टैक्स की नौकरी नहीं छोड़ता. अरविंद लोगों को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि वह जीवन के ऐशोआराम को छोड़कर राजनीति में आए हैं. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखकर भी यह एहसास होता है कि वे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि केजरीवाल के भक्त हैं. वे उनकी महानता के गीत गाते हैं और उनकी बुराइयों की तरफ़ देखना भी नहीं चाहते हैं. लेकिन सच्चाई का चरित्र ही कुछ ऐसा होता है कि वह आज नहीं तो कल, सामने आ ही जाती है. सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति एक ईमानदार राजनीति है या फिर यह एक आत्मकामी व्यक्ति की सत्ता की भूख का नतीजा है, जो ऊपर से ईमानदार राजनीति का महज ढोंग कर रहा है. इसे समझना आसान है. बस, उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, उसे जानना है और यह साफ़ हो जाएगा कि उनकी राजनीति और व्यक्तित्व में कितनी ईमानदारी है.

उन दिनों भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई तेज थी. आंदोलन था. राजनीति नहीं थी. स्टेज पर अन्ना हजारे थे. बाबा रामदेव और किरण बेदी भी थीं. साथ ही और भी कई सारे दिग्गज बैठे थे. माइक पर अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे थे. अरविंद लोगों को बता रहे थे कि दोस्तो, अभी-अभी हम बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में 370 पृष्ठों का सुबूत थाने में जमा कराकर आ रहे हैं. हम कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए घोटाले के ख़िलाफ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर आ रहे हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार हुआ, फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुई, साजिश हुई, फॉर्जरी हुई. ये सारे के सारे मामले आपराधिक हैं और इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाए. अगर सात दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो हम कोर्ट जाएंगे, आदेश लेकर आएंगे पुलिस के ख़िलाफ़ कि एफआईआर दर्ज कराई जाए. तालियों की गड़गड़ाहट के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारे पास सुबूत है कि जो ट्रॉली खरीदी गई, वह बाज़ार में डेढ़ लाख रुपये की मिलती है, लेकिन उन्होंने पौने तीन लाख रुपये में खरीदी. यह दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी है. उन्होंने एक हृदय रोग की मशीन खरीदी है. उसकी भी क़ीमत बाज़ार में डेढ़ लाख रुपये है, लेकिन उन्होंने पांच-पांच लाख में सौ मशीनें खरीदी हैं. मतलब कि पांच करोड़ रुपये का चूना. जनता की तरफ़ से तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आती है और लोग शेम-शेम कहने लगते हैं. यह कार्यक्रम टीवी पर भी दिखाया जा रहा था. जिन लोगों ने देखा, उन्हें सचमुच कांग्रेस की सरकार से घृणा हो रही होगी और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लड़ने वाले एक योद्धा नज़र आ रहे थे. अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में एक और खुलासा किया. उन्होंने कहा, प्रसार भारती ने एक कंपनी को 246 करोड़ रुपये का ठेका दिया और उस कंपनी ने कुछ घंटों के अंदर वह ठेका दूसरी कंपनी को 170 करोड़ में दे दिया. मतलब यह कि काम सिर्फ़ 170 करोड़ रुपये का था और कुछ ही घंटों में एक कंपनी करोड़ों रुपये लेकर इंग्लैंड भाग गई. इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई. उन्होंने कहा, मैं जो बात बता रहा हूं, वह बात हवा की नहीं है. हमने सीवीसी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट और कई अन्य स्रोतों से ये जानकारियां ली हैं. यह हम नहीं कह रहे, सरकार की एजेंसियां खुद कह रही हैं.

यह घटना 14 नवंबर, 2010 की है और यह था अरविंद केजरीवाल का ईमानदार चेहरा. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बेबाक बोलने वाला चेहरा. इसके बाद अन्ना के नेतृत्व में केजरीवाल लोकपाल आंदोलन का हिस्सा बने. फिर राजनीतिक दल बनाया. भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता, भ्रष्टाचार से लड़ने और

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले जिन-जिन मुद्दों को प्राथमिकता दी, उन्हें वह पूरा करने में विफल रहे. एक महत्वपूर्ण मुद्दा था ठेके पर काम करने वाले लोगों का. मतलब यह कि दिल्ली में ज़्यादातर विभाग स्थायी नौकरी देने की जगह लोगों से ठेके पर काम कराते हैं. इनमें टीचर, चपरासी, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, मजदूर और ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जिनकी नौकरी परमानेंट नहीं है. केजरीवाल ने वादा किया था कि सरकार बनाते ही वह दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करेंगे.

अरविंद केजरीवाल ने किताब की चोरी की है? 03

पेड़ पर पैसा उगाने की कला 05

ख़तरे में नीतीश सरकार 06

साई की महिमा 12

अरविंद केजरीवाल : चुनाव से पहले, चुनाव के बाद

> चुनाव से पहले केजरीवाल ने यह वादा किया कि ऐसे सभी लोगों का बिल माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसे लोगों को न तो माफी मिली और न ही बिल में कोई छूट दी गई. ये लोग अब अपना माथा पीट रहे हैं. पानी की छूट पर चुनाव से पहले जो वादा किया, उसे लागू नहीं किया. मुफ्त पानी देने में केजरीवाल ने एक शर्त लगा दी. मुफ्त पानी सिर्फ़ उन चंद परिवारों को मिल रहा है, जिनके घरों में मीटर लगा है. ज़्यादातर लोगों के घरों में मीटर नहीं है, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा. लेकिन टीवी में छाने की रणनीति में अरविंद ने उन लोगों को भुला दिया,

पृष्ठ एक का शेष

भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाले कार्यकर्ताओं ने अरविंद का जमकर साथ दिया. अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि वह अपनी मनमर्जी से राजनीति में नहीं आए, उन्हें बाध्य होना पड़ा है. यहां से ही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लड़ने वाले योद्धा से एक कुटिल राजनीतिज्ञ में बदलने लग गए. टीवी चैनलों में जब इंटरव्यू होता, तो हर जगह सिर्फ़ एक ही बात करते कि वह न तो चुनाव लड़ेंगे, न कोई कुर्सी लेंगे. वह न सीएम बनना चाहते हैं और न पीएम. वह तो राजनीति में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आए हैं.

दिल्ली चुनाव से पहले के उनके बयानों और आज की परिस्थिति में काफी विरोधाभास पैदा हो गया है. आजकल अरविंद केजरीवाल अपनी ही कही बातों को हर दिन गलत साबित करने में जुटे हुए हैं. सबसे पहला झटका अरविंद केजरीवाल ने तब दिया, जब वह चुनाव लड़ने को तैयार हो गए और सीएम बनने के लिए भी राजी हो गए. लोग तो उन्हें भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने वाला योद्धा समझ रहे थे, लेकिन वह पार्टी बनने के साथ ही राजनीति का घिनौना खेल खेलना शुरू कर चुके थे. दिल्ली में चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी हर जगह पोस्टर लगा रही थी कि अगर कांग्रेस को वोट दिया, तो बहू–बेटियों की इज्जत लूट ली जाएगी. केजरीवाल का दूसरा सबसे अहम मुद्दा भ्रष्टाचार. चुनाव प्रचार के दौरान वह खुद को सबसे ईमानदार नेता घोषित करते रहे और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भ्रष्ट बताते रहे. कैमरा देखते ही वह बोल पड़ते कि शीला दीक्षित तो भ्रष्टाचार की पर्याय हैं. चुनाव प्रचार में वह हमेशा कहते थे कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको सजा मिलेगी. न सिर्फ़ सजा मिलेगी, बल्कि इन भ्रष्टाचारियों ने जनता का पैसा लूटा है. इनसे हम पैसा वापस लेंगे, जनता का पैसा वापस लाएंगे. सरकार बनने के बाद से आज तक भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाना तो दूर, किसी भी घोटाले की जांच के आदेश तक नहीं दिए गए.

चुनाव जैसे–जैसे नजदीक आते गए, तो उन्होंने लोगों को झांसा देने के लिए एक और चाल चली. वह इसलिए, क्योंकि चुनावी सर्वे आने लगे थे. हर सर्वे का नतीजा यह था कि दिल्ली में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है. तब सवाल यह उठा कि फिर आम आदमी पार्टी किसके साथ जाएगी. लोग कांग्रेस से नाराज थे और दूसरा विकल्प सिर्फ़ भाजपा थी. अरविंद केजरीवाल को लगा कि दोनों में से किसी के साथ जाना आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया. उन्होंने यह ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी न तो किसी से समर्थन लेगी और न ही समर्थन देगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बहुमत नहीं मिला, तो वह विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन किसी भी क़ीमत पर न तो भाजपा और न ही कांग्रेस से समर्थन लेंगे और न ही देंगे. जब चुनाव के नतीजे आए, तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. आम आदमी पार्टी ने 18 मुद्दों की एक लिस्ट तैयार की और कांग्रेस एवं भाजपा से इन मुद्दों के आधार पर समर्थन मांगा. समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल आज भी यह सफेद झूठ बेझिझक बोलते हैं कि हमने किसी से समर्थन नहीं मांगा. सवाल यह उठता है कि अगर समर्थन नहीं मांगा, तो वह चिट्ठी क्यों लिखी? अपने मैनिफेस्टो से 18 मुद्दों को क्यों अलग किया? कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं मुद्दों के आधार पर बाहर से समर्थन देने का फ़ैसला लिया. हालांकि कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक समर्थन देने का विरोध कर रहे थे. एक स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस के विधायक ने अरविंद केजरीवाल को झूठा, मक्कार और बंदर के हाथ में उस्तरा जैसी बातें भी कहीं. फिर भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थन स्वीकार किया, क्योंकि यह फ़ैसला कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लिया था. कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर भ्रष्टाचार से लड़ना, टकले को कंघी बेचने जैसा है. इस गठजोड़ की वजह से अरविंद केजरीवाल को कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार के मुद्दों से समझौता करना पड़ा. जो केजरीवाल चुनाव से पहले शीला दीक्षित और राजकुमार चौहान को जेल भेजने की बात कर रहे थे, वही केजरीवाल चुनाव के बाद कहते हैं कि उनके पास शीला दीक्षित के ख़िलाफ़ कोई सुबूत नहीं है. अब तो यह केजरीवाल ही बात सकते हैं कि 2010 में दिया हुआ बयान और 370 पेजों का सुबूत झूठा था या फिर आज जो केजरीवाल बोल रहे हैं, वह सफेद झूठ है.

अरविंद केजरीवाल खुद को सबसे ईमानदार व्यक्ति साबित करने में जुटे हैं. उन्होंने एक आभामंडल अपने इर्द–गिर्द तैयार किया है और उनकी हार्दिक इच्छा है कि देश की जनता और मीडिया उन्हें उसी नज़र से देखे. अगर कोई भी व्यक्ति या पत्रकार इस पर सवाल खड़ा करे, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उसे झट से भाजपा और कांग्रेस का दलाल बता देते हैं. कहने का मतलब यह कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देश में अकेले ऐसे हैं, जो सच्चाई, सादगी और ईमानदारी की गंगोत्री हैं. इसके अलावा दुनिया के बाकी सारे लोग चोर, बेईमान, भ्रष्ट और दलाल हैं. लेकिन चुनाव के बाद ही अरविंद केजरीवाल की असलियत खुल गई. झूठ, लोभ और आडंबर का पर्दाफाश हो गया. चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल यह कहते रहे कि मैं राजनीति में सेवा करने आया हूं. पैसे कमाने होते, तो मैं इनकम टैक्स की नौकरी क्यों छोड़ता. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता न बंगला लेगा और न ही गाड़ियां. आम आदमी पार्टी के चुने हुए लोग अपने पुराने घर में ही रहेंगे. इन्हीं सारी बातों के झांसे में आकर लोगों ने वोट दिया था. दिल्ली के लोगों को लगा था कि ये लोग दूसरों से अलग हैं, लेकिन सरकार बनते ही इनकी असलियत सामने आ गई. अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के जरिए दिल्ली में एक बड़ा बंगला ढूंढ लिया. दरअसल, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने पहले घर देने से मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं, दो दिनों में क्या हुआ कि उसी कांग्रेस सरकार ने भगवान दास रोड पर आलीशान बंगला दे दिया. इसमें दस कमरे थे, लॉन था. बंगला आलीशान था. वैसे मुख्यमंत्री को ऐसा घर मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है. मुख्यमंत्री को अगर सरकारी बंगला नहीं मिलेगा, तो इन बंगलों में कौन रहेगा?

समस्या यह है कि वह खुद को त्यागी बताने के चक्कर में आदर्श राजनीति को नाटक–नौटंकी में तब्दील करने में महारथ हासिल कर चुके हैं. यही वजह है कि जब मीडिया में बंगले की ख़बर आ गई, तो किरकिरी हो गई. आदर्शवाद की डींगे हांकने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं को शर्मसार होना पड़ा. लेकिन कुछ तो ऐसे थे, जिन्हें शर्म भी नहीं आई. वे झूठ बोलते रहे. कुमार विश्वास ने तो यहां तक कहा कि इस मकान में पांच कमरे हैं, जिसमें दो कमरों में अरविंद रहेंगे और बाकी के तीन कमरे जनता की सेवा के लिए ऑफिस के रूप में इस्तेमाल होंगे. केजरीवाल ने तो पहले यह बयान भी दे दिया कि उन्होंने इस मकान को देख रखा है और इस मकान को लेना कोई बुराई नहीं है. पहले तो आदर्शवाद की टांय–टांय फिस्स हुई, फिर झूठ बोलकर वे अपने ही कार्यकर्ताओं की आलोचना के शिकार हुए. सोशल मीडिया में लोग पार्टी छोड़ने लगे. जब अरविंद केजरीवाल को समझ में आया कि इस बंगले के चक्कर में पार्टी को नुकसान हो रहा है, लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तब उन्हें दबाव में आकर फ़ैसला बदलना पड़ा. इस दौरान यह भी देखा गया कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने 16 लाख रुपये की इनोवा कार भी ली और उस पर वीआईपी नंबर भी लगवाया. जब मीडिया ने पूछा, तो आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने कहा, हां..हम सरकारी गाड़ी लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे, क्योंकि हम चोरी नहीं कर रहे हैं. बंगला या गाड़ियां लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ढोंग और धोखेबाजी से जनता का विश्वास जीतना सचमुच निंदनीय है.

अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले तक यही कहते आए कि वह व्यवस्था परिवर्तन करने वाली राजनीति में विश्वास करते हैं. वह भारत को डायरेक्ट–डेमोक्रेसी यानी सहभागी–प्रजातंत्र में तब्दील करना चाहते हैं. इस व्यवस्था में सरकार के हर फ़ैसले में जनता की राय ज़रूरी है. इसलिए सरकार को सीधे जनता के बीच ले जाना, जनता द्वारा ही नीतियां बनाना और जनता से पूछकर सरकार चलाना जैसी बातें अरविंद केजरीवाल करते हैं. इसी बात को साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार सड़क पर बुलाया. लेकिन जब जनता आई, तो न सिर्फ़ जनता दरबार की पोल खुली, बल्कि अरविंद केजरीवाल के व्यवस्था परिवर्तन के नजरिए पर सवाल खड़ा हो गया. जनता दरबार में भगदड़ के डर से सबसे पहले भागने वाले स्वयं अरविंद केजरीवाल थे. यह केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला कार्यक्रम था. उन्होंने जनता दरबार इसलिए बुलाया था, क्योंकि वह इस बात को साबित करना चाहते थे कि वह सरकार सड़क से चला सकते हैं. अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि हमारे संविधान को बनाने वाले नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुष थे. उन्होंने भारत की विशालता को देखते हुए डायरेक्ट या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को खारिज किया था. केजरीवाल को शायद यह लगता है कि वह उन महापुरुषों से ज़्यादा राजनीतिक–सामाजिक समझ और ज्ञान रखते हैं. लेकिन, जब असलियत से सामना हुआ, तो अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार ही बंद कर दिया. वैसे अरविंद केजरीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन का ब्लूप्रिंट अपनी एक पुस्तक स्वराज में लिखा है. दु:ख की बात यह है कि उक्त किताब भी विवादों के घेरे में आ गई है, क्योंकि यह आरोप लगा है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी दूसरी किताब से विचारों और वाक्यों की चोरी की है.

चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते गए, तो उन्होंने लोगों को झांसा देने के लिए एक और चाल चली. वह इसलिए, क्योंकि चुनावी सर्वे आने लगे थे. हर सर्वे का नतीजा यह था कि दिल्ली में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है. तब सवाल यह उठा कि फिर आम आदमी पार्टी किसके साथ जाएगी. लोग कांग्रेस से नाराज थे और दूसरा विकल्प सिर्फ़ भाजपा थी. अरविंद केजरीवाल को लगा कि दोनों में से किसी के साथ जाना आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया. उन्होंने यह ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी न तो किसी से समर्थन लेगी और न ही समर्थन देगी.

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले जिन–जिन मुद्दों को प्राथमिकता दी, उन्हें वह पूरा करने में विफल रहे. एक महत्वपूर्ण मुद्दा था ठेके पर काम करने वाले लोगों का. मतलब यह कि दिल्ली में ज़्यादातर विभाग स्थायी नौकरी देने की जगह लोगों से ठेके पर काम कराते हैं. इनमें टीचर, चपरासी, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, मजदूर और ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जिनकी नौकरी परमानेंट नहीं है. केजरीवाल ने वादा किया था कि सरकार बनाते ही वह दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करेंगे. सरकार बनने के बाद उन्होंने ऐसे लोगों की नौकरी स्थायी नहीं की. लोग धरना–प्रदर्शन करने लगे. केजरीवाल ने मामला टालने के लिए एक कमेटी बना दी और धरना–प्रदर्शन ख़त्म न करने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी. ऐसे लोग आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं. दरअसल, अरविंद केजरीवाल अपने ख़िलाफ़ किसी विरोध को झेल नहीं सकते. उन्हें लगता है कि वह जो करते हैं, वही सही है, बाकी सब गलत है. लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी है, जिस पर आम आदमी पार्टी भागती फिरती नज़र आती है. यह मामला अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का है. वैसे तो मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षाकर्मी होना ही चाहिए, लेकिन अरविंद ने इसे मीडिया में छाए रहने का एक मुद्दा बना दिया. सरकार बनने से पहले उन्होंने कहा कि वह सुरक्षा नहीं लेंगे. उन्हें किसी चीज का भय नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके साथ हमेशा सुरक्षाकर्मी चलते हैं. सिविल ड्रेस में या फिर कभी–कभी टोपी लगाकर भी नज़र आए हैं.

अब जरा समझते हैं किस तरह से केजरीवाल ने बिजली और पानी के मुद्दे पर लोगों को झांसा दिया. चुनाव से पहले उन्होंने बिजली के बिल को लेकर आंदोलन किया था और लोगों से अपील की थी कि वे बिजली का बिल न भरें. कई लोगों ने बिल का भुगतान नहीं किया. बिजली कंपनियों से ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया, जुर्माना लगाया गया. चुनाव से पहले केजरीवाल ने यह वादा किया कि ऐसे सभी लोगों का बिल माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसे लोगों को न तो माफी मिली और न ही बिल में कोई छूट दी गई. ये लोग अब अपना माथा पीट रहे हैं. पानी की छूट पर चुनाव से पहले जो वादा किया, उसे लागू नहीं किया. मुफ्त पानी देने में केजरीवाल ने एक शर्त लगा दी. मुफ्त पानी सिर्फ़ उन चंद परिवारों को मिल रहा है, जिनके घरों में मीटर लगा है. ज़्यादातर लोगों के घरों में मीटर नहीं है, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा. लेकिन टीवी में छाने की रणनीति में अरविंद ने उन लोगों को भुला दिया, जिनके इलाके में पाइप लाइन तक नहीं है. ऐसा ही हाल बिजली बिल में माफी का है. दिल्लीवासियों के पास अब बिल आने लगे हैं और वादे के मुताबिक बिल में 50 फ़ीसद की छूट नहीं मिल रही है. देश की जनता को अरविंद केजरीवाल की कथनी–करनी में फर्क का प्रमाण तब मिला, जब वह गणतंत्र दिवस के दो दिन पहले तक धरना दे रहे थे और गणतंत्र दिवस परेड को दिखावा बता रहे थे. उन्होंने कहा था कि वह आम जनता के बीच बैठकर परेड को देखेंगे, लेकिन जब टीवी पर वह यूपीए मिनिस्टर्स के बीच वीवीआईपी गैलरी में नज़र आए, तो उनकी असलियत सामने आ गई. वह बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं.

अरविंद केजरीवाल आम आदमी के नाम पर आम आदमी के साथ छलावा कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक वैसे ही, जैसे उन्होंने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया. उनकी राजनीति वर्तमान व्यवस्था से नाराज लोगों को भड़काने की राजनीति है. अरविंद केजरीवाल की राजनीति भावनाओं की राजनीति है, प्रजातांत्रिक संस्थानों को अविश्वसनीय बनाने वाली राजनीति है, प्रजातंत्र को कमजोर करने वाली राजनीति है, अराजकता फैलाने वाली राजनीति है. आम आदमी पार्टी की राजनीति व्यक्तिवादी है. यह सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल की जय–जयकार की राजनीति है. यह विचारहीन राजनीति है. समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में कई कमियां ज़रूर हैं, जिन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए एक रोडमैप होना चाहिए. प्रजातंत्र को जीवित रखते हुए हमें यह बदलाव लाना होगा. इसके लिए लोगों को संघर्ष करना होगा. यह काम किसी आत्मकामी व्यक्ति के वश की बात नहीं है, जो सफेद झूठ एवं आधारहीन आरोपों को राजनीति का माध्यम बनाता है और जनता को ठग कर वोट लेने को ही राजनीति समझता है. आम आदमी पार्टी की राजनीति दिन–रात झूठ बोलकर हंगामा खड़ा करने और टीवी चैनलों पर चेहरा चमकाने की राजनीति है. अगर यही नई राजनीति की परिभाषा है, तो ऐसी नई राजनीति को अविलंब इतिहास बना देना चाहिए.■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 50
दिल्ली, 17 फरवरी –23 फरवरी 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060
+91–8451050786
+91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से प्रभावित होकर अजय ने अपनी किताब की एक प्रति केजरीवाल को 12 मार्च, 2012 को भेजी थी. नवंबर, 2012 में उन्हें पता चला कि स्वराज शीर्षक से अरविंद केजरीवाल की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है. दोनों किताबों को पढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि केजरीवाल की स्वराज उनकी किताब भारतीय राजव्यवस्था से नकल करके लिखी गई है. अजय बताते हैं कि स्वराज में उनकी किताब का क़रीब 70 प्रतिशत अंश प्रयोग किया गया है.

पुस्तक-स्वराज पर विवाद

अरविंद केजरीवाल ने किताब की चोरी की है?

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नित्य नए आरोपों का सामना करना पड़ रहा है. अब तक विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहे केजरीवाल इस बार ग्रेटर नोएडा के एक शिक्षक के निशाने पर हैं. उक्त शिक्षक का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी पुस्तक-भारतीय राजव्यवस्था की अक्षरशः नकल करते हुए अपनी किताब-स्वराज लिखी. हालांकि, इस मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वयं कोई बयान नहीं दिया है. क्या है इस मामले की हक़ीक़त, जानने के लिए पढ़ें चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट...

अभिषेक रंजन सिंह

ग्रेटर नोएडा स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अजयपाल नागर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साहित्य चोरी का सनसनीखेज़ आरोप लगाया है. अजय का कहना है कि उनकी पुस्तक–भारतीय राजव्यवस्था की नकल केजरीवाल ने अपनी पुस्तक–स्वराज में की है. इस बाबत जानकारी मिलने और दोनों क़िताबों का समग्र अध्ययन करने के बाद तथा अपने साथ हुए इस विश्वासघात से दुःखी होकर उन्होंने 15 दिसंबर, 2012 को गौतमबुद्ध नगर स्थित बादलपुर थाने में इसकी लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट होने पर अजयपाल नागर ने न्यायालय सिविल जज, गौतमबुद्ध नगर में दिसंबर, 2012 में एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत अरविंद केजरीवाल, सोनू, कपिल बजाज, बीडी शर्मा, एससी बेहर, संतोष कोली, अन्नपूर्णा मिश्र, संतोष कुमार एवं हरिशंकर कश्यप के विरुद्ध देकर 496, 407, 408, 120 बी, 420, 463, 464 और 467 आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की. 4 जनवरी, 2013 को न्यायालय सिविल जज, गौतमबुद्ध नगर के समक्ष उक्त प्रार्थनापत्र को प्रस्तुत किया गया. उसके बाद न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गौतमबुद्ध नगर ने इस बाबत दलील सुनी और 23 मार्च, 2013 को परिवाद दर्ज़ करने का आदेश पारित किया. उक्त आदेश इस प्रकार है:–

आदेश

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर

प्रार्थना पत्र संख्या–64/13
परिवाद संख्या–3023/13
अजय पाल नागर
बनाम
अरविंद केजरीवाल व अन्य

पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई. विगत नियत दिनांक को परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है. प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रार्थी अजयपाल नागर, पुत्र–स्व. वीर नारायण नागर, निवासी–ग्राम बम्बावड, थाना–बादलपुर, ज़िला–गौतमबुद्ध नगर की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. विपक्षीगण अरविंद केजरीवाल, पुत्र–नामालूम व अन्य के विरुद्ध धारा 156(3) दं.प्र.सं. इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा भारतीय राजव्यवस्था शीर्षक से एक पुस्तक की रचना की गई थी. प्रार्थी द्वारा उक्त पुस्तक दिनांक 20.3.2012 को साहित्य अकादमी, दिल्ली को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी व 26.3.2012 को पुस्तक की एक प्रति विपक्षी अरविंद केजरीवाल को ए–119, कौशांबी, गाज़ियाबाद के पते पर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट डाक से भेजी थी. परंतु विपक्षी ने अपनी एक पुस्तक स्वराज शीर्षक से प्रकाशित की है, जिसमें विपक्षी द्वारा प्रार्थी की पुस्तक भारतीय राजव्यवस्था के अंश को बेईमानी पूर्वक संपूर्ण तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर परिवर्तित कर रचित कर दिया है.

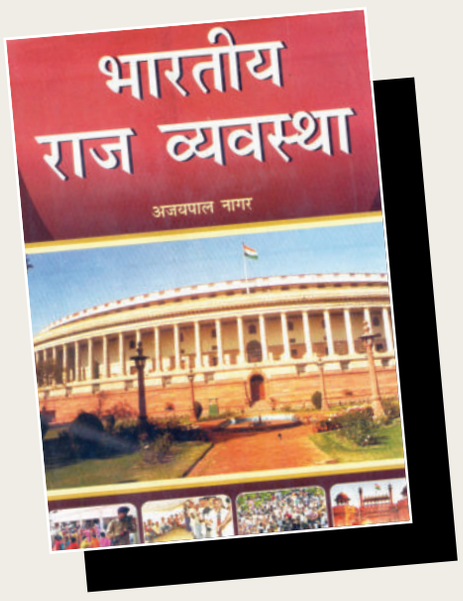

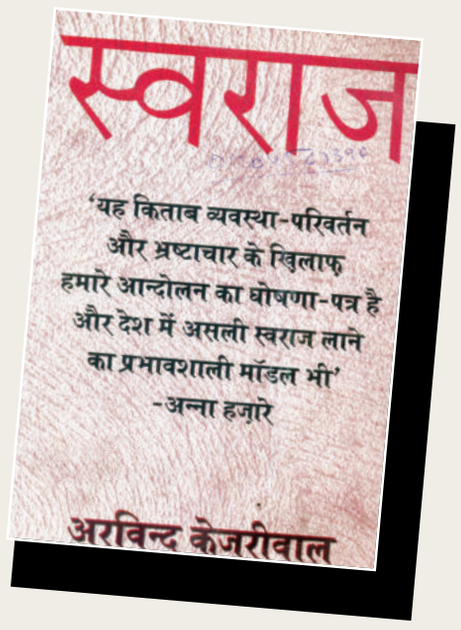

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में भारतीय राजव्यवस्था व स्वराज दोनों पुस्तकों में मेल खाती हुई लाइनों का उल्लेखन भी किया है. प्रार्थी द्वारा अपनी पुस्तक भारतीय राजव्यवस्था व स्वराज पुस्तक की छायाप्रति भी अपने तथ्यों के समर्थन हेतु प्रस्तुत की है. उपरोक्त से विदित है कि प्रार्थी के अभिकथनानुसार, विपक्षीगण द्वारा कॉपीराइट एक्ट अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया गया है.

परिवादी के गवाहान व अभियुक्त के संबंध में भी पूरा ब्यौरा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत कर दिया है. जिस कारण अध्याय 15 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है. जैसा कि मत सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2007 (59) ए.सी.सी 739 व मोना पवार बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ज़रिए महानिबंधक (2011) 1 एस.सी.सी (क्रि.) 1181 में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है. प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) द.प्र.सं परिवाद के रूप में दर्ज़ किए जाने योग्य है.

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है. पत्रावली वास्ते परीक्षण अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं हेतु दिनांक 18.4.2013 को पेश हो.
–सीजेएम
गौतमबुद्ध नगर
23.3.2013

ग़ौरतलब है कि शिक्षक अजयपाल नागर मूलतः बम्बावड गांव के रहने वाले हैं. यह गांव ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी तहसील के अंतर्गत आता है. चौथी दुनिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी किताब भारतीय राजव्यवस्था (नेहा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रकाशित) अरविंद केजरीवाल की किताब स्वराज (हार्पर कॉलिंस प्रकाशन से प्रकाशित) से काफी पहले छप गई थी. अजयपाल नागर की किताब भारतीय राजव्यवस्था में कुल 305 पृष्ठ हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल की पुस्तक स्वराज में कुल 175 पृष्ठ हैं. स्वराज की भूमिका समाजसेवी अन्ना हज़ारे ने लिखी है. इसका लोकार्पण 29, जुलाई 2012 को अन्ना हज़ारे ने जंतर–मंतर पर किया था.

अजय के अनुसार, उन्होंने क़रीब दस वर्षों की कड़ी मेहनत और स्वयं के अनुभवों पर यह पुस्तक लिखी थी. अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी किताब की एक प्रति केजरीवाल को 12 मार्च, 2012 को भेजी थी. नवंबर, 2012 में उन्हें पता चला कि स्वराज शीर्षक से अरविंद केजरीवाल की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है. दोनों किताबों को पढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि केजरीवाल की स्वराज उनकी किताब भारतीय राजव्यवस्था से नकल करके लिखी गई है. अजय बताते हैं कि स्वराज में उनकी किताब का क़रीब 70 प्रतिशत अंश प्रयोग किया गया है.

हालांकि, इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता एवं प्रवक्ता मनीष सिसोदिया का बयान 17 दिसंबर, 2012 को एक दैनिक अख़बार में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, ***हमने कभी नहीं कहा कि स्वराज हमारा आइडिया है. ऐसे में कॉपीराइट का सवाल नहीं उठता. स्वराज भारतीय शासन प्रणाली थी. हमने उसे अपने शब्दों में लिखा है और कभी नहीं कहा कि यह हमारा आइडिया है. हो सकता है कि अजय पाल ने भी अपने शब्दों में उसे लिखा हो.*** हालांकि, अजय पाल नागर उनकी इस दलील से सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि जब स्वराज उनका आइडिया नहीं है, तो स्वराज पुस्तक अरविंद केजरीवाल के नाम से कॉपीराइट क्यों है?

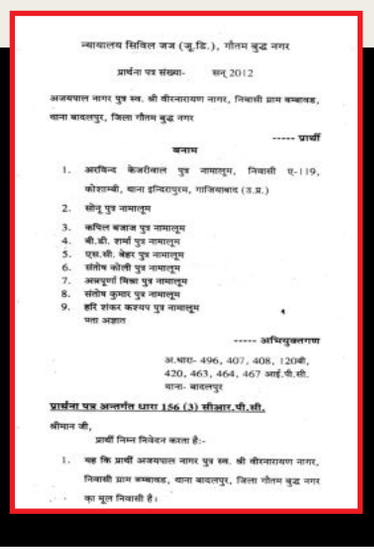

हमने कभी नहीं कहा कि स्वराज हमारा आइडिया है. ऐसे में कॉपीराइट का सवाल नहीं उठता. स्वराज भारतीय शासन प्रणाली थी. हमने उसे अपने शब्दों में लिखा है और कभी नहीं कहा कि यह हमारा आइडिया है. हो सकता है कि अजय पाल ने भी अपने शब्दों में उसे लिखा हो.
मनीष सिसोदिया
नेता, आम आदमी पार्टी

जब स्वराज उनका आइडिया नहीं है, तो स्वराज पुस्तक अरविंद केजरीवाल के नाम से कॉपीराइट क्यों है? मुझे देश की न्यायपालिका पर पूरा यकीन है और हम न्याय पाने तक यह लड़ाई लड़ते रहेंगे.
अजय पाल नागर
केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले शिक्षक

उल्लेखनीय है कि इस बाबत न्यायालय में फ़रियाद करने से पहले शिक्षक अजयपाल नागर ने अरविंद केजरीवाल समेत उनके नौ सहयोगियों के ख़िलाफ़ थाना बादलपुर में 15 दिसंबर, 2012 को एक तहरीर दी थी. उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर, पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ और पुलिस उप महानिदेशक (क़ानून एवं व्यवस्था), लखनऊ को भी एक शिकायती पत्र रजिस्टर्ड डाक से आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा. इतना ही नहीं, इस मामले में अजयपाल नागर ने समाजसेवी अन्ना हज़ारे को एक दिसंबर और 27 दिसंबर, 2012 को दो पत्र भी लिखे. उन्होंने ये पत्र भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास, रालेगण सिद्धि, ताल्लुका–पारेनर, ज़िला–अहमद नगर के पते पर भेजा. अन्ना को लिखे एक दिसंबर, 2012 के पत्र में अजय ने लिखा:–

देश के दूसरे गांधी श्री अन्ना हज़ारे जी, मैं आपका प्रशंसक हूं. दिल्ली में आपके समस्त आंदोलनों में शामिल हुआ हूं. मैं आपकी ईमानदारी, संघर्षशीलता व बेदाग़ छवि का आदर करता हूं. आपके व्यक्तित्व का प्रशंसक हूं.

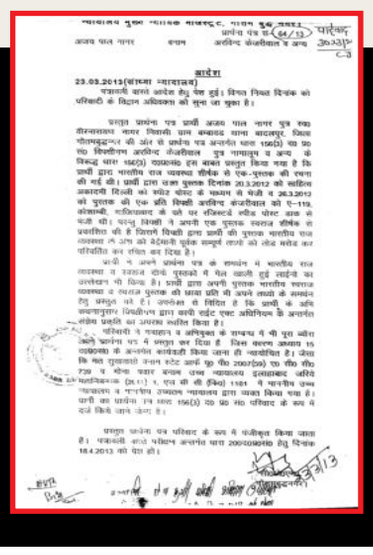

मैंने आपकी छवि को देखते हुए आपके सहयोगी श्री अरविंद केजरीवाल जी को स्वलिखित पुस्तक भारतीय राजव्यवस्था रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्री अरविंद केजरीवाल, ए– 119, कौशांबी, गाज़ियाबाद के पते पर 26 मार्च, 2012 को इस आशय के साथ भेजा था कि वे आपके सहयोगी हैं और इस पुस्तक में देश की वर्तमान व्यवस्था का वर्णन है. आप इसका अध्ययन कर देश की व्यवस्था से अच्छी तरह परिचित हो जाएं, लेकिन आदरणीय केजरीवाल साहब ने मुझे वापसी का कोई पत्र नहीं लिखा. उन्होंने मेरी पुस्तक भारतीय राजव्यवस्था को तोड़–मरोड़ कर स्वराज शीर्षक से जुलाई, 2012 में अपने नाम से प्रकाशित करा कर आपके द्वारा विमोचन भी करा दिया, जो मुझ जैसे आम आदमी के साथ किया गया विश्वासघात और छल है.

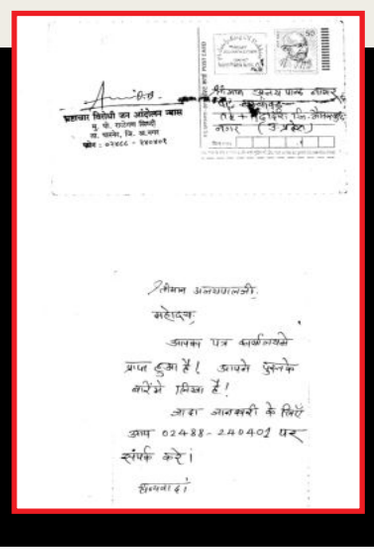

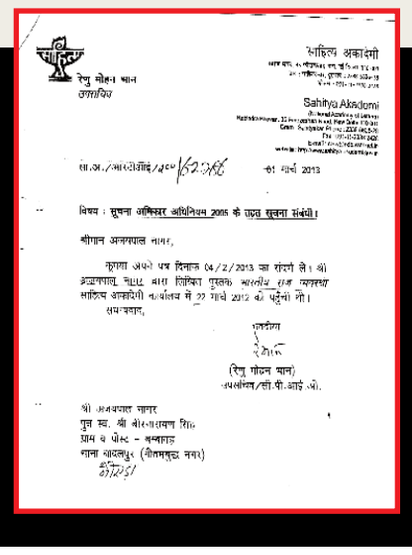

पूज्यनीय श्रद्धेय जी, इस आशा के साथ यह पत्र लिख रहा हूं कि आप मेरी पुस्तक पढ़कर, भेजी गई डाक रसीद देखकर व स्वराज से उसकी तुलना करके स्वयं निर्णय लेंगे और मुझे न्याय दिलाने में मदद करेंगे.
प्रार्थी
अजयपाल नागर
ग्राम व पो. बम्बावड
तहसील–दादरी
ज़िला–ग़ौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)

अजय पाल नागर को इस पत्र के आशय में एक मार्च, 2013 को अन्ना हज़ारे के रालेगण सिद्धि स्थित कार्यालय से अशोक गौतम का ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि ***आपने जो ख़ुलासा किया है, वह बेहद संवेदनशील और गोपनीय है. इसकी जानकारी अन्ना जी को दी जाएगी.***

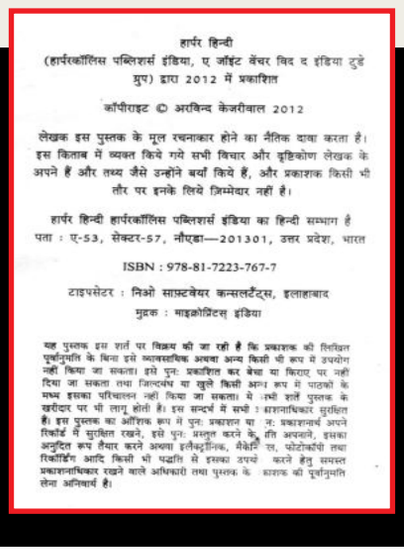

ग़ौरतलब है कि अजय पाल नागर की भारतीय राजव्यवस्था नामक पुस्तक फरवरी, 2012 में प्रकाशित हुई थी. 20 मार्च, 2012 को उन्होंने अपनी पुस्तक की एक प्रति साहित्य अकादमी, दिल्ली और 26 मार्च, 2012 को स्पीड पोस्ट के ज़रिए अरविंद केजरीवाल को भेजी थी. अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर अजय ने 3 जनवरी, 2014 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक ख़त भी लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिला. उससे ठीक दो दिन पहले यानी एक जनवरी, 2014 को अजय ने भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने न्याय में हो रही देरी के बारे में अपनी पीड़ा प्रकट की. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साहित्य चोरी का संगीन आरोप लगाने वाले शिक्षक अजय पाल नागर का कहना है कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा यकीन है. उनके मुताबिक़, वह इस लड़ाई को उस समय से लड़ रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे. ■

arsingh@chauthiduniya.com

आधे घंटे के भाषण में मुलायम का सारा ध्यान मोदी की आलोचना में ही रहा. मुलायम के सिपहसालारों ने भी मोदी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली. कुछ ही घंटों के बाद नरेंद्र मोदी ने मुलायम के हमले का सिलसिलेवार जवाब दे दिया. तभी से ऐसा लग रहा था कि मोदी-मुलायम काफी चतुराई के साथ अपनी गोटें आगे बढ़ा रहे हैं. मेरठ की तरह गोरखपुर की शंखनाद रैली में भी मोदी के निशाने पर परंपरागत रूप से राहुल गांधी की जगह मुलायम सिंह यादव ही रहे.

उत्तर प्रदेश

सांप्रदायिकता और तुष्टिकरण की सियासत

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की राजनीति को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बड़ी चतुराई के साथ दो दलों के बीच समेट लेना चाहते हैं. दोनों ही दलों के नेता एक-दूसरे पर हमला बोलकर बसपा-कांग्रेस को हाशिये पर ढकेल देने की जिस राजनीति को हवा दे रहे हैं, वह कांग्रेस के अघोषित पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी और बसपा प्रमुख मायावती के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी चालाकी के साथ वोटों का ध्रुवीकरण करते जा रहे हैं. मोदी की नज़र हिंदू वोटों पर है, तो मुलायम मुसलमान वोटरों पर डोरे डाल रहे हैं. मुलायम भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो मोदी की नज़रों में मुलायम की राजनीति तुष्टिकरण से पूर्ण और आम जन के बीच भेदभाव वाली है.

दोनों ही दलों के नेता अपनी-अपनी जनसभाओं में एक-दूसरे को कोसते-काटते रहते हैं. जुबानी जंग में सामान्य शिष्टाचार को तिलांजलि दे दी गई है. शुरू-शुरू में मोदी के निशाने पर राहुल गांधी और मनमोहन की यूपीए सरकार हुआ करती थी, उनके अधिकांश भाषण उन्हीं के बीच सिमटे रहते थे. मुलायम कांग्रेस के साथ खड़े होकर भी कांग्रेस को ही कोसते थे. मुलायम के निशाने पर मोदी भी रहते थे, लेकिन वह उनका नाम अपनी जुबान से लेने में परहेज करते थे, ताकि उन्हें बेवजह महत्व न मिले. लेकिन पिछली दो-तीन रैलियों से दोनों दलों के नेताओं ने अपनी सियासत में बदलाव कर लिया है. मुलायम और मोदी खुलकर एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. कोशिश वोटों के ध्रुवीकरण की है. बीती 2 फरवरी को मेरठ में भाजपा की शंखनाद रैली के दौरान नरेंद्र मोदी मुलायम और अखिलेश को लेकर कुछ ज़्यादा उग्र दिखे. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जहर की खेती वाले बयान पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ही विभिन्न समुदायों को लड़ाकर जहर के बीज बोने और फसल काटने का काम करती है. इसके बाद उनका रुख सपा की तरफ़ मुड़ गया. उन्होंने सपा को समाज विरोधी पार्टी करार दे दिया और आरोप लगाया कि यूपी में गुंडों को सरकारी संरक्षण हासिल है, महिलाएं घरों से बाहर निकलने में डरती हैं. मोदी ने मुलायम और अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा कि रैलियों के मामले में होड़ करने के बजाय वे विकास की राजनीति में उनका मुकाबला करें, कानून व्यवस्था में करें, किसानों की भलाई में करें, गांवों की बिजली और विकास में करें. मोदी ने कहा कि यहां इंसान कैसे जीता है, भगवान ही जाने.

मोदी की कड़वी बातें सपा नेताओं को रास नहीं आईं. सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मोदी झूठ की खेती करते हैं. पीएम बनने का उनका सपना मुंगेरी लाल जैसा है. बात यही नहीं थमी, सपा प्रमुख ने भी घोषणा कर दी कि वह इसका जवाब 3 फरवरी को गोंडा की रैली में देंगे. गोंडा में देश बचाओ-देश बनाओ रैली में मुलायम सिंह यादव ने आरोप लगाया कि मोदी को नफरत फैलाने के सिवा कुछ नहीं आता. पहले मोदी अपनी रैलियों का मुकाबला सपा की रैलियों से कर रहे थे, जब भीड़ में मात खा गए, तो विकास का तोता रटत मंत्र जपने लगे. मुलायम ने एक-एक करके अखिलेश सरकार की खूबियां गिनाईं. साथ ही गुजरात दंगों पर मोदी को खुली बहस की चुनौती भी दी. मुलायम ने पूछा, मोदी जी बताएं, क्या उनके गुजरात में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवाई की व्यवस्था है? किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त सिंचाई, वृद्धावस्था पेंशन जैसी सुविधाएं क्या गुजरात में हैं? मुजफ्फरनगर में पीड़ितों को तत्काल मदद दी गई. क्या इसके पहले कांग्रेस सरकार या गुजरात सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा दिया? उनके आश्रितों को नौकरी दी? जैसा उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने किया? मुलायम से पहले सूबे के मुख्यमंत्री एवं सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों पर मोदी के बयान की धज्जियां उड़ाते हुए बताया कि प्रदेश के 3-4 शहरों जितनी कुल चीनी मिलें गुजरात में हैं. उनका गन्ना साल भर में पैदा होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 6 माह में हो जाता है. बसपा राज में चीनी मिलें बेची गईं, जबकि सपा के समय दो दर्जन नई चीनी मिलें लगी थीं, तब चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ था. अखिलेश यादव यह बताने से नहीं चूके कि पीएम का रास्ता यूपी तय करता है.

ग़ौरतलब है कि इससे पहले वाराणसी में मुलायम ने मोदी के हाथ खून से सने होने की बात कहते हुए आरोप लगाया था कि मोदी ने गुजरात में क्या किया, यह सब जानते हैं. उन्होंने वहां कत्लेआम कराया और महिलाओं की आबरू लुटवाई. हम यूपी को गुजरात नहीं बनने देंने. आधे घंटे के भाषण में मुलायम का सारा ध्यान मोदी की आलोचना में ही रहा. मुलायम के सिपहसालारों ने भी मोदी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली. कुछ ही घंटों के बाद नरेंद्र मोदी ने मुलायम के हमले का सिलसिलेवार जवाब दे दिया. तभी से ऐसा लग रहा था कि मोदी-मुलायम काफी चतुराई के साथ अपनी गोटें आगे बढ़ा रहे हैं. मेरठ की तरह गोरखपुर की शंखनाद रैली में भी मोदी के निशाने पर परंपरागत रूप से राहुल गांधी की जगह मुलायम सिंह यादव ही रहे. मोदी ने तब भी मुलायम को मुजफ्फरनगर दंगों के लिए कठघरे में तो नहीं खड़ा किया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि गुजरात में पिछले दस वर्षों से शांति है. यही बात मेरठ में भी मोदी ने दोहराई और कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी, तो यूपी को दंगामुक्त बना दिया जाएगा. मुलायम के वाराणसी में दिए गए बयान-यूपी को गुजरात नहीं बनने देंगें पर तिलमिलाए मोदी ने गोरखपुर में उसका कड़ा प्रतिकार करते हुए कहा कि यूपी को गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए. गुजरात का मतलब 24 घंटे बिजली और दस प्रतिशत विकास दर है. महिलाओं को सुरक्षा देनी होती है. कानपुर, आगरा, झांसी, काशी, बहराइच, बुंदेलखंड, गोरखपुर के बाद मेरठ में मोदी की सातवीं रैली कई मायनों में अलग रही. यहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बहाने राजनीति की धारा बदलने की कोशिश की.

बहरहाल, शुरुआती दौर में कांग्रेस पर हमलावर रहने वाले मोदी ने गोरखपुर में जब पहली बार जोरदार तरीके से सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और सूबे की सरकार को कठघरे में खड़ा करने में ज़्यादा समय बिताया, तभी से ऐसा लग रहा था कि जैसे मोदी और मुलायम, दोनों ही मान बैठे हैं कि यूपी में कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है. मोदी यूपी के स्थानीय मुद्दों और दलितों, शोषितों, वंचितों एवं पिछड़ों की बात करके साफ़ संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति को वह दूसरे तरीके से हैंडिल करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

नीडो हत्याकांड

आख़िर हम जाएं तो कहां जाएं

देश में समय-समय पर पूर्वोत्तर के लोगों के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार होता आया है, उससे वे खुद को शेष भारत से कटा हुआ महसूस करते हैं. अरुणाचल प्रदेश निवासी छात्र नीडो की मौत इसका ताजा प्रमाण है कि अपने ही देश में पूर्वोत्तर के लोग किस कदर बेगाने और असुरक्षित हैं.

एस बिजेन सिंह

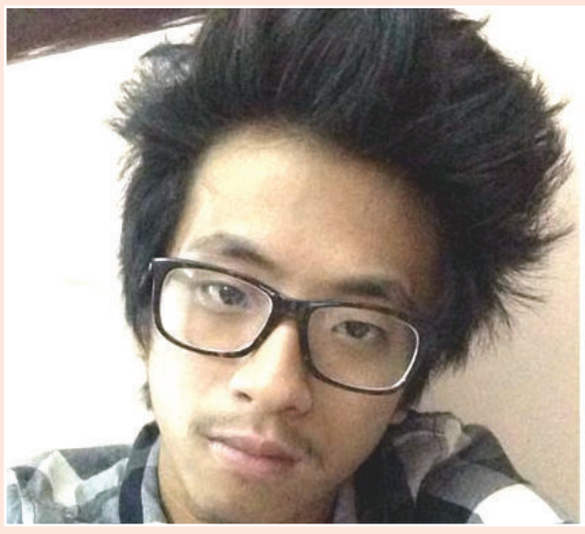

हाल ही में दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के एक छात्र की जिस तरह से पीट-पीटकर नृशंस हत्या कर दी गई, वह पूर्वोत्तर के साथ हो रही नाइंसाफी की पोल खोलने के लिए काफी है. अगर राजधानी या उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में पूर्वोत्तर के लोगों, खासकर छात्र-छात्राओं से भेदभाव का अपना लंबा इतिहास नहीं होता, तो यह घटना साधारण अपराध मानी जाती. नीडो ताबयो अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला था. उम्र महज 19 साल. ऊंची अट्टालिकाओं के शहर दिल्ली में नीडो अंजान था. किसी के घर जाना था. उसने लाजपत नगर में एक पनीर की दुकान पर पता पूछा. उसका रंग-रूप देखकर पनीर वाले दुकानदार ने नीडो का मजाक उड़ाया. नीडो और दुकानदार के बीच बात जब हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, तो नीडो ने दुकान के शीशे तोड़ दिए. दुकान वालों ने उसकी पिटाई की. मामला पुलिस थाने पहुंचा. नीडो ने कांच तोड़ने के एवज में 10,000 रुपये भी दिए. आरोप यह भी है कि थाने से वापस आने पर रास्ते में दोबारा उसकी पिटाई की गई. इसके बाद नीडो वापस अपने कमरे पर लौट गया और सो गया. ऐसा सोया कि हमेशा-हमेशा के लिए सो गया. नीडो की मौत मानवता के समक्ष एक सवाल है, जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता.

समय रहते अगर पुलिस और प्रशासन ने क़दम उठाए होते, तो नीडो आज जीवित होता, लेकिन हमेशा की तरह प्रशासन ने अकर्मण्यता का परिचय दिया, जो नीडो की मौत का कारण बना. नीडो की मौत के बाद पूर्वोत्तर के छात्र-छात्राएं आंदोलन पर उतर आए, क्योंकि उनका मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी में उनके साथ न्यायपूर्ण और समानता का व्यवहार नहीं होता है. क्या एक संप्रभु राष्ट्र के लिए यह शोभनीय है? पूर्वोत्तर का हो या देश के किसी अन्य हिस्से का, है तो वह इंसान ही. ऐसे में मारपीट या झगड़े में किसी की जान चली जाए, तो कोई देश खुद को सभ्य कैसे कह सकता है? किसी देश की राजधानी में इस तरह की घटना का होना शर्मनाक और दु:खद है. दिल्ली किसी की जागीर नहीं है. यहां देश के विभिन्न हिस्सों के लोग आकर रहते हैं. यह मल्टी-कल्चर सिटी है. यहां हर कल्चर को स्पेस दिया जाता है. ऐसे में दूसरों के रूप-रंग, हाव-भाव, भाषा, रहन-सहन, मान्यताओं और आस्थाओं के प्रति सम्मान बरतना चाहिए. किसी खास वर्ग को निशाना बनाकर भद्दे मजाक और टिप्पणियां नहीं करने चाहिए. किसी ने अपने बालों का रंग पीला किया हो, नीला या फिर लाल, किसी ने अपनी मूंछें कटा ली हों या दाढ़ी बढ़ाई हो, किसी ने अपने कान में ईयर रिंग पहना हो या कुछ और, किसी को क्या फर्क पड़ता है? हम औरों पर क्यों टिप्पणी करेंगे?

इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि पूर्वोत्तर के छात्र-छात्राओं के प्रति उत्तर भारत में एक खास तरह का पूर्वाग्रह है. पूर्वोत्तर के लोगों को चिंकी कहा जाता है और इन राज्यों से आई लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं आएदिन होती रहती हैं, लेकिन आज तक उनकी सुरक्षा के लिए सरकार या प्रशासन की तरफ़ से कुछ नहीं किया गया. जब कोई घटना घटती है, उस समय सरकार खुद को काफी गंभीर दिखाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है. ये है पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति उदासीनता का आलम. आप अक्सर पूरी दिल्ली में पोस्टर पर लिखा हुआ पाएंगे और लोगों से या टीवी चैनलों पर भी सुनेंगे या देखेंगे कि दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन सच्चाई कुछ और है. विदेशों और अपने देश में भी दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है. क्या दिल्लीवासियों को नहीं लगता कि इस कलंक को धोना चाहिए? अगर लगता है तो अपने से भिन्न रूप-रंग वालों से कैसे व्यवहार किया जाए, उनके साथ सामाजिक संबंध कैसे कायम किया जाए, उन्हें दिल्ली के सांस्कृतिक जीवन की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, यह दिल्ली वालों को सीखना होगा. अन्यथा दिल्ली को मेरी दिल्ली, प्यारी दिल्ली के नारे से नहीं, बल्कि वहशी दिल्ली के नारे से नवाजा जाएगा.

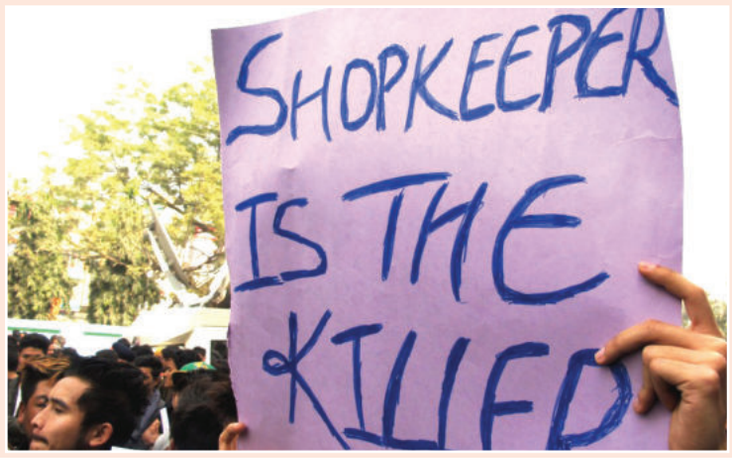

दरअसल, मैं मूल रूप से पूर्वोत्तर यानी मणिपुर का निवासी हूं. मैं पिछले 10 सालों से बिहार, झारखंड, पंजाब एवं दिल्ली में रह रहा हूं. इतने सालों में आज तक मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं हुई. मेरे कई दोस्त उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब से हैं. कुछ बातों पर मैं उनसे असहमति ज़रूर व्यक्त करता हूं और वे भी मुझे कई मुद्दों पर टोकते हैं, मगर आज तक कभी उन्होंने मुझ पर तंज नहीं कसे, न मैं उन पर कसता हूं. मैं दोस्तों से अपनी बात शेयर करता हूं. उनके दु:ख-दर्द का हिस्सा बनता हूं और वे भी मेरे दु:ख-सुख में भागीदार बनते हैं. इरोम शर्मिला के कैंपेन में जितना पूर्वोत्तर के लोगों का समर्थन है, उससे कहीं ज्यादा हिंदीभाषी राज्यों के लोगों का.

जैसे देश के अन्य हिस्से के लोग अपने समूह में रहते हैं, वैसे ही पूर्वोत्तर के छात्र-छात्राएं अपने समूह में रहते हैं. हालांकि पूर्वोत्तर के लोगों को चाहिए कि वे अपने आसपास के लोगों से घुलें-मिलें, बातें करें, ताकि लोग उनकी सभ्यता-संस्कृति को जानें-समझें और उन्हें भी अपने बीच का मानें. समाज से कटकर रहना हमेशा दूसरों के मन में जिज्ञासा जगाता है, जो अपराध को बढ़ावा देता है. अगर हम एक-दूसरे को नहीं समझेंगे, एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, एक-दूसरे की सभ्यता-संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे, तो याद रखिए, आने वाले दिनों में नीडो जैसे और भी मामले हमारे सामने से गुजरते रहेंगे. ■

sbijensngh@gmail.com

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भले ही इस बात की चिंता करते हों कि सब्सिडी इसलिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि अधिभार बढ़ेगा, लेकिन राहुल गांधी अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए प्रधानमंत्री की इस चिंता को धता बता रहे हैं. तक़रीबन दो महीने पहले पार्टी और राहुल गांधी की इमेज संवारने के लिए जापान की पीआर एजेंसी डेंट्सू की इंडिया इकाई को 500 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया. एजेंसी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राहुल गांधी की दमदार मौजूदगी पर काम कर रही है.

देश के नेताओं से सीखिए पेड़ पर पैसा उगाने की कला

नीरज सिंह

पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने 9 से बढ़ाकर 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी देने की घोषणा की, तो आर्थिक विश्लेषकों ने आम राय से यह व्याख्या की कि जब दो साल पहले यही निर्णय वापस लिया गया था, तब भी ऐसी ही आर्थिक परिस्थितियां देश के सामने थीं या इससे कमतर ही थीं, तब वही निर्णय आज दोहराया क्यों गया. उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि पेट्रोलियम पदार्थों पर अगर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, तो अधिभार बढ़ेगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा. पैसा पेड़ पर नहीं उगता. लेकिन, अगर देश के आर्थिक माहौल को देखें, तो आपके आसपास ही ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे, जब यह मानने की कोई वजह रह नहीं जाती कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते.

हाल ही में आरटीआई के तहत एक जानकारी मिली कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के वकील सरकार की तरफ़ से मुकदमों की पैरवी के नाम पर पैसे बना रहे हैं. यह क्रम बदस्तूर हर सरकारों में जारी है, फिर चाहे वह सपा हो या बसपा. बसपा नेता एवं अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्र और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एवं अधिवक्ता गौरव भाटिया का नाम इस प्रकरण में सबसे ऊपर है.

आरटीआई के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निचली अदालत, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में पेश होने वाले वकीलों के शुल्क ढांचे, चयन प्रक्रिया और मापदंड आदि की जानकारी मांगी गई थी. उत्तर प्रदेश न्याय विभाग के विशेष सचिव डॉ. अजय कृष्णविश्वेश ने इस प्रतिवेदन में जो जवाब दिया, उसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सतीश चंद्र मिश्र 2009–10 से 2011–12 तक राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान मिश्र ने अपनी फीस के रूप में राज्य सरकार से कुल 4,64,20,000 रुपये लिए, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद से गौरव भाटिया भी विभिन्न मुकदमों में पेश होकर आर्थिक लाभ उठा रहे हैं. सपा की विधि इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता वीरेंद्र भाटिया के पुत्र गौरव भाटिया को लगभग डेढ़ साल में सूबे के अपर महाधिवक्ता के तौर पर मुकदमों की पैरवी के लिए 47,69,677 रुपये का भुगतान किया गया है.

यह फेहरिस्त बहुत लंबी है. सुप्रीम कोर्ट के बहुत से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, जिन्होंने शीर्ष न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने के के वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी, हरीश एन साल्वे और गोपाल सुब्रह्मण्यम जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी फीस के रूप में भारी–भरकम रकम अदा की है. उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007–08 से 31 अक्टूबर, 2013 तक सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता के के वेणुगोपाल को 2,40,76,000 रुपये, अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम को 1,47,45,000 रुपये, अधिवक्ता राकेश द्विवेदी को 1,24,29,300 रुपये और अधिवक्ता हरीश एन साल्वे को 63,97,500 रुपये का भुगतान किया है.

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता की बहस की फीस 15 हज़ार रुपये, जबकि कनिष्ठ पैनल अधिवक्ता की फीस पांच हज़ार रुपये प्रति कार्य दिवस है. लेकिन यहां पर जो मौजूं सवाल है कि इतनी फीस लेने के बाद भी अधिकांश अधिवक्ता सरकार की ओर से पैरोकारी में असफल रहते हैं यानी अपने मुकदमे हार जाते हैं. अब सवाल यह है कि क्या सरकार जनता के इन पैसों को अपने वकीलों पर मुकदमे हारने के लिए लुटा रही है? भारत सरकार की तरफ़ से आयकर के समय पर भुगतान के जो विज्ञापन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचाए जाते हैं, उनके लिए सरकार उक्त माध्यमों को करोड़ों रुपये शुल्क के तौर पर चुकाती है. सरकार प्रचार माध्यमों से लोगों को जागरूक करती है कि आप अपना आयकर समय से चुकाएं. देश में अधिकांश लोग आयकर में छूट पाने के लिए पब्लिक क्षेत्र की कंपनी एलआईसी में निवेश करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एलआईसी ही इस देश की सबसे बड़ी इनकम टैक्स डिफॉल्टर कंपनी है. 15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति वाली और देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) 7000 करोड़ रुपये से अधिक के आयकर डिफॉल्ट के आरोपियों की सूची में शीर्ष पर है.

यह जानकारी भी देश को सूचना के अधिकार के तहत ही मिली. आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने जो जानकारी आयकर विभाग से हासिल की है, उसके मुताबिक, आयकर विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने एक सूची जारी की है. एलआईसी 7000 करोड़ रुपये से अधिक के आयकर डिफॉल्ट के साथ इस लिस्ट में पहले पायदान पर है. हालांकि यह आंकड़ा साल 2011 तक का ही है, उसके बाद के आंकड़े अभी नहीं मिल पाए हैं और एलआईसी ऐसे किसी मामले से इंकार भी कर रहा है. एलआईसी के बाद आदित्य बिड़ला टेलीकॉम पर 2,372 करोड़, वोडाफोन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2,038 करोड़, आइडिया सेल्युलर पर 1,517 करोड़ और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर 1,494 करोड़ रुपये बकाया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर भी 167.10 करोड़ रुपये का बकाया है. वहीं संस्थाओं के अलावा इस सूची में कई व्यक्तियों के भी नाम शामिल हैं, जिनमें एक प्रमुख नाम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का भी है. वही सवाल फिर से एक बार खड़ा होता है कि सरकार कहती है कि अगर आप टैक्स नहीं चुकाएंगे, तो वह सुविधाएं कहां से देगी? तो आख़िर सरकार अपने ही संस्थानों से आयकर हासिल करने में फिसड्डी क्यों होती जा रही है? सरकार अपना राग पैसा पेड़ पर नहीं उगता, क्यों भूल जाती है?

वास्तव में पैसा पेड़ पर नहीं उगता की दोबारा शुरुआत राहुल गांधी के ही कारण हुई. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भले ही इस बात की चिंता करते हों कि सब्सिडी इसलिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि अधिभार बढ़ेगा, लेकिन राहुल गांधी अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए प्रधानमंत्री की इस चिंता को धता बता रहे हैं. तक़रीबन दो महीने पहले पार्टी और राहुल गांधी की इमेज संवारने के लिए जापान की पीआर एजेंसी डेंट्सू की इंडिया इकाई को 500 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया. एजेंसी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राहुल गांधी की दमदार मौजूदगी पर काम कर रही है. इसी तैयारी के चलते राहुल गांधी का मीडिया साक्षात्कार भी आयोजित किया गया, लेकिन पीआर एजेंसी तो केवल राहुल के बाहरी व्यक्तित्व को ही निखार सकती है, बेहतर प्रस्तुत कर सकती है. भीतर तो जो वह हैं, उसे केवल राहुल अपने प्रयासों से ही बदल सकते हैं. इसीलिए जब राहुल गांधी ने पहली बार एक अंग्रेजी चैनल को साक्षात्कार दिया और उसके बाद जिस तरह चौतरफ़ा आलोचना झेली, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि राहुल की इमेज बिल्डिंग के नाम पर यह पैसा क्यों बहाया जा रहा है.

अप्रैल–मई में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले जापान की एडवरटाइजिंग एवं पीआर कंपनी डेंट्सू इंडिया कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा कैंपेन भी तैयार कर रही है. लेकिन उस एजेंसी की भी कलई तब खुल गई, जब राहुल के मैं नहीं हम वाले विज्ञापन पर विवाद हो गया. एजेंसी जो कैंपेन आम आदमी के सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट पर तैयार कर रही है और राहुल गांधी को एक एंग्री यंगमैन के रूप में पेश कर रही है, राहुल अपने बयानों से उन सारे प्रयासों पर पानी फेर दे रहे हैं. याद कीजिए, अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी का वह बयान, जिसमें 1984 के दंगों के बारे में पूछे जाने पर वह कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उन दंगों में शामिल नहीं था. जो लोग शामिल थे, उन्हें सजा मिल चुकी है. इसके बाद सिख समुदाय के लोगों ने इस बात को लेकर खासा बवाल किया कि राहुल गांधी स्पष्ट करें कि वे कौन से कांग्रेसी थे, जो 1984 के सिख दंगों में शामिल थे. राहुल की इमेज बनने के बजाय दिनोंदिन बिगड़ती ही जा रही है. जो आगामी लोकसभा चुनाव रागां बनाम नमो के तौर पर देखा जा रहा था, वह अब खिसक कर नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की ओर बढ़ गया है. क्या 500 करोड़ खर्च करके राहुल गांधी अपनी ऐसी ही इमेज बनाना चाहते थे? यह तो उन्हें फ्री में ही हासिल हो जाती. इन पैसों का हिसाब अगर जनता मांगे, तो जाहिर है कि राहुल गांधी उसे यही जवाब देंगे कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता.

अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले जापान की एडवरटाइजिंग एवं पीआर कंपनी डेंट्सू इंडिया कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा कैंपेन भी तैयार कर रही है. लेकिन उस एजेंसी की भी कलई तब खुल गई, जब राहुल के मैं नहीं हम वाले विज्ञापन पर विवाद हो गया. एजेंसी जो कैंपेन आम आदमी के सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट पर तैयार कर रही है और राहुल गांधी को एक एंग्री यंगमैन के रूप में पेश कर रही है, राहुल अपने बयानों से उन सारे प्रयासों पर पानी फेर दे रहे हैं.

लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ गया है, तो कांग्रेस सरकार उन्हीं योजनाओं को नए सिरे से लागू कर रही है, जिनके लिए वह कल तक अधिभार का रोना रो रही थी. मौजूदा समय में कुल जीडीपी का 14 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी पर खर्च किया जा रहा है. सब्सिडी पर खर्च को लेकर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है, लेकिन सवाल इस बात पर ज़रूर है कि आख़िर इस क़दम से जनता के पैसे से जनता को ही तो लुभाया जा रहा है और वह भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए. ग़ौर करिए कि जहां भी सब्सिडी दी जा रही है, वहीं पर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है. अनाज माफिया खाद्यान्नों पर दी जाने वाली सब्सिडी के चलते ही सस्ता अनाज खरीद कर कालाबाज़ारी कर रहे हैं, तो मंजूनाथ और यशंवत सोनावणे जैसे अधिकारी तेल सब्सिडी से उपजे माफियाओं के हाथों मारे जा रहे हैं. एक और सवाल है कि जब सरकारी खजाने की हालत पतली हो, तो राजकोषीय घाटे को बढ़ाने वाले क़दमों के अर्थव्यवस्था पर संभावित असर को लेकर सबको चिंतित होना चाहिए. यूपीए सरकार यही कर रही है. और यह हथियार केवल यूपीए सरकार ही नहीं, राज्य सरकारें भी हथिया रही हैं. दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए जनता का ही पैसा लेकर सब्सिडी के नाम पर बिजली कंपनियों को सौंप रही है. उत्तर प्रदेश में सरकार हर घटना के बाद कंबल और खाद्यान्नों के पैकेट बांटकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी मान लेती है. वास्तव में ऐसे क़दम रोग को कम नहीं करते, बल्कि रोग को बढ़ाते हैं.

इस मुद्दे पर सरकारें सामान्य दिनों में जो कहती हैं, व्यवहार में (खासकर चुनाव क़रीब आने पर) वे खुद उसका उल्लंघन करती हैं. जिस सब्सिडी का लाभ संपन्न तबके हथिया लेते हैं, अक्सर उन्हें भी तर्कसंगत बनाने का साहस वे नहीं दिखातीं. इसकी एक मिसाल डीजल है, जिस पर सरकार अभी भी प्रति लीटर लगभग साढ़े आठ रुपये सब्सिडी दे रही है, जबकि खुद पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक, देश में डीजल की 70 फ़ीसद खपत परिवहन में होती है. डीजल पर दी जा रही कुल 92,061 करोड़ रुपये की सब्सिडी में लगभग 12,100 करोड़ रुपये का लाभ प्राइवेट कारों एवं यूटिलिटी वेहिकल्स के मालिक उठा रहे हैं, जबकि कमर्शियल कारों एवं यूवीज को 8,200 करोड़ और भारी कमर्शियल वाहनों को 26,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का फायदा मिल रहा है. 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी अन्य क्षेत्रों को जाती है, जिनमें जनरेटर और मोबाइल टावर चलाना शामिल है. सरकार कहती है कि डीजल सब्सिडी को कृषि क्षेत्र एवं सार्वजनिक परिवहन के नाम पर खर्च किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है.

जनता के पैसे अपनी जेबों में रखकर सरकार आंखें तरेर रही है कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं. और देश की जनता सिर्फ़ और सिर्फ़ इन राजनीतिक चालबाजियों को देखने–सहने को मजबूर है. वह पैसा जो सपा–बसपा के वकील ले रहे हैं, वह पैसा जो एलआईसी आयकर न जमा करके अपनी जेब में डाल रहा है, वह पैसा जिसके दम पर राहुल गांधी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, वह सब जनता का पैसा है. लेकिन उसके लाभ में जनता कहां है? यह पैसा कभी भी पेड़ पर नहीं उगा, यह देश की जनता की मेहनत का पैसा है और जिस पर कोई और कुंडली मारे बैठा है.

feedback@chauthiduniya.com

लोकसभा चुनाव परिणाम के फायदे और नुकसान का नीतीश को भी पूरा एहसास है, इसलिए वह अपनी सभाओं में दिल्ली के लिए ज़्यादा ताकत देने की अपील बार–बार जनता से कर रहे हैं. अगर दस का आंकड़ा नीतीश पार कर गए, तो आशंकाओं से ठीक उलट उसका पूरा फायदा उन्हें मिलेगा. राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद तो बढ़ेगा ही, साथ ही बिहार में जदयू कार्यकर्ताओं के बीच यह साफ़ संदेश चला जाएगा कि विपरीत से विपरीत हालात होने के बावजूद नीतीश कुमार का करिश्मा बरकरार है, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगा देगा.

ख़तरे में नीतीश सरकार

सरोज सिंह

कोई और यह बात कहता, तो इसे महज अटकल या फिर अफवाह मानकर खारिज कर दिया जाता, लेकिन अगर बिहार सरकार का मुखिया ही यह कहे कि अगर दिल्ली के लिए ताकत नहीं मिली, तो कोई दस दिन भी बिहार में टिकने नहीं देगा, तो इसे क्या माना जाए. लखीसराय की संकल्प रैली में नीतीश कुमार ने जब सार्वजनिक मंच से इस तरह की आशंका का इजहार किया, तो राजनीतिक गलियारे में सनसनी फैल गई. गरमागरम बहस में तर्कों के तीर चलने लगे और कम से कम कोई यह मानने को अब तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार ने यह बात हल्के में की है. आख़िर ऐसी क्या बात हो गई कि नीतीश कुमार को यह बात कहनी पड़ी. इस बात को समझने के लिए बिहार के पिछले तीन–चार महीनों की राजनीति को बारीकी से समझना ज़रूरी है. यह ऐसा दौर रहा, जिसमें नीतीश कुमार के कई अनुमान गलत निकले, कई उम्मीदें टूट गईं और कई चुनावी रणनीतियों को गहरा झटका लगा. इन्हीं कारणों से उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद बिहार सरकार के चले जाने का ख़तरा महसूस हो रहा है. यह सभी जानते हैं कि भाजपा से अलगाव के बाद जदयू की ताकत कमजोर हुई है. नीतीश कुमार इस अलगाव को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि सिद्धांतों के लिए वह कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं.

नीतीश कुमार को लगता था कि भाजपा को त्यागने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनके साथ आ जाएगा, लेकिन भाजपा के जाने के बाद जो नुकसान हो रहा है, उसकी पूरी भरपाई हो जाएगी, यह भरोसा नीतीश कुमार को अब नहीं हो पा रहा है. दूसरी तरफ़ भाजपा बिहार में अपने आप को रोजाना मजबूत कर रही है. पंचायत से लेकर राजधानी तक संगठन मजबूत करने में पूरी पार्टी लगी है. उधर सभी सर्वेक्षणों में भाजपा को मिल रही बढ़त भी जदयू और नीतीश कुमार को परेशान कर रही है. नीतीश कुमार इसलिए बार–बार कह रहे हैं कि इस तरह के चुनावी सर्वेक्षणों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके आंकड़े सच से काफी दूर हैं. नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं कि यह सब भाजपा द्वारा प्रायोजित है और जनता को भ्रमजाल में फंसाने की साजिश है. नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में लालू एवं कांग्रेस विरोध का वोट अगर पूरी तरह भाजपा में चला गया, तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं. इसलिए इधर नीतीश कुमार भाजपा के प्रति काफी आक्रामक हो गए हैं. लगभग अपनी सभी जनसभाओं में वह भाजपा को ज़्यादा कोस रहे हैं. वह कह रहे हैं कि भाजपा के पास लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कमी है. जब साथ थे, तो हमने कई दफा उसे अपने प्रत्याशी दिए.

दरअसल, बिहार की राजनीति की जमीनी सच्चाई अभी यह है कि अगड़ी जातियों का ध्रुवीकरण बड़ी तेजी से भाजपा की ओर हो रहा है. यह वोट पहले भाजपा–जदयू गठबंधन को मिलता था, पर अब तो गठबंधन रहा ही नहीं. इसके अलावा पिछड़ी जातियों के वोटों के लिए भी जदयू एवं भाजपा के बीच जंग छिड़ गई है. भाजपा चिल्ला–चिल्ला कर कह रही है कि अति पिछड़े नरेंद्र मोदी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं. इसलिए आप लोग अपने वोट बर्बाद न करें और एकजुट होकर भाजपा का समर्थन करें. भाजपा की यह बात नीतीश कुमार के खजाने से चोरी जैसी है. अमूमन अति पिछड़ों के वोटों पर पिछले दस सालों से जदयू का दबदबा रहा है. ऐसे में, अब भाजपा की सेंधमारी नीतीश कुमार को खल रही है. भाजपा की बढ़त के अलावा कांग्रेस, लोजपा एवं राजद की संभावित दोस्ती भी नीतीश के लिए परेशानी का सबब बनने वाली है. अगर तीनों दलों का तालमेल हो गया, तो नीतीश कुमार मुस्लिम वोटों को लेकर जो मंसूबा बांधे हुए हैं, उसे करारा झटका लग सकता है, क्योंकि ऐसे में यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस, लोजपा एवं राजद का गठबंधन ही भाजपा को हराने की ताकत रखता है. अगर मुसलमानों का झुकाव यूपीए गठबंधन की ओर हो गया, तो फिर नीतीश कुमार को जबरदस्त चुनावी घाटे का सामना करना पड़ सकता है.

नीतीश कुमार को इस संभावित ख़तरे का एहसास था, इसलिए उन्होंने लोजपा की तरफ़ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था. लोजपा की तरफ़ उन्होंने ऐसे लुभावने प्रस्ताव रखवाए थे कि उसे ठुकराना मुश्किल जैसा ही था, लेकिन उनके राजनीतिक बड़े भाई नीतीश कुमार की इस चाल को अच्छी तरह समझ गए, इसलिए उन्होंने अपना रवैया बेहद नरम कर लिया और कहने लगे कि बिहार में लोजपा एवं कांग्रेस से तालमेल के लिए वह कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं. एक तरफ़ भाजपा की बढ़त और दूसरी तरफ़ कांग्रेस, राजद एवं लोजपा का संभावित गठबंधन, इस दोहरी राजनीतिक कवायद से नीतीश कुमार इस समय बुरी तरह घिर गए हैं. इसलिए उन्होंने अब बचाव की जगह आक्रमण की नीति अपना ली. अपनी रैलियों में वह भाजपा, राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला कर रहे हैं, ताकि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बुलंद रखा जा सके. इस दरम्यान विशेष राज्य के दर्जे के मसले में भी नीतीश कुमार की किरकिरी हो गई. नीतीश को पूरी उम्मीद थी कि यह मसला, जिसे वह चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, पूरी तरह हिट रहेगा और केंद्र सरकार चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ज़रूर दे देगी.

कांग्रेस से नीतीश कुमार के पिछले दिनों बेहतर होते रिश्ते और केंद्र की राजनीति में जदयू सांसदों की उपयोगिता को देखते हुए ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार अपने मिशन में अब सफल ही होने वाले हैं, लेकिन यहां भी एक बार फिर लालू उनसे भारी निकले. नीतीश कुमार आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद ने अपने प्रभाव और दबाव में यह सुनिश्चित करा दिया कि कम से कम इस लोकसभा चुनाव तक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिले. यह कहा जा सकता है कि विशेष राज्य की गाड़ी लटकने का चाहे जो कारण रहा हो, पर उससे नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर काफी नुकसान हुआ. नीतीश कुमार की इन राजनीतिक असफलताओं की पृष्ठभूमि में अब आगामी लोकसभा चुनाव की बात करते हैं. यह लगभग अब सभी मानकर चल रहे हैं कि मुकाबले के एक छोर पर भाजपा मजबूती से खड़ी हो गई है. अगर लोजपा, राजद और कांग्रेस का गठबंधन मजबूती से उभर गया, तो फिर जदयू का चुनावी आंकड़ा दहाई तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा. ऐसा इसलिए है, क्योंकि ऐसी सूरत में सूबे की चालीस सीटों में कम से कम 20–25 सीटें ऐसी हो जाएंगी, जहां सीधा मुकाबला भाजपा और यूपीए गठबंधन के बीच होगा. अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो जदयू यहां मुख्य मुकाबले से लगभग बाहर रहेगा. बाकी सीटों पर त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार हैं. ऐसे में, दावे के साथ यहां कोई नहीं कह सकता कि यहां कौन किससे बाजी मार ले जाएगा.

कांग्रेस से नीतीश कुमार के पिछले दिनों बेहतर होते रिश्ते और केंद्र की राजनीति में जदयू सांसदों की उपयोगिता को देखते हुए ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार अपने मिशन में अब सफल ही होने वाले हैं, लेकिन यहां भी एक बार फिर लालू उनसे भारी निकले. नीतीश कुमार आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद ने अपने प्रभाव और दबाव में यह सुनिश्चित करा दिया कि कम से कम इस लोकसभा चुनाव तक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिले.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के परिणामों पर ही बिहार की मौजूदा सरकार का भविष्य टिका है. इसकी झलक नीतीश कुमार ने भी अपनी लखीसराय की संकल्प रैली में दे दी है. अगर नीतीश कुमार के खाते में दस से कम सीटें आईं, तो उन्हें दोहरा झटका लगेगा. एक तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद काफी घट जाएगा, ठीक उसी तरह, जैसे भाजपा से अलग होने के बाद प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदारों से उनका नाम चर्चा से हट गया. लेकिन इससे भी बड़ा झटका उन्हें बिहार में अपनी सरकार को लेकर लग सकता है. बहुमत के लिहाज से अभी यह सरकार तलवार की धार पर चल रही है. नीतीश का चुनाव जिताऊ आभामंडल ही इस सरकार के लिए संजीवनी का काम कर रहा है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए और आंकड़ा दस की संख्या नहीं पार कर पाया, तो संदेश बिल्कुल उलटा चला जाएगा. यह परिणाम नीतीश के उस आभामंडल को तोड़ देगा, जिसमें अब तक यह दिखाई पड़ता रहा है कि उनका अपना एक मजबूत वोट बैंक है और वह किसी भी प्रत्याशी को जिताने की ताकत रखते हैं. जिस दिन यह आभामंडल टूटा, नीतीश की सरकार उसी दिन ख़तरे में पड़ जाएगी. पार्टी में संभावित टूट को रोकना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. बिहार में उनके राजनीतिक विरोधी तो उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं. जदयू के जो महत्वाकांक्षी नेता अभी उनकी बात मान रहे हैं या फिर बर्दाश्त कर रहे हैं, वे आशा के अनुरूप चुनाव परिणाम न आने के बाद खुलेआम बोलना शुरू कर सकते हैं. उन्हें रोकने का नैतिक साहस तब नीतीश कुमार के पास काफी कम रह जाएगा. दूसरे दल के जो लोग अभी जदयू में आना चाहते हैं, वे भी अपने क़दम इस हालत में वापस खींच सकते हैं, क्योंकि सभी को अपनी चुनावी जीत की गारंटी चाहिए. मनोनयन कोटे से विधान पार्षद बनना तब और भी टेढ़ी खीर हो जाएगा, क्योंकि तब सभी अपने तेवर कड़े कर चुके होंगे. कहा जाए तो एक बहुत ही मुश्किल राजनीतिक हालात से नीतीश कुमार को जूझना पड़ सकता है.

लोकसभा चुनाव परिणाम के फायदे और नुकसान का नीतीश को भी पूरा एहसास है, इसलिए वह अपनी सभाओं में दिल्ली के लिए ज़्यादा ताकत देने की अपील बार–बार जनता से कर रहे हैं. अगर दस का आंकड़ा नीतीश पार कर गए, तो आशंकाओं से ठीक उलट उसका पूरा फायदा उन्हें मिलेगा. राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद तो बढ़ेगा ही, साथ ही बिहार में जदयू कार्यकर्ताओं के बीच यह साफ़ संदेश चला जाएगा कि विपरीत से विपरीत हालात होने के बावजूद नीतीश कुमार का करिश्मा बरकरार है, जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगा देगा. उधर नीतीश कुमार ने फेडरल फ्रंट का जो शिगूफा छोड़ा है, उसके पीछे भी उनकी गंभीर राजनीतिक चाल है. दस से ज़्यादा सीटों वाला जदयू चुनाव बाद फेडरल फ्रंट में निर्णायक भूमिका निभा सकता है और नीतीश कुमार को अहम ओहदा भी दिला सकता है, लेकिन अगर आंकड़ा दस से कम हो गया, तो इस राजनीतिक चाल की हवा निकल सकती है. इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव नीतीश के लिए जीवन–मरण का प्रश्न बन गया है. अगर इस चुनौती से पार पा गए, तो एक बार फिर वह महानायक की तरह उभर कर सामने आ जाएंगे, लेकिन अगर कहीं ऐसा न हो पाया, तो दिल्ली दूर, बिहार बचाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि वह अपनी हर सभाओं में अब कह भी रहे हैं.हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

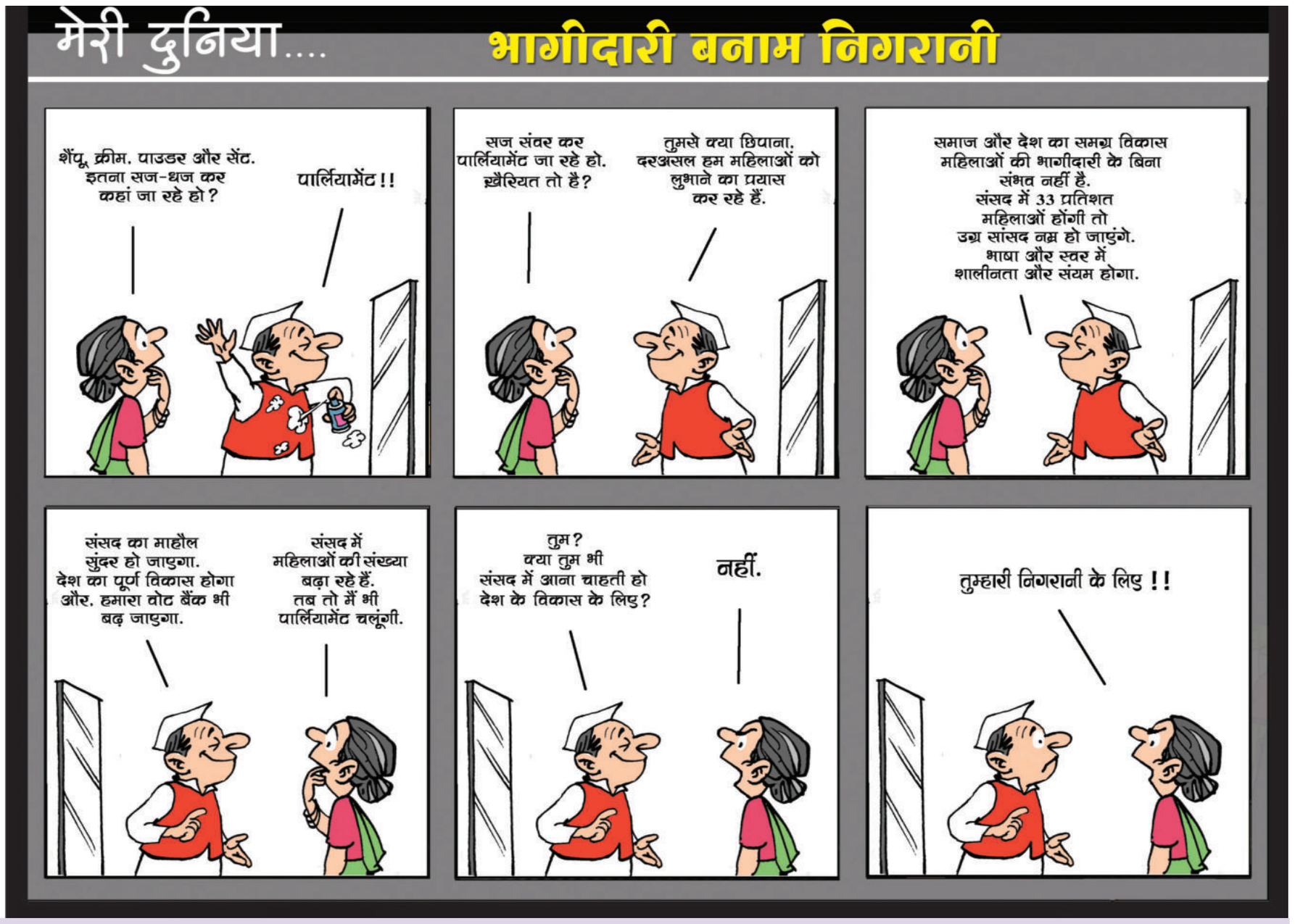

SACHAR COMMITTEE REPORT ON

Social, Economic and Educational status of the Muslim Community of India

सच्चर कमेटी ने अपनी 48वीं अनुशंसा में कहा था कि सरकार को कोई ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए, जिससे मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो सके. इसके लिए सरकार को प्राइवेट सेक्टर और स्वयंसेवक संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए. इस पर यूपीए सरकार पूरी तरह ख़ामोश है. ज़ाहिर है कि उसने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया है, इसलिए उसके पास दावा करने के लिए भी कुछ भी नहीं है. इस प्रकार देखा जाए तो यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की 48वीं अनुशंसा को भी लागू नहीं किया है.

सच्चर समिति की सिफारिशों का सच

73 नहीं, सिर्फ़, 31 पर अमल

चौथी दुनिया ने सच्चर समिति की सभी अनुशंसाओं का गहन अध्ययन करने के बाद पता लगाया है कि 76 में से 45 अनुशंसाओं पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है. आइए देखते हैं कि वे 45 अनुशंसाएं कौन-कौन सी हैं, जिन पर यूपीए सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है.....

(पिछले अंक से आगे)

डॉ. क़मर तबरेज़

20. सच्चर कमेटी ने अपनी 40वीं अनुशंसा में कहा था कि वक्फ़ संपत्ति के उचित प्रयोग से सरकार मुस्लिम समुदाय और प्राइवेट सेक्टर के बीच साझेदारी के अवसर पैदा करने में सहयोग मिलेगा. सरकार का कहना है कि वह राष्ट्रीय वक्फ़ प्राधिकरण निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है जिससे वक्फ़ संपत्ति को पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी के द्वारा उचित ढंग से प्रयोग किया जा सकेगा और इससे मुस्लिम समुदाय को अपने विकास ढांचे को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी. यह सब कब होगा, यह किसी को नहीं मालूम. यूपीए सरकार का दूसरा कार्यकाल भी अब ख़त्म होने जा रहा है. सरकार से जब यह काम पिछले सात वर्षों में, यानी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद से लेकर अब तक नहीं हो सका तो क्या गारंटी है कि इस देश में अगली सरकार जिसकी बनेगी, वह मुसलमानों की समस्याएं हल करेगा?

21. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 41 में कहा था कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्वीकृति के अमल को आसान बनाया जाए. यूपीए सरकार का दावा है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सरकार की ओर से स्वीकृति दिलाने के लिए संसद में एक क़ानून पारित करके अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का राष्ट्रीय आयोग (एनसीएमईआई) स्थापित किया गया, जिसके तहत इस बात को सुनिश्चित किया गया गया कि मुसलमानों सहित देश के सभी अल्पसंख्यकों को संविधान की धारा 30(1) में दर्ज सभी आवश्यक अधिकार मुहैया कराए जाएं. यूपीए सरकार का यह भी दावा है कि एनसीएमईआई के द्वारा अब तक ऐसे 5830 शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा चुका है, जबकि यह कड़वी सच्चाई सामने आ चुकी है कि इन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों के शिक्षण संस्थान बेहद कम हैं और जिन संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया भी गया है, तो वह काग़ज़ी है और व्यवहारिक रूप से वे संस्थाएं अब भी इस दर्जे से वंचित हैं. उदाहरणस्वरूप दरभंगा (बिहार) का 1957 में मुस्लिमों के द्वारा स्थापित किया गया 'मिल्लत कॉलेज', जो 1976 में इस अधिकार से वंचित हो गया था और लगभग 5 वर्षों से एनसीएमईआई के द्वारा अल्पसंख्यक भूमिका की पुष्टि के बावजूद यह अभी तक इससे वंचित है. सरकार के पास मामला अभी खटाई में पड़ा हुआ है. इस कॉलेज के मूल संगठन 'अंजुमन मुस्लिम तालीम' के अध्यक्ष डॉ. अब्दुल वहाब कहते हैं कि मिल्लत कॉलेज के मामले से सरकार के दावे की सच्चाई समझी जा सकती है.

22. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 45 में कहा है कि मुलसमान पिछड़ेपन की दोहरी मार इसलिए झेल रहे हैं, क्योंकि एक तो उनमें शिक्षा की कमी है और दूसरे उन्हें जो शिक्षा मिल भी रही है, वह मानकों पर खरी नहीं उतरती. इसीलिए सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा के मैदान में मौजूद इन ख़ामियों को दूर करे और मुसलमानों की शिक्षा को निश्चित बनाते समय इस बात का भी ख़्याल रखे कि उन्हें मानक शिक्षा प्राप्त हो रही है या नहीं. यूपीए सरकार सच्चर कमेटी की इस 45वीं अनुशंसा पर ख़ामोश है. उसने इस सिलसिले में कोई भी दावा नहीं किया है. इसका मतलब तो यही निकलता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की इस 45वीं अनुशंसा को लागू नहीं किया गया है, वरना वह इस पर अपनी ओर से कोई न कोई दावा ज़रूर पेश करती.

23. सच्चर कमेटी ने अपनी 46वीं अनुशंसा में कहा था कि उच्च शिक्षा के लिए देश में जितने भी लोग योग्य हैं, उनमें मुसलमानों की तुलना के मुक़ाबले एससी/एसटी से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है. सरकार को चाहिए कि वह इसके कारणों का पता लगाकर हल निकाले. यूपीए सरकार का दावा है कि इस सिलसिले में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए) के द्वारा एक स्टडी कराई गई थी. एनयूईपीए ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय विचार कर रहा है.

बड़े अफसोस की बात की है कि यह सब जानते हुए कि मुसलमानों की सभी समस्याओं का मूल कारण उनका शैक्षणिक पिछड़ापन है, यूपीए सरकार उनकी इस कमी को दूर करने के लिए गंभीरता नहीं दिखा रही है. शायद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार जानबूझ कर मुसलमानों को पिछड़ा ही देखना चाहती है. सरकार को कम से कम अब तो यह बता देना चाहिए कि उसे किसी रिपोर्ट को पढ़ने और फिर उसपर कोई फैसला सुनाने में पचास साल चाहिए या 100 साल?

24. सच्चर कमेटी ने अपनी 47वीं अनुशंसा में कहा था कि मदरसों के नवीनीकरण को लेकर किसी योजना पर सरकार को विचार करना चाहिए. यूपीए सरकार का दावा है कि सच्चर कमेटी की इस अनुशंसा के तहत दो काम किए जा रहे हैं. पहला काम तो यह है कि मदरसों में मानक शिक्षा उपलब्ध करने की योजना शुरू की जा चुकी है और दूसरा काम यह है कि सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थानों (मूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों) में बुनियादी ढांचे को दुरूस्त करने की योजना चल रही है. इसके उलट सच्चाई यह है कि यूपीए सरकार की ये दोनों योजनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं. मदरसों में शिक्षा का हाल और वहां का पाठ्यक्रम अब भी वही है, जो सदियों पहले था और अल्पसंख्यक के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में बुनियादी ढांचे अब भी वैसे ही हैं, जैसे पहले थे. इन स्कूलों में अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, तो वह सरकार की सहायता से नहीं, बल्कि मुसलमानों के अपने प्रयासों से हो रहा है. इसलिए यूपीए सरकार का यह कहना कि मदरसों में मानक शिक्षा के लिए वह कुछ कर रही है या फिर अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में वह कोई मदद कर रही है, सरासर झूठ है.

25. सच्चर कमेटी ने अपनी 48वीं अनुशंसा में कहा था कि सरकार को कोई ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए, जिससे मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो सके. इसके लिए सरकार को प्राइवेट सेक्टर और स्वयंसेवक संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए. इस पर यूपीए सरकार पूरी तरह ख़ामोश है. ज़ाहिर है कि उसने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया है, इसलिए उसके पास दावा करने के लिए भी कुछ भी नहीं है. इस प्रकार देखा जाए तो यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की 48वीं अनुशंसा को भी लागू नहीं किया है.

26. सच्चर कमेटी ने अपनी 49वीं अनुशंसा में कहा था कि मुसलमानों के लिए उच्च स्तर पर रोज़गार के पैदा करने के लिए सरकार को कपड़ा व्यापार, ऑटो रिपयेरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी आदि के उत्पादन क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए. यूपीए सरकार ने इस महत्वपूर्ण अनुशंसा को भी लागू नहीं किया है.

27. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 50 में कहा था कि ऐसे मुसलमानों की संख्या देश में अधिक है, जो स्वयं छोटे-मोटे कारोबार में लगे हुए हैं. सरकार को चाहिए कि वह इन मुस्लिम कामगारों के लिए हाई ग्रोथ वाले क्षेत्रों की तलाश करे और उन्हें कम विकास वाले क्षेत्रों से अधिक विकास वाले क्षेत्रों की ओर ले जाए, ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें. यूपीए सरकार ने इस अनुशंसा को भी लागू नहीं किया है, इसीलिए वह इस पर ख़ामोश है.

28. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 51 में कहा था कि मुसलमानों को सीधे तौर पर सरकारी फंड पर मुहैया कराया जाना चाहिए और साथ ही इन प्रोग्रामों का प्रचार किया जाना चाहिए और मुसलमानों को इस बात के लिए जागरूक किया जाना चाहिए कि वे सरकारी सहायता से अपना स्वयं का कारोबार करने की की ओर बढ़ें, लेकिन यूपीए सरकार ने इस सिफ़ारिश पर भी अमल नहीं किया है.

29. सच्चर कमेटी की 52वीं अनुशंसा के अनुसार, मुसलमानों की ग़रीबी में किस हद तक कमी आई है, इसका हर वर्ष संगठित तरीके से पता लगाया जाना चाहिए. यूपीए सरकार ने इस काम को योजना आयोग के सुपुर्द किया था, जिसने इस सिलसिले में तीन वर्किंग ग्रुप क़ायम किए थे, जिनमें से एक वर्किंग ग्रुप ने तो अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी थी, लेकिन शेष दो की रिपोर्ट अब तक जमा नहीं हुई है.

30. मज़ेदार बात तो यह है कि यूपीए सरकार ने अपने अपने दावों की इस सूची में सच्चर कमेटी की अनुशंसा नंबर 56, 57 और 58 को 'गोल कर दिया है, यानी इन तीन अनुशंसाओं का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं हैं. लिहाज़ा, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि सच्चर कमेटी ने अपनी इन तीनों 'गुमशुदा' अनुशंसाओं में क्या कुछ करने के लिए कहा था और सरकार ने इन पर क्या अमल किया?

31. अनुशंसा नंबर 57 लागू ही नहीं हुई है.

31. अनुशंसा नंबर 58 का उल्लेख भी यूपीए सरकार के दावों की सूची से ग़ायब हैं.

33. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 60 में कहा था कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वक्फ़ संपत्तियों के विकास के लिए तकनीकी सलाहकार अमला तैयार करने की आवश्यकता है. यूपीए सरकार का दावा है कि नेशनल वक्फ़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापित करने के लिए अलग से एक प्रस्ताव मौजूद है और अन्तर मंत्रालय सुझावों के लिए मंत्रिमंडल की ओर से एक मसौदा जारी किया जा चुका है, लेकिन जैसा कि हमने चौथी दुनिया के पिछले अंक में देखा कि यूपीए सरकार ने नेशनल वक़्फ़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना के लिए अब तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है और चूंकि अब मनमोहन सिंह सरकार का दूसरा कार्यकाल भी ख़त्म होने वाला है, इसलिए इसकी उम्मीद कम ही है कि इस प्रस्ताव पर सरकार कोई अमल कर पाएगी. इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगली सरकार वक्फ़ संपत्ति के विकास के संबंध से यह कॉर्पोरेशन बना ही देगी.

34. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 61 में कहा था कि सेन्ट्रल वक्फ़ काउंसिल (सीडब्ल्यूसी) और प्रत्येक राज्य के वक्फ़ बोर्ड में कम से कम एक महिला को नामज़द किया जाना चाहिए. यूपीए सरकार कह रही है कि वह वक्फ़ संशोधन बिल के पास होने के बाद इस पर अमल किया जाएगा. वक्फ़ संशोधन बिल अब पास हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय या राज्य वक्फ़ बोर्ड में महिलाओं की नामज़दगी को लेकर अब तक यूपीए सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

35. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 62 में कहा था कि केन्द्रीय वक्फ़ काउंसिल में एक फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए, जिसका चुनाव महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा तय होना चाहिए, मसलन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, विश्वविद्यालयों के कुलपति आदि, जबकि सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल के अन्य सदस्यों का चुनाव विभिन्न पेशों से जुड़े महत्वपूर्ण मुस्लिम व्यक्तियों के बीच से होना चाहिए. इसी प्रकार सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल का सचिव भारत सरकार में कार्यरत संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए. यूपीए सरकार कहती है कि यह सारे काम वक्फ़ एक्ट में संशोधन से संबंधित हैं. सवाल एक बार फिर वही उठता है कि वक़्फ़ एक्ट में जब संशोधन का अमल पूरा हो चुका है, तो फिर सरकार इस पर आख़िर कब अमल करेगी?

36. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 63 में राज्य वक्फ़ बोर्डों का विन्यास कैसे हो, इस पर बात की है. यूपीए सरकार ने इसमें भी वही पुरानी बात दोहराई है कि इसका संबंध वक्फ़ एक्ट में संशोधन से है.

37. यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की 64वीं अनुशंसा का कोई उल्लेख नहीं किया है, बल्कि इसे 'गोल' कर दिया है. इसका मतलब तो यही निकाला जा सकता है कि उसने इस अनुशंसा को लागू नहीं किया है और न ही इसके बारे में कुछ बताने का कष्ट नहीं किया है.

38. सच्चर कमेटी ने अपनी 67 वीं अनुशंसा में कहा था कि तमाम वक्फ़ संपत्तियों की अनिवार्य रूप से ऑडिटिंग होनी चाहिए. यूपीए सरकार कह रही है कि इस पर अमल राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम की स्थापना के बाद होगा क्योंकि इसे भी अभी लागू होना है.

39. सच्चर कमेटी ने अपनी 66वीं अनुशंसा में कहा था कि नेशनल वक्फ़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 500 करोड़ रुपये की लागत से अमल में आना चाहिए. यूपीए सरकार ने अभी तक इस अनुशंसा को लागू नहीं किया है.

40. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 67 में कहा था कि अजमेर दरगाह एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है. यूपीए सरकार का दावा है कि मंत्रालय के अन्दर इस पर अभी विचार किया जा रहा है.

41. सच्चर कमेटी की अनुशंसा नंबर 68 में वक्फ़ संपत्तियां क़ानूनी और प्रशासनिक समीतियों से संबंधित हैं, इन्हें सरकारी प्रभाव से बाहर किया जाना चाहिए. इस पर यूपीए सरकार ने अभी तक कोई अमल नहीं किया है.

42. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 69 में कहा था कि जहां-जहां वक्फ़ संपत्ति का प्रयोग रजिस्टर्ड चैरिटेबिल सोसाइटीज़ या ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, वहां इन संपत्तियों की लीज़ की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 30 साल कर देना चाहिए. यूपीए सरकार ने वक्फ़ संशोधन बिल के पास होने के बाद इस पर कोई अमल नहीं किया है.

43. सच्चर कमेटी ने अपनी 70वीं अनुशंसा में कहा था कि अवैध क़ब्ज़ा करने को लेकर व्याख्या करने की आवश्यकता है. इसके बारे में भी यूपीए सरकार का यही कहना है कि वह वक्फ़ संशोधन बिल के पास होने के बाद इस पर अमल करेगी.

44. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 75 में कहा था कि वक्फ़ संपत्ति से संबंधित नियम बनाए जा सकते हैं. यूपीए सरकार कहती है कि इसका संबंध भी वक्फ़ संशोधन बिल से ही है, जिस पर अमल इस बिल के पास होने के बाद होगा. सवाल अब भी वही है कि वक्फ़ संशोधन बिल तो पास हो चुका है, तो इस पर अमल कब होगा?

45. सच्चर कमेटी ने अपनी अनुशंसा नंबर 76 में कहा था कि वक्फ़ बोर्डों के प्रभावी ढंग से काम काज के लिए लीगल प्रोवीज़न की आवश्यकता है, जो वक्फ़ एक्ट, 1995 में संशोधन के बाद ही हो सकेगा. यूपीए सरकार भी अब तक वक्फ़ संशोधन बिल पास होने का इंतेज़ार कर रही थी. अब, जबकि यह बिल पास हो चुका है, वह अभी तक हरकत में नहीं आई है और सरकार का कार्याकाल भी ख़त्म होने वाला है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वक्फ़ संपत्तियों का भविष्य क्या होगा?

इस प्रकार हमने देखा कि यूपीए सरकार ने कैसे सच्चर कमेटी की 45वीं अनुशंसा को बिल्कुल लागू नहीं किया है और किस प्रकार सरकार के प्रधानमंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने सच्चर कमेटी की 76 में से 72 अनुशंसाओं को लागू कर दिया है. इसे बेशर्मी नहीं तो और क्या कहेंगे. क्या कांग्रेस अब भी इस भ्रम शिकार है कि वह झूठ बोलकर मुसलमानों को मूर्ख बनाने में इस बार भी सफल हो जाएगी? हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. दिल्ली में तो केवल मुसलमानों ने कांग्रेस की इज्जत को नीलाम होने से बचा लिया था, लेकिन 2014 के चुनावों में भी कांग्रेस को बचा लेंगे, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, उसे लेकर पार्टी ऐसा माहौल बना रही है, जैसे समूचा देश ही उस व्यक्ति को वोट देने जा रहा है. कांग्रेस को इस झांसे में नहीं आना चाहिए. कांग्रेस को उसी राजनीतिक रास्ते पर चलना चाहिए, जिस पर वह चल रही है. हां, यह ज़रूर है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, उस पर रोक लगानी चाहिए. पार्टी के नेता गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए. चुनाव के दृष्टिकोण से देखें, तो चुनाव आयोग बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग, दोनों को आपस में इस मसले पर बात करनी चाहिए कि देश में होने वाले चुनावों को किस तरह गौरवशाली तरीके से संपन्न किया जा सके. निर्वाचक और भी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है.

यह मौजूदा सरकार की परीक्षा का दौर है

राहुल जो भी कर रहे या कह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि ठीक है. उनकी कोशिश बेहतर है, लेकिन अगर देश के हालात उनके पक्ष में नहीं रहते, तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि तेलंगाना प्रकरण के चलते संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है. ऐसे में वह इस सत्र में कोई बिल कैसे पास करा पाएंगे?

संसद सत्र चल रहा है. शुरू में मौजूदा सरकार संसद के इस आख़िरी सत्र को लेकर स्पष्ट नहीं थी. दिसंबर में यूपीए सरकार ने एक निर्णय लिया कि शीतकालीन सत्र का सत्रावसान नहीं किया जाएगा, जिससे राष्ट्रपति को नए सत्र का उद्घाटन नहीं करना पड़ेगा. इस तरह फरवरी में होने वाले सत्र को शीतकालीन सत्र का ही विस्तार मान लिया जाएगा. ऐसा करने की पीछे यूपीए सरकार की सोच क्या है? दरअसल, अगले कुछ महीनों के भीतर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में बजट सत्र नहीं पेश किया जाएगा, लेकिन इस सत्र के माध्यम से कुछ आर्थिक सुधार और बिल पेश किए जाएंगे, जो कि मौजूदा सरकार और कांग्रेस पार्टी, दोनों की छवि सुधारने में मदद करेंगे. इसके अलावा पार्टी जिस माध्यम से खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, वह हैं राहुल गांधी. राहुल गांधी एकाएक भ्रष्टाचार से जुड़े मसलों के प्रति गंभीर होते हुए यह राय जाहिर कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े क़ानून बनाने होंगे. लेकिन, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने यह क़दम उठाने में काफी देर कर दी.

जुलाई 2011 में राहुल गांधी अन्ना आंदोलन के माध्यम से उठाई जा रही आवाज को अपना समर्थन देते, तो आज उनका पक्ष मजबूत रहता, क्योंकि राहुल गांधी युवा हैं, उन्होंने कभी खुद कोई मंत्री पद नहीं लिया. ऐसे में, वह आसानी से यह स्टैंड ले सकते थे कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उस पर क़ानून के तहत कार्यवाही होगी. लेकिन दुर्भाग्य से तब वह राजनीतिक क्रियाकलापों में इतने सक्रिय नहीं थे, इसलिए तब उन्होंने अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई. हालांकि, अब वह ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है. बावजूद इसके वह जो कुछ कर रहे हैं, उसका स्वागत करना चाहिए. मसलन, दागी नेताओं को लेकर सरकार के अध्यादेश पर अपना कड़ा रुख और जनलोकपाल बिल पास कराने में बड़ी भूमिका और फिर इसी क्रम में उनका यह कहना कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाले चार-पांच बिल लोकसभा में लंबित हैं और वह चाहते हैं कि वे बिल पास हों, उनकी प्रतिबद्धता जाहिर करता है.

राहुल जो भी कर रहे या कह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि ठीक है. उनकी कोशिश बेहतर है, लेकिन अगर देश के हालात उनके पक्ष में नहीं रहते, तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि तेलंगाना प्रकरण के चलते संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है. ऐसे में वह इस सत्र में कोई बिल कैसे पास करा पाएंगे? सीमांध्र और तेलंगाना की मांग कर नेता संसद की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जब तक कि उन्हें इसका कोई हल नहीं मिल जाता. और वैसे भी मौजूदा सरकार की स्थितियों पर ग़ौर करें, तो सत्ता के दो केंद्र बने हुए हैं. एक तरफ़ हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो दूसरी तरफ़ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी. अब यह संघर्ष त्रिकोणीय हो गया है, जिसके चलते कई गतिरोध बन रहे हैं. राहुल गांधी जितने आक्रामक दिख रहे हैं, उससे तुलना करते हुए लोग कह रहे हैं कि वह हाल में एक अंग्रेजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में खुद को सही ढंग से पेश नहीं कर पाए. बावजूद इसके, मुझे लगता है कि उनके जवाब तर्कसंगत थे, हां, यह ज़रूर है कि युवाओं को और अधिक व्यवहारिक होना चाहिए. तर्कसंगत इसलिए, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हैं, तो उन्होंने सही जवाब दिया कि इस देश में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है. जनता जिन सांसदों को चुनती है, वही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं.

इधर भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, उसे लेकर पार्टी ऐसा माहौल बना रही है, जैसे समूचा देश ही उस व्यक्ति को वोट देने जा रहा है. कांग्रेस को इस झांसे में नहीं आना चाहिए. कांग्रेस को उसी राजनीतिक रास्ते पर चलना चाहिए, जिस पर वह चल रही है. हां, यह ज़रूर है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, उस पर रोक लगानी चाहिए. पार्टी के नेता गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए. चुनाव के दृष्टिकोण से देखें, तो चुनाव आयोग बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग, दोनों को आपस में इस मसले पर बात करनी चाहिए कि देश में होने वाले चुनावों को किस तरह गौरवशाली तरीके से संपन्न किया जा सके. निर्वाचक और भी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है. बावजूद इसके, देश में बड़े पैमाने पर जाति और मजहब के आधार पर मतदान किया जाता है. इस पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है.

यह मौजूदा लोकसभा का आख़िरी सत्र है और मेरा मानना है कि जिस तरह से आंध्र का मसला सुलग रहा है, उसके चलते इस सत्र की कोई उपादेयता नहीं साबित हो पाएगी. ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वह आंध्र या किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी. यह बेहद मूर्खतापूर्ण क़दम है. आंध्र प्रकरण कोई चुनावी मसला नहीं है. यह एक मांग है, जो कि 1948 से ही लंबित है. ऐसे में, इस मसले पर विचार न किया जाए, यह भी संभव नहीं है. वास्तव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को तभी तेलंगाना का गठन कर देना चाहिए था, जब उसने झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया था. जो हुआ सो हुआ, अब यह गठन हो जाना चाहिए. हां, यह ज़रूर है कि अब यह एक समझौते की तरह होगा, लेकिन चुनावों के बाद आप ऐसा कर सकते हैं. साथ ही सभी पार्टियों को यह सर्वसम्मति दिखानी होगी कि चुनावों के बाद यह गठन हो, भले ही चुनावों के परिणाम कैसे हों और किसी की भी सरकार बने.

एक और मुद्दा, जो कि पिछले तक़रीबन दस वर्षों से लंबित है. दरअसल, स्वर्गीय जस्टिस वर्मा ने किसी संदर्भ में एक निर्णय दिया था कि हिंदुत्व हिंदूवाद नहीं है, इसलिए अगर कोई हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगता है, तो यह नहीं माना जा सकता कि वह धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है. निश्चित रूप से यह एक भ्रामक विचार है. अब यह मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और एक बड़ी बेंच के सामने विचाराधीन है. सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर इस बारे में अपना निर्णय देगा, लेकिन मेरा मानना है कि यह निर्णय चुनावों के पहले ही आना चाहिए. चुनावों के पहले ही सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के संदर्भ में धर्म का क्या आशय है? भले ही आप हिंदुत्व और हिंदूवाद के बीच एक रेखा खींचें, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आप आरएसएस, भाजपा और हिंदू महासभा या इस विचारधारा वाली दूसरी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं. अगर ऐसा करने की अनुमति है, तो मुसलमानों को भी इस आधार पर वोट मांगने की छूट मिलनी चाहिए. ऐसे में समूची व्यवस्था ही ख़तरे में पड़ जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

खर्च का इंतजाम और प्रचार

ठाकुर दास बंग

खर्च कैसे इकट्ठा किया जाएगा?

मतदाताओं का वोट, मतदाताओं का उम्मीदवार और मतदाताओं का पैसा, यह बात मन में रखिए. क्या अपने उम्मीदवार के लिए हर मतदाता एक रुपया नहीं दे सकता? प्रति मतदाता एक रुपया (ईच वन रुपी वन) की मांग कीजिए. कुछ लोग ज़्यादा भी देंगे, कुछ लोग नहीं भी देंगे. अगर कुछ रुपया बच जाएगा, तो निर्वाचक मंडल के कोष में जमा रहेगा.

प्रचार का ढंग क्या होगा?

प्रचलित ढंग से बिल्कुल भिन्न.

किस तरह?

हमारा काम चुनाव के काफी पहले शुरू होगा. हम जल्दी में काम नहीं करेंगे. हमारी टोलियां हर गांव, हर मतदाता के पास पहुंचेंगी, ताकि वे समझें कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हर मतदाता का स्थान है. हम महत्व मतदाता को देंगे, न कि उसकी जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, भाषा, धन या दल को. हम प्रचार में इन बातों का नाम भी नहीं लेंगे. हम मतदाताओं को बताएंगे कि किस तरह ये बातें कह-कहकर हम स्वयं अपने लोकतंत्र को गंदा और कमजोर बनाते हैं. हमें मतदाता के दिमाग़ में गलत नारे नहीं भरने हैं, उसे समझदार बनाना है.

चुनाव में तो और बहुत कुछ होता है. शराब की बोतलें चलती हैं, तरह-तरह की चीजें बांटी जाती हैं, बूथ लूटने के लिए लठैत बुलाए जाते हैं. उनसे जान कैसे बचेगी?

मत कीजिए यह काम, अपने-आप जान बच जाएगी. जिन मतदाताओं ने स्वयं अपना उम्मीदवार तय किया है, क्या वे अपने ही उम्मीदवार से घूस मांगेंगे? ऐसे गलत काम करने की बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए. हमारी टोलियों की ज़िम्मेदारी होगी कि चुनाव में किसी प्रकार का भ्रष्ट काम न होने दें, बूथ कैप्चरिंग तो कदापि न होने दें. चुनाव के दिन लोग मतदान केंद्र पर जुलूस बनाकर जाएं और उत्साह के साथ मतदान करें.

बूथ लूटने के लिए लठैत बुलाए जाते हैं, जो बम-बंदूक से लैस होते हैं, उनका मुकाबला कैसे होगा?

उत्तर-कौन नहीं जानता कि बूथ की लूट कैसे होती है? यह कहिए कि लूट कराई जाती है. वोट नहीं, लूट-यह है हमारी राजनीति का प्रचलित रवैया. अगर इस राजनीति को बदलना है, तो बूथ की लूट सबसे पहले ख़त्म करनी पड़ेगी. एक ओर लोक उम्मीदवार खड़ा किया जाए और दूसरी ओर बूथ की लूट जारी रहे, यह कैसे हो सकता है! अगर गांव के लोग डट जाएं और संगठित होकर चौकसी रखें, तो बाहर के लोग गांव में आकर बूथ की लूट कदापि नहीं कर सकते.

हमारे उम्मीदवार को यह सब नहीं करना है. मतदाताओं ने जिस व्यक्ति को लोक उम्मीदवार बनाया है, उसे जिताने की ज़िम्मेदारी मतदाताओं की है, निर्वाचक मंडल की है. लोक उम्मीदवार अपने आप नहीं खड़ा हुआ है, उसे मतदाताओं ने खड़ा किया है. वोट खरीदने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा, न निर्वाचक मंडल करेगा और न उम्मीदवार.

लेकिन इसके लिए गांव को संगठित होना पड़ेगा, बिना संगठन के मुकाबला नहीं हो सकता.

संगठन तो बुनियादी शर्त है. बिना संगठन के कोई काम कैसे होगा? गांव-गांव में ग्राम शांति सेना का संगठन होना चाहिए, जिसमें पुरुषों एवं स्त्रियों के अलग-अलग दस्ते हों. अपने गांव के महिला दस्ते से कहिए कि बूथ कैप्चरिंग रोकने की अगुवाई उसे करनी चाहिए. पुरुष दस्ते साथ रहें, किंतु नेतृत्व महिलाओं का हो.

लठैतों के सामने महिलाएं!

जी हां, लठैतों का मुकाबला महिलाएं करेंगी. आग बुझाने के लिए पानी चाहिए. महिलाओं को कमज़ोर मत समझिए. उनकी शक्ति के सामने लठैत और लुटेरे कभी नहीं ठहर सकते.

एक ओर लठैत बूथ लूटते हैं, दूसरी ओर उम्मीदवार मतदाताओं को खरीदने की कोशिश करते हैं. आजकल लगभग सभी उम्मीदवार ऐसा करते हैं. मतदाताओं की भी आदत बिगड़ गई है...

हमारे उम्मीदवार को यह सब नहीं करना है. मतदाताओं ने जिस व्यक्ति को लोक उम्मीदवार बनाया है, उसे जिताने की ज़िम्मेदारी मतदाताओं की है, निर्वाचक मंडल की है. लोक उम्मीदवार अपने आप नहीं खड़ा हुआ है, उसे मतदाताओं ने खड़ा किया है. वोट खरीदने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा, न निर्वाचक मंडल करेगा और न उम्मीदवार. मतदान शुद्ध होगा. पैसा, शराब एवं सवारी आदि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा. लोक उम्मीदवार की जीत मतदाताओं की जीत है और हार मतदाताओं की हार है, यह बात हर मतदाता के दिल में बैठ जानी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

संगठन तो बुनियादी शर्त है. बिना संगठन के कोई काम कैसे होगा? गांव-गांव में ग्राम शांति सेना का संगठन होना चाहिए, जिसमें पुरुषों एवं स्त्रियों के अलग-अलग दस्ते हों. अपने गांव के महिला दस्ते से कहिए कि बूथ कैप्चरिंग रोकने की अगुवाई उसे करनी चाहिए. पुरुष दस्ते साथ रहें, किंतु नेतृत्व महिलाओं का हो.

पाठकों की दुनिया

पेंशन का औचित्य

लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास रखने वाली स्वर्गीय इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए आपातकाल के समय जेल जाने वाले लोगों को पेंशन दी जा रही है, जो कि निंदनीय है. 1974 में डीआईआर एवं मीसा में सिर्फ़ दो प्रतिशत लोग जेल गए थे, जबकि आपातकाल के दौरान जो लोग जेल गए, उनमें से सिर्फ़ पांच प्रतिशत लोगों का ही संबंध 1974 के आंदोलन से था, बाकी कई संस्थाओं पर प्रतिबंध था. इंदिरा गांधी को तानाशाह कहकर और जेपी को बदनाम करके आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोगों को पेंशन दिया जाना अनुचित है, इसका विरोध होना चाहिए. साथ ही संपूर्ण क्रांति का जो काम अधूरा रह गया है, उसे पूरा किया जाना चाहिए.

-मनमोहन प्रसाद गुप्ता, जेपी आंदोलनकारी, बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार.

सुशासन का भ्रष्टाचार

बिहार की सुशासन सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. जनता, अफसर, नेता, ठेकेदार एवं इंजीनियर, सभी लोग मिलकर लूट रहे हैं और बिहार का विकास कर रहे हैं. दुकानों के फर्जी बिल लगाकर भुगतान उठाए जा रहे हैं. विद्यार्थियों की पोशाक योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, मिड डे मील और साइकिल सहायता राशि में बड़े पैमाने पर गोलमाल किया जा रहा है. इंदिरा आवास योजना में रिश्वतखोरी चल रही है. जो पैसा दे रहा है, उसे ही योजना का लाभ मिल रहा है और जिसके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है, वह इस योजना के लाभ से वंचित है.

-परमानंद मिश्र, खरपोखरा, चंपारण, बिहार.

अनुचित मांग

चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर रोक लगाने की मांग नितांत अ-जनतांत्रिक है और हमारे संविधान में संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाली है. ज़्यादातर विकसित देशों, जैसे अमेरिका, रूस एवं जापान आदि में ऐसे सर्वेक्षणों को मान्यता प्राप्त है. भारत एक विशाल एवं लोकतांत्रिक देश है, जहां अनेक राजनीतिक दल अपना दांव खेलते हैं. ऐसे में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात होगा. अपना जनाधार तेजी से खिसकता देखकर कांग्रेस ऐसी मांग कर रही है, यह दलील देकर कि सर्वेक्षण वैज्ञानिक नहीं होते, इन्हें पूरी तरह पारदर्शी तरीके से नहीं किया जाता, इससे जनमत प्रभावित होता है. क्या लोकतंत्र में जनमत को प्रभावित करना अपराध है?

-अशोक निर्मोही, दरभंगा, बिहार.

मुसलमानों के साथ धोखा

10-16 फरवरी का अंक मिला. कवर स्टोरी-मुसलमानों को कांग्रेस ने सिर्फ़ धोखा दिया है, में मनीष कुमार ने मुसलमानों के प्रति कांग्रेस के रवैये को रेखांकित किया है. मुसलमान कांग्रेस लिए केवल एक मतदाता है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं. यूपीए के दस सालों के शासनकाल में जो हाल मुसलमानों का हुआ है, वह बेहद चिंताजनक है. मुसलमान केवल वोटों की राजनीति बनकर रह गया है. कांग्रेस सच्चर कमेटी द्वारा दिए सुझावों को अभी तक लागू नहीं करा पाई और नए वादे करने लगी है. जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, कांग्रेस हो या दूसरी राजनीतिक पार्टियां, मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए उनसे नए-नए वादे करने लगती हैं.

-फिरोज आलम, रामपुर, उत्तर प्रदेश.

बदलाव की ज़रूरत

आलेख-क्या ऐसे वर्ल्डकप जीतेगी टीम इंडिया (अंक: 10-16 फरवरी) में नवीन चौहान द्वारा जो तथ्य रखे गए हैं, वे बिल्कुल सही हैं. अभी हाल में टीम इंडिया का जो प्रदर्शन देखने को मिला है, वह काफी निराशाजनक है. टीम इंडिया और उसके चयनकर्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि 2015 का विश्वकप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है और टीम इंडिया का जो प्रदर्शन न्यूजीलैंड में देखना को मिला है, वह बेहद चिंताजनक है. ऑस्ट्रेलिया में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. टीम इंडिया अपने प्रदर्शन में सुधार करेगी, तभी अगला विश्वकप जीत पाएगी, अन्यथा विश्वकप में बने रहना भी भारत के लिए मुश्किल होगा.

-नवनीत सिंह, झांसी, उत्तर प्रदेश.

आप का सच

10-16 फरवरी के अंक में प्रकाशित, नीरज सिंह द्वारा लिया गया ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह का साक्षात्कार पढ़ा. कई तरह की सच्चाइयां सामने आईं. पता चला कि जिन्हें हम बदलाव की राजनीति का वाहक समझ रहे थे, वे तो जनता का अ-राजनीतिकरण करने वाली ताकतें हैं, आम आदमी को गुमराह करने वाली ताकतें हैं. यही नहीं, वे कॉरपोरेट्स के हितों को साधने में दीगर राजनीतिक पार्टियों से भी दो क़दम आगे हैं.

-त्रिलोक कुमार झा, नई दिल्ली.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

लोकतंत्र को तमाशा न बनने दें

भारत की राजनीति में वैसे तो अजीब बातें होती रहती हैं, पर इस बार एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है. प्रधानमंत्री पद की दावेदार दो बड़ी पार्टियां बिना किन्हीं मुद्दों के लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं. मुद्दों से मेरा मतलब बिना किन्हीं विशेष चिन्हित कार्यक्रमों के. वे जब मुद्दे की बात कहती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पांच टी (टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी) की बात करती है, राहुल गांधी नौजवानों को स्थान दिलाने की बात करते हैं. लेकिन कोई भी स्पष्टतय: यह नहीं बताता कि इनका मतलब क्या है. वे यह नहीं बताते कि अगर सत्ता में आएंगे, तो शुरू के एक साल में क्या-क्या करेंगे?

मुद्दों का मतलब रामचरित मानस की यह चौपाई नहीं होती कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता. समस्याएं अनंत हैं, जब हम सत्ता में आ जाएंगे, तो उन्हें हल कर देंगे. पहले हमें सत्ता में तो भेजो. होना यह चाहिए कि महंगाई को नियंत्रित करने का क्या कार्यक्रम है? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का क्या कार्यक्रम है? बेरोज़गारी को नियंत्रित करने का क्या कार्यक्रम है? देश में साठ साल के भीतर टूट गए शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे को पुन:निर्मित करने का क्या कार्यक्रम है. क्या कोई वक्त बताया जा सकता है, एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल या दस साल, जबकि इनके ऊपर सरकारों का ध्यान जाएगा. दोनों पार्टियां इन सवालों के ऊपर चुप हैं.

एक और अद्भुत चीज सामने आई है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिर्फ़ नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं और नीति संबंधी वक्तव्य दे रहे हैं. कांग्रेस की ओर से सिर्फ़ राहुल गांधी घूम रहे हैं और नीति संबंधी वक्तव्य दे रहे हैं. हालांकि दोनों के नीति संबंधी वक्तव्यों का कोई मतलब नहीं है. दोनों मिलकर देश की जनता को सड़क पर होने वाले मदारी के तमाशे में उलझा रहे हैं. दोनों एक-दूसरे द्वारा बोली गई भाषा के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं. जाहिर है, जिस तरह से हम अपने दु:ख-दर्द को भूलने के लिए मनोरंजन के साधनों का सहारा लेते हैं, उसी तरह से इन चुनावों में हम ऐसी शब्दावली और ऐसे हाव-भाव में मजा लेने लगे हैं, जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं है. चुनाव देश में व्याप्त समस्याओं का हल करने वाले दल को सत्ता में पहुंचाने का माध्यम है, पर जितने भी दल हैं, वे सब सत्ता में पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन समस्याओं को हल करने की कोई गारंटी नहीं देते.

भारतीय जनता पार्टी कथावाचक शैली में सभाओं पर सभाएं करती जा रही है और उसके मुख्य कथावाचक घटनाओं के ऊपर टिप्पणी करके अपनी पार्टी के जरिए लोगों को यह बता रहे हैं कि यही बदलाव का उनका दर्शन है. दूसरी तरफ़ कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी के ऊपर निर्भर है और उसने उनकी छवि नाराज युवा या अंग्रेजी में कहें, तो एंग्री यंगमैन की बनाई है. वह हर जगह चिल्लाते हुए एक-दूसरे से न जुड़ने वाले शब्दों की माला लोगों के सामने परोसते हैं. यूं भी राहुल गांधी ने अपना कैंपेन बहुत देर से शुरू किया, लेकिन अभी भी वह कैंपेन नहीं कर रहे हैं. अभी भी वह कुछ सभाएं ही कर रहे हैं. उनका पहला बहु-प्रचारित इंटरव्यू अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ में देखा गया. अर्नब गोस्वामी ने वही सवाल राहुल गांधी से पूछे, जो सामान्य सवाल थे. देश को लेकर उनके नज़रिए, देश में व्याप्त अंतर्विरोध, देश में विकास और भ्रष्टाचार की जड़ों से संबंधित सवाल तो उन्होंने पूछे ही नहीं. लेकिन, उन आसान सवालों में भी राहुल गांधी इस तरह उलझ गए कि देश के लोगों को लगा कि उनके अंदर समस्याओं को देखने का कोई दृष्टिकोण है ही नहीं. नरेंद्र मोदी इस मामले में होशियार हैं. वह पत्रकारों का सामना नहीं करते. पत्रकारों के सवालों को आंख दिखाकर अनदेखा कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी क़ीमत पर वह देश से जुड़े सवालों और देश के सामने आने वाली समस्याओं पर अपना मुंह न खोलें, जिसमें वह अब तक सफल होते जा रहे हैं.

इन दोनों बड़े दलों के अलावा छोटे-छोटे दल भी समस्याओं को सामने रखकर अपनी कोई आधी-अधूरी योजना भी जनता के सामने नहीं रख रहे हैं. मार्क्सवादी पार्टी सालों पहले से जिस कार्यक्रम की बात करती आई है, अभी भी उसी के ऊपर चल रही है. एक नया मोर्चा बनने जा रहा है, जिसके मुख्य शिल्पी सीताराम येचुरी और नीतीश कुमार हैं. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) में सबसे होशियार नेता के तौर पर सीताराम येचुरी उभरे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए उन दो राज्यों में जगह बनाने की कोशिश की है, जहां उन्हें जगह मिलेगी, आज तक ऐसा कोई नहीं सोचता था. जयललिता ने सीपीएम के लिए सीटें छोड़ने की घोषणा की है और उन्होंने राज्यसभा में मार्क्सवादी पार्टी के एक नेता को भी अपने समर्थन से भेज दिया है. दूसरी तरफ़ उड़ीसा में भी सीताराम येचुरी ने नवीन पटनायक को अपने साथ रहने के लिए तैयार कर लिया है. बंगाल में सीपीएम को कितनी सीटें मिलेंगी, वह दस सीटों की संख्या पार कर पाएगी भी या नहीं, इसमें संदेह है, क्योंकि इतने सालों के भीतर भी कम्युनिस्ट पार्टी के 35 साल के शासन के ख़िलाफ़ उपजे गुस्से को अभी तक कम होते हुए नहीं देखा गया है. 30 जनवरी को कोलकाता के परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी की रैली हुई और वह रैली ऐसी थी, जैसी अब तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुई नहीं. लगभग 20 लाख लोग मैदान में थे, लगभग पांच लाख लोग मैदान के बाहर और तकरीबन पांच लाख लोग ही कोलकाता की सड़कों पर थे. पूरे पश्चिम बंगाल से लोग आए थे, गांव-गांव से लोग आए थे. ममता बनर्जी के पास काडर नहीं है. काडर वामपंथी दलों के पास है. लोग अपने आप आए. शांति से, अनुशासन से आए. रैली में शिरकत की और वापस चले गए. पंचायत चुनाव के बाद यह दूसरा संकेत है कि बंगाल अभी भी ममता बनर्जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है. तब जब सीपीएम को बंगाल में सीटें नहीं मिल रहीं, तो फिर दूसरी जगह जहां सीटें मिल सकती हैं, वह केरल है. इसका मतलब संपूर्ण वामपंथी पार्टियां 20-22 सीटों के आसपास सिमटती दिखाई दे रही हैं. अगर समूचे देश में कम्युनिस्ट पार्टियों को 20 या 22 सीटें मिलने की संभावना है, तब कैसे तमिलनाडु और उड़ीसा में उनके साथ दोनों मुख्यमंत्रियों ने समझौता किया, यह रहस्य है. रहस्य इसलिए भी है, क्योंकि जयललिता और सीपीएम को जोड़ने वाला दूर-दूर तक कोई धुंधला सूत्र भी नज़र नहीं आता. पर बिना किसी जोड़ने वाले सूत्र या धागे के अस्तित्व के दोनों में समझौता हो गया और ठीक यही बात नवीन पटनायक के साथ भी है.

एक चौदह पार्टियों का गठबंधन बना है, जिसमें कोई किसी को कहीं पर मदद नहीं कर पाएगा. एक वोट कोई किसी को दूसरे राज्य में नहीं दिलवा पाएगा. नीतीश कुमार, एचडी देवेगौड़ा, नवीन पटनायक, जयललिता, सीताराम येचुरी एवं बाबूलाल मरांडी, ये प्रमुख नाम हैं अपने-अपने यहां से. लेकिन इन्हें अगर चुनाव जीतना होगा, तो अकेले जीतना होगा. हां, इनकी सभाओं में ये सारे नेता होंगे, लेकिन इनके पास न तो कोई भी साझा घोषणा-पत्र है और न साझा कार्यक्रम. उसी तरह शरद पवार भी इस गठजोड़ में शामिल हैं, लेकिन शरद पवार की पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को जोड़ने का सूत्र क्या है, यह भी समझ में नहीं आता. दरअसल, यह भी एक वैसा ही तमाशा रचने की कोशिश है, जैसा तमाशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस देश के लोगों के सामने मनोरंजन कार्यक्रम के रूप में रख रही हैं. एक और ताकत दिल्ली की गद्दी के लिए अपने को तैयार कर रही है.

ममता बनर्जी देश की पहली ऐसी नेता हैं, जो पहले दिन से ही आर्थिक कार्यक्रम देश के सामने रख रही हैं और उन्होंने इस देश के सबसे बड़े नैतिक आधार वाले व्यक्ति अन्ना हजारे के आर्थिक कार्यक्रम को न केवल माना, बल्कि उसे स्वीकार करने वाला जवाबी पत्र भी अन्ना हजारे को भेज दिया है. अन्ना हजारे ने 17 सूत्रीय कार्यक्रम मौजूदा आर्थिक नीतियों के ख़िलाफ़ बनाया है. अभी मैंने ममता बनर्जी के अलावा जितने भी राजनीतिक दलों का जिक्र किया, ये सब मौजूदा आर्थिक व्यवस्था के पोषक हैं और एक ही अर्थव्यवस्था यानी बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था को चलाने में इनकी रुचि है. जिस अर्थव्यवस्था ने इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी बढ़ाई, जिसने किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी और जिसने संभावनाओं के रास्ते बंद कर दिए, उसी अर्थव्यवस्था को ये सारे दल लागू करना चाहते हैं. और ये देश के लोगों को यह बता रहे हैं कि इनमें से अगर कोई सत्ता में आया, तो देश में न तो महंगाई ख़त्म होगी, न भ्रष्टाचार ख़त्म होगा और न बेरोज़गारी ख़त्म होगी. गांव की लूट वैसे ही जारी रहेगी. इस स्थिति में ममता बनर्जी ने अन्ना हजारे के कार्यक्रम को स्वीकार करके कम से कम यह संकेत दिया है कि वह इस देश की बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था को हटाकर गांव आधारित अर्थव्यवस्था लागू करेंगी. वह तकनीकी का उपयोग विकास के लिए करेंगी, शोषण के लिए नहीं. उनके इस कार्यक्रम में जहां किसान हैं, नौजवान हैं, छोटे उद्योग हैं, गांव आधारित उद्योग हैं, एक नई अर्थव्यवस्था की संभावना है, वहीं पर शहरों के भीतर भी पानी-बिजली जैसी चीजें सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं. ममता बनर्जी के आर्थिक कार्यक्रम में हर गांव को बिजली देने, हर गांव में बिजलीघर बनाने का वादा किया गया है. अपने शासन के अंतिम दिनों में मनमोहन सिंह ने गैस को लेकर अमेरिका के साथ ताबड़तोड़ समझौते किए. दरअसल, हमारे देश के सारे संसाधन कैसे अमेरिका के उपयोग में आएं और हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को किस तरह से सहारा दें, इसकी योजना न केवल मौजूदा सरकार ने बनाई है और कांग्रेस पार्टी उसकी पोषक है, बल्कि नरेंद्र मोदी तो यहां तक कह रहे हैं कि यह योजना ठीक से नहीं बन रही है. हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पोषण देने वाली योजना बनाएंगे. और जिन लोगों के ऊपर इससे लड़ने का ज़िम्मा था, जैसे जयललिता, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, नवीन पटनायक और वामदल, ये लोग एक अनहोली अलाएंस या अलाएंस ऑफ कनविनिएंश या सुविधा के लिए गठजोड़ जैसे सवालों पर उलझे हुए हैं.

देश के सामने चुनौती है और ममता बनर्जी के सामने सारे लोग एक स्वर से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आख़िर मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने की बात ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं? उन्हें भी उन्हीं सवालों को सामने रखना चाहिए, जिन सवालों को ये लोग तमाशे के रूप में देश के सामने रख रहे हैं. इसलिए आने वाला लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी के अलावा सारे दलों के लिए तमाशा दिखाने का एक मौक़ा है. एक हल्की संभावना ममता बनर्जी ने दिखाई है कि वह देश के लोगों के सामने मुद्दे रखकर तस्वीर साफ़ करने की कोशिश कर रही हैं. अब ज़िम्मा लोगों पर भी है कि वे इस चीज को समझ पाते हैं या फिर साठ साल से चले आ रहे तमाशे को चलने देते हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

कौन बनेगा समलैंगिकों की राजनीतिक आवाज़?

समलैंगिक संबंधों की स्वतंत्रता को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इस निर्णय से दु:खी नहीं होना चाहिए और न ही क्रोधित. मैंने समलैंगिक अधिकारों को लेकर पचास वर्ष पूर्व इंग्लैंड में चले अभियानों को नजदीक से देखा है. मैं कह सकता हूं कि यह कभी आसान नहीं रहा है, लेकिन यह आवश्यक है कि समाज के बहुसंख्यक तबके में इस अधिकार के प्रति साम्य भाव हो. इंग्लैंड में साठ के दशक के आख़िरी में वोल्फेनडेन की रिपोर्ट के बाद समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कोई मजबूत क़दम उठाने में सरकार को चालीस साल लग गए.

तक़रीबन बीस साल पहले ब्रिटेन में काम कर रहा एक भारतीय अर्थशास्त्री मुझसे मिलने के लिए आया. उसने मुझसे पूछा कि क्या उसे स्वदेश वापस लौट जाना चाहिए और वहीं सेटल हो जाना चाहिए? मैंने कहा, हां, बिल्कुल. तभी उसने अपनी मुख्य परेशानी कह ही दी और बोला कि क्या उसे भारत में समलैंगिक होने की वजह से दिक्कतें आएंगी? मैंने कहा कि हिंदू धर्म में अब्राह्मिक धर्मों की तरह समलैंगिकता को अस्वीकार नहीं किया गया है. विक्टोरियन काल के आधुनिकीकरण के समय में ही भारतीय समाज ने कुछ नैतिकतावादी पुराने विचारों पर कुठाराघात किया था, जो शारीरिक संबंधों, विशेष रूप से समलैंगिक संबंधों को गलत मानते थे. उस समय मेरा ऐसा मानना था कि अगर वह नौजवान अपने संबंधों के बारे में बहुत बढ़-चढ़कर बात नहीं करेगा, तो उसे भारत में रहने में कोई परेशानी नहीं होगी. उसके बाद वह युवक भारत लौट गया और इस समय अपने घर पर ही रहता है.

मुझे यह विचार सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया निर्णय के बाद आया, जिसमें समलैंगिक संबंधों पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं और दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को किनारे कर दिया गया, जिसकी वजह से धारा 377 आईपीसी से बाहर होने की कगार पर आ गई थी. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद ऐसा लगा था कि शायद सरकार इस पर दृढ़ता से आपत्ति दर्ज कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब एकमात्र उपाय संसद में कानून बनाकर इस धारा को आईपीसी से निकालना ही बचा है, लेकिन इसकी भी कितनी उम्मीद की जा सकती है? संसदीय गतिविधियां अपने पूरे उद्देश्य के साथ चल नहीं पाती हैं. चुनावों के बाद आपसी झगड़ों में शायद कुछ कमी आए, कम से कम शुरुआती दो-तीन सालों तक तो ऐसा ही लगता है. लेकिन क्या हम इस बात की आशा कर सकते हैं कि संसद धारा 377 को हटाने के लिए कोई

मजबूत क़दम उठा सकेगी? यह 2014 के लोकसभा चुनाव के विजेताओं पर निर्भर करेगा और अगर भाजपा जीतेगी तो, जैसा लग रहा है, इस मुद्दे पर कुछ होने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि वह धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हैं. इस कारण इसकी उम्मीद कम ही है कि वह इस पर कुछ करें या कोई क़ानून लाएं.

समलैंगिक संबंधों की स्वतंत्रता को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इस निर्णय से दु:खी नहीं होना चाहिए और न ही क्रोधित. मैंने समलैंगिक अधिकारों को लेकर पचास वर्ष पूर्व इंग्लैंड में चले अभियानों को नजदीक से देखा है. मैं कह सकता हूं कि यह कभी आसान नहीं रहा है, लेकिन यह आवश्यक है कि समाज के बहुसंख्यक तबके में इस अधिकार के प्रति साम्य भाव हो. इंग्लैंड में साठ के दशक के आख़िरी में वोल्फेनडेन की रिपोर्ट के बाद समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कोई मजबूत क़दम उठाने में सरकार को चालीस साल लग गए. जब कंजरवेटिव पार्टी ने इस पर निर्णय लिया और यह निर्णय इतनी देर से उस स्थिति में हुआ, जबकि मशहूर पब्लिक स्कूलों में कई कंजरवेटिव नेता रहे हैं, जहां पर इसका पूरा प्रसार है. यहां तक कि सांसदों के बीच भी कई ऐसे समलैंगिक रहे हैं, जिन्होंने कभी अपनी यौन प्राथमिकताओं को उजागर नहीं किया. इसलिंगटन साउथ के सांसद क्रिस स्मिथ पहले ऐसे नेता थे, जो इस मामले में खुलकर सामने आए कि मैं पार्टी में एक्टिव रहा हूं और इस अभियान के लिए भी. स्मिथ द्वारा खुली घोषणा करना समलैंगिकता के मुद्दे पर एक मजबूत क़दम था.

लेबर पार्टी समलैंगिक अधिकारों को लेकर एक्टिव थी, लेकिन पार्टी के भीतर भी कई नेता ऐसे थे, जो इसे लेकर कंजरवेटिव व्यवहार करते थे. ट्रेड यूनियन वाले ब्रेड और बटर को लेकर तो काफी उत्साह दिखाते थे, लेकिन समलैंगिक संबंधों को लेकर वे मृतप्राय: थे. मारग्रेट थैचर वाली कंजरवेटिव सरकार इस बात के पक्ष में भी नहीं थी कि समलैंगिक अध्यापक स्कूलों में पढ़ाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा होने से ये अध्यापक विद्यार्थियों में भी इस बीमारी का संचार कर सकते हैं. समय और एक बार फिर हमने भी एजुकेशन एक्ट से उस धारा को हटवाया, जो समलैंगिक विरोधी थी. इंग्लैंड के गिरिजाघरों में भी खुले रूप से गे बिशप रहे हैं. कैथोलिक चर्च को 21वीं सदी में हाल में पोप फ्रांसिस लेकर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद कैथोलिक गिरिजाघरों में खुले तौर पर समलैंगिक पादरी रहे हैं.

इस तरह से भारतीय समलैंगिकों के लिए यह एक लंबा अभियान है कि वे अपने माता-पिता, शिक्षकों एवं दोस्तों को इस बात के लिए जागरूक करें कि वे एक स्वस्थ वातावरण तैयार करें. यह अभियान कोर्ट के इस निर्णय मात्र से समाप्त नहीं हो जाता है. ज़रूरत इस बात की है कि समलैंगिकों की जीवन प्रणाली को किसी भी अन्य जीवन प्रणाली की तरह ही समाज में बड़े स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा. इस कार्य में राजनेताओं का बड़ा योगदान हो सकता है, जैसा कि बिल क्लिंटन और बराक ओबामा ने दिखाया है. आख़िर भारत में कौन है, जो समलैंगिकों की राजनीतिक आवाज बनेगा? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल अथवा कोई दूसरा, जो हाल ही में उभरा हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार

चौथी दुनिया ब्यूरो

हमने आपको तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया कि कैसे इन शब्दों का गलत इस्तेमाल करके लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर देते हैं. इस बार हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में. कैसे और कब फंसता है संसदीय विशेषाधिकार का पेंच. सबसे पहले एक उदाहरण से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं. अमेरिका से एटमी डील के दौरान यूपीए सरकार को जब सदन में विश्वास मत हासिल करना था, उसके कुछ घंटे पहले सदन में भारत के संसदीय इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना घटित हुई. भाजपा के तीन सांसदों ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये नोट उन्हें सरकार के पक्ष में विश्वास मत के दौरान वोट देने के लिए घूस

के रूप में मिले हैं, जिसे एक मीडिया चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अपने कैमरे में कैद कर लिया था और उसे लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को सौंप दिया था. बाद में कुछ गैर सरकारी संगठनों और लोगों ने जब सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करके वीडियो टेप सार्वजनिक करने की मांग की, तो लोकसभा ने उस टेप को सार्वजनिक करने से मना कर दिया. लोकसभा ने बताया कि वीडियो टेप अभी संसदीय समिति के पास है और जांच की प्रक्रिया चल रही है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस सूचना के दिए जाने से धारा 8 (1)(सी) का उल्लंघन होता है. इस धारा में बताया गया है कि ऐसी सूचना, जिसके सार्वजनिक किए जाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है, उसे सूचना के अधिकार के तहत दिए जाने से रोका जा सकता है.

ऐसा ही एक मामला और है, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग से मुख्यमंत्री राहत कोष में मुंबई ट्रेन धमाकों के बाद प्राप्त अनुदानों के खर्चों का ब्यौरा मांगा था. उन्हें यह कहकर सूचना देने से मना कर दिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष एक निजी ट्रस्ट है और सूचना कानून के दायरे में नहीं आता, जबकि शैलेष का मानना था कि राहत कोष एक पब्लिक बॉडी है और आयकर छूट का लाभ उठाती है. मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है, इसलिए इस सूचना के दिए जाने से विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन नहीं होता है.

एक मासिक पत्रिका से जुड़े रमेश तिवारी ने उत्तर प्रदेश के स्पीकर और स्टेट असेंबली के सचिव के पास एक आवेदन किया था. आवेदन के माध्यम से उन्होंने यह जानना चाहा था कि क्या कोई लेजिसलेटर अपने आप से कोई सरकारी ठेका ले सकता है और यदि ऐसा ठेका लिया गया है, तो क्या ऐसे सदस्य की असेंबली से सदस्यता रद्द की जा सकती है? असेंबली से रमेश को जब कोई जवाब नहीं मिला, तो मामले को वह उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष ले गए. आयोग के तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त एम ए खान ने स्पीकर और सचिव को सूचना के अधिकार कानून के तहत नोटिस जारी कर दिया. नोटिस पाते ही सबसे पहले तो रमेश का आवेदन खारिज कर दिया गया और उसके बाद असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसके माध्यम से सूचना आयोग को चेतावनी दी गई कि आयोग का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और इस तरह की सूचना मांगने और आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने से विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है. आयोग को आगे से ऐसे मामलों में सावधान रहने की चेतावनी दी गई.

राहुल विभूषण ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और तीन सांसदों के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि मांगी थी. दरअसल, एक पेट्रोल पंप को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बंद कर दिया गया था. इस पेट्रोल पंप को दोबारा खुलवाने के लिए तीन सांसदों ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा था. राहुल ने इस पत्र के जवाब की प्रतिलिपि मांगी थी, जिसे यह कहकर देने से मना कर दिया गया कि इसे दिए जाने से संसद के विशेषाधिकारों का हनन होता है. आयोग में सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ने माना कि सांसद द्वारा लिखे गए पत्र का संसद या संसदीय कार्रवाई से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और इस सूचना के सार्वजनिक किए जाने से संसद के किसी विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होता है. आयुक्त ने मांगी गई सूचना 15 दिनों के भीतर आवेदक को सौंपे जाने का आदेश दिया. कुल मिलाकर देखें, तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा नहीं होता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301, ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
वित्तीय फायदे साधारण रहेंगे. खाने का खास ख्याल रखें, नहीं तो पेट से जुड़ी किसी दिक्कत से गुजर सकते हैं. आप जो यात्रा करने जा रहे हैं, वह आपके लिए फायदे से भरपूर रहेगी और आपको मनचाही सफलता दिलाएंगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
मांगलिक कार्यों के लिए जारी प्रयास सफल होगा. कारोबारी स्थितियां कामों में रुकावट डालेंगी और आप कई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में रहेंगे. किसी बुजुर्ग व्यक्ति पर खर्च होगा. दोस्तों एवं परिवार के साथ आपको बेहद खुशी मिलेगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आपके पास कई विकल्प होंगे, जिनका आप भरपूर इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदे में रहेंगे. व्यवसायिक क्षेत्र में किसी काम की शुरुआत में देर होगी. यात्रा उम्मीदों के मुताबिक सफल नहीं हो पाएगी. वाणी में मधुरता बनाए रखें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
व्यवसायिक सफलता खुशियों से भर देगी. कोई नया प्रॉजेक्ट शुरू होगा, जो मेहनत के बाद सफलता दिलाने वाला रहेगा. फाइनेंशल ग्रोथ के लिए आपको अपने निवेश पर फोकस रखकर चलना ज़रूरी होगा. दिल के मामले में कोई नौजवान मददगार साबित होगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आर्थिक क्षेत्र में जारी प्रयास सफल साबित होगा. पैसों से जुड़े मामले में आपके साथ बड़ों का आशीर्वाद रहेगा. व्यवसायिक स्तर पर आपका अस्त-व्यस्त व्यवहार तनाव का कारण बन सकता है. स्वास्थ्य को लेकर परेशान न हों. परिवार में कोई महिला आपके लिए चिंता का कारण बनेगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
वक़्त के साथ आप कई दिक्कतों से बाहर निकल आएंगे. नए अवसर रिलेशनशिप में रोमांस एवं धैर्य लाएंगे. वित्तीय बदलाव सकारात्मक रहेंगे, लेकिन आपकी उम्मीदों से कम होंगे. प्रॉपर्टी में पैसा निवेश करने के बारे में सोचेंगे. दिल से जुड़े कुछ मामले, जो लंबे समय से परेशान किए थे, दूर हो जाएंगे.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह यात्रा करने से बचें, नहीं तो आप बेहद थकान, हड्डियों में दर्द जैसी तकलीफों से गुजरेंगे. निवेश में नए सिरे से प्लानिंग करके आप अपना करियर आगे बढ़ा पाएंगे. परिवार में कुछ मामले सिर उठाएंगे, जो तनाव का कारण बनेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
वित्तीय तौर पर कोई मजबूत व्यक्ति काम के मामले में आपकी मदद करेगा. वित्तीय फायदे होंगे और आप उन्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेकर चलेंगे. किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता की संभावना है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
वाहन सावधानी से चलाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है. पेट से संबंधी शिकायत हो सकती है. ट्रैवल से जुड़े मामलों में बेहद खर्चा होगा.फाइनेंशल तौर पर कोई अकेली महिला आपके लिए मददगार रहेगी. किसी नए प्रॉजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
परिवार में कोई नई शुरुआत खुशियां और शांति लाने का कारण बनेगी. वाणी पर मधुरता बनाए रखें, वरना विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. आय के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे. किसी अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिलेगा, जो आपके लिए लाभप्रद होगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
लंबे समय से अधूरा पड़ा कार्य पूरा होगा. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है. दोस्तों से अधिक बात न करें, क्योंकि लड़ाई- झगड़े की स्थिति पैदा हो सकती है. कोई नया व्यवसाय शुरू करने से पहले सोच-विचार कर किसी निर्णय पर पहुंचें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो चुप रहने से बेहतर होगा कि आप अपनी परेशानी दूसरों से शेयर करें. व्यर्थ की बातों में न उलझें, क्योंकि वे आपको पीड़ा पहुंचा सकती हैं. इस सप्ताह समाज के कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे. मनोरंजन के अवसर भी प्राप्त होंगे.

सोशल मीडिया विंडो

लाइक इट

अखिलेश अखिल

जो जनता कल तक नेताओं के पीछे दौड़ रही थी, आज नेता उनके पीछे दौड़ लगा रहे हैं. यह है लोकतंत्र की मजबूती और राजनीति के बदलते मिजाज का प्रतीक. लेकिन एक सवाल है, देश के युवा पार्टी लाइन से आख़िर ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं? देश के युवा एक होकर राजनीति को बदलें, तो बड़े बदलावों की संभावना है. राजनीतिक दल इस बात को समझ रहे हैं. यही वजह है कि उन्होंने युवाओं को बांटकर रख दिया है.

राजीव थेरपा

समय बीतने के साथ, तब जबकि, अपने वर्तमान में भोगे हुए यथार्थ से आगे बढ़ जाते हैं हम, तब स्थितियों का विश्लेषण आसान/सरल हो जाता है, तभी तो हम खुद को इतने समझदार मानने लगते हैं कि गांधी-नेहरु आदि सबकी ही धज्जियां उड़ाने की योग्यता पा लेते हैं...बेशक हमारा यह विश्लेषण खुद हमारी ही धज्जियां क्यूं न उड़ा देता हो...!!

कार्टून क्लास

लहरी का कार्टून फेसबुक वाल से साभार

स्वीट-ट्वीट

आमिर खान

दो दिन की ज़िंदगी है,
इसे दो ही उसूलों पर
गुजार दो.
रहो तो फूलों की तरह,
बिखरो तो खुशबू की तरह.

अरविंद केजरीवाल

दिल्ली वालों के लिए बिजली की किल्लत पैदा करने वाले अनिल अंबानी राजनीति कर रहे हैं. किसके इशारे पर वह ऐसा कर रहे हैं?

गॉसिप गैलरी

मित्रों से सुनता रहता हूं कि मुल्क में फासिज़्म के पदचाप सुने जा रहे हैं. मैंने भी कई बार सुनने की कोशिश की, पर एक तो मेरे कान कुछ कमज़ोर हैं और दूसरे मैंने यूरोप का इतिहास भी ठीक से नहीं पढ़ा है. मित्र कहते हैं कि वे रहेंगे ही नहीं इस देश में, प्रगतिशील जर्मनीवासियों की तरह जलावतन हो जाएंगे. मेरा क्या होगा? मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं, मैं कहां जाऊं? और सबसे ख़तरे की बात तो यह है कि जब तथाकथित फासिज़्म आएगा, तो फासिज़्म से लड़ने वाले योद्धा पहले ही फ़रार हो जाएंगे...?? भाई कुछ लोग रह जाइएगा!

अभय तिवारी

अभय कुमार सिंह

केजरीवाल का अगला अनशन 20 फरवरी से सूर्य देवता के ख़िलाफ़ है. उनका कहना है कि सूर्य सिर्फ़ 12-13 घंटे ही रोशनी देता है और अंधेरा होने पर दिल्ली में बलात्कारी इसका फायदा उठाते हैं. वह मांग करेंगे कि सूर्य अपनी रोशनी का टाइम बढ़ाकर कम से कम 18 घंटे करे.

अमेरिका, भारत और अन्य देशों से मिली अरबों डॉलर की सहायता के चलते अफगानियों के जीवनस्तर में काफी सुधार आया है. तालिबान शासन की तुलना में वहां के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं. महिलाएं घरों से निकलने लगी हैं. आंकड़े बताते हैं कि सत्तर लाख से अधिक बच्चे स्कूल जाने लगे हैं. अब सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो नया राष्ट्रपति बनेगा, क्या वह अफगानिस्तान में सुधारों की नई इबारत लिख सकेगा.

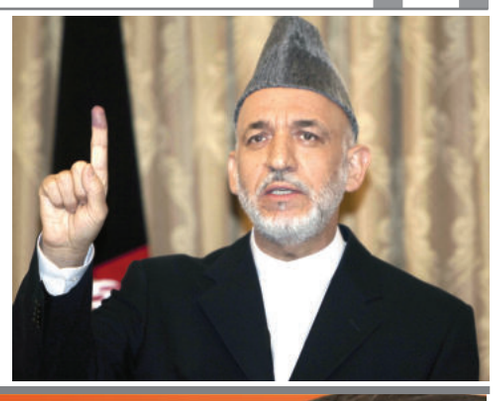

अफगानिस्तान में चुनाव

कैसी होगी नई सुबह

अफगानिस्तान में अप्रैल में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं. हामिद करज़ई के बाद कौन बनेगा अफगानिस्तान का राष्ट्रपति, इसे लेकर अमेरिका, पाकिस्तान और भारत की जिज्ञासा स्वाभाविक हैं, क्योंकि लंबे अर्से के बाद करज़ई का शासन समाप्त हो रहा है. चुनाव की सुगबुगाहट और प्रचार अभियान के शुरू होते ही तालिबान ने भी अपने आतंकी पांव पसारने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में अमन-चैन की आस में अफगानियों के ज़ेहन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की नई सुबह कैसी होगी.

हामिद करज़ई

हामिद करज़ई 2004 में अफगानिस्तान के पहले चुने गए राष्ट्रपति बने. इससे पहले वे तीन साल तक देश के आंतरिक नेता के तौर पर काम कर रहे थे. उनका जन्म 24 दिसंबर, 1957 में कंधार में हुआ. करज़ई का भारत से नाता पुराना रहा है. काबुल में कुछ देर पढ़ाई करने के बाद वे भारत के शिमला में पढ़ाई के लिए चले गए. 90 के दशक के शुरुआती सालों में जब तालिबान का उदय हुआ था तो करज़ई ने पहले उसका समर्थन किया था, लेकिन 1994 तक आते-आते वे तालिबान को शक़ की निगाह से देखने लगे. इसके बाद उन्होंने अपनी राह अलग कर ली. दिसंबर 2001 में तालिबान को उनके अंतिम गढ़ कंधार से निकालने में करज़ई ने अहम भूमिका निभाई थी. अफगानिस्तान में 2001 में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन में सम्मेलन हुआ, ताकि वहां अंतरिम सरकार का गठन हो सके. करज़ई को तब तक अमेरिका का समर्थन हासिल हो चुका था. ■

अब्दुल्ला अब्दुल्ला

अब्दुल्ला अब्दुल्ला अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं. अब्दुल्ला अब्दुल्ला का जन्म 1960 में हुआ था. 1995 में जब कुछ समय के लिए अफगानिस्तान में नॉर्दन एलायंस का शासन था तो वे विदेश मंत्री बने. अब्दुल्ला अब्दुल्ला का संबंध जनजातीय ताजिक समुदाय से है. पेशे से डॉक्टर रहे अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में कुछ समय शरणार्थियों के साथ काम किया. अस्सी के दशक में वे ताजिक समुदाय के नेता अहमद शाह मसूद के साथ जुड़ गए. फिर तालिबान के आने के बाद भी वे निर्वासन में काम कर रहे विदेश मंत्री के तौर पर जाने जाते रहे. नॉर्दन एलायंस के नेता जनरल मसूद की हत्या के बाद वे गुट के तीन अहम नेताओं में से एक बनकर उभरे. ■

राजीव रंजन

अफगानिस्तान में 5 अप्रैल को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं. चुनाव प्रचार जोरों पर है. अफगानिस्तान से इस साल अमेरिकी अगुवाई वाले नाटो बलों की विदाई के बीच इस चुनाव को अफगानिस्तान के लिए काफी अहम माना जा रहा है. यह चुनाव भारत के लिए भी अहम है, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति हामिद करजई का रुख भारत के प्रति हमेशा से ही दोस्ताना रहा है. अफगानिस्तान के कानून के मुताबिक करज़ई तीसरी बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते. ऐसे में भारत के लिए अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में अगला राष्ट्रपति जो बनेगा, वह भारत के हितों का कितना ख्याल रखेगा.

फिलहाल चुनाव प्रचार के साथ-साथ अपराधी एवं विद्रोही तत्व खूनी खेल भी शुरू कर चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (आईएएसएफ) के वरिष्ठ अमेरिकी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मार्क मिली ने भी अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले की आशंका व्यक्त की है. कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि तालिबान निर्दोष अफगानी नागरिक, अफगान सेना या अमेरिकी गठबंधन सैनिकों पर और हमले कर सकता है. आखिर तालिबान चाहता भी तो यही है कि अफगानिस्तान में आतंक और भय का माहौल पैदा कर फिर से तालिबानी शासन स्थापित किया जा सके. यह चुनाव विदेशी सैनिकों के अफगानिस्तान से हटने की तैयारी के बीच साढ़े तीन लाख अफगान बलों के लिए एक परीक्षा भी माना जा रहा है. इसी वर्ष के अंत तक अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी भी होनी है.

साल 2001 में तालिबान के पतन के बाद से देश में करजई का शासन है. उन पर कई बार जानलेवा हमले किए गए. हो सकता है कि इन चुनावों के बाद मई के आखिर में दो मजबूत दावेदारों के बीच दूसरा रन ऑफ हो. अब्दुल्ला अब्दुल्ला साल 2009 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे. तब करजई की जीत हुई थी और चुनावों में धांधली होने का आरोप लगा था. अब्दुल्ला पूर्व विदेश मंत्री हैं और उन्हें पद के मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि पिछले दिनों अब्दुल्ला के दो सहयागियों की जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो चुनाव में हिंसा के वीभत्स रूप को सामने ला रहा है. चुनाव में अब्दुल्ला के अलावा अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व वित्त मंत्री अशरफ गानी और करजई के प्रति वफादार जलमाई रसौल तथा राष्ट्रपति के बड़े भाई कयूम करजई शामिल हैं.

तालिबान के चंगुल से आजाद होने के बाद अफगानिस्तान में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. हालांकि अफगानियों द्वारा अमेरिकी सेना के विरोध के कारण इसका खामियाजा भी यहां के नागरिकों को विरोध और खून-खराबे के तौर पर देखने को मिला है. अमेरिका, भारत और अन्य देशों से मिली अरबों डॉलर की सहायता के चलते अफगानियों के जीवनस्तर में काफी सुधार आया है. तालिबान शासन की तुलना में वहां के बच्चे स्कूल जाने लगे. महिलाएं घरों से निकलने लगीं. आंकड़े बताते हैं कि सत्तर लाख बच्चे स्कूल जाने लगे हैं. हालांकि यह सच्चाई है कि अमेरिकी मदद के बिना अफगानिस्तान सरकार की स्थिति रेंगने वाली सरकार की हो जाएगी. इस साल के अंत तक अमेरिकी बलों के स्वदेश लौटने का असर अफगानिस्तान को मिलने वाली सुविधाओं और वित्तीय सहायता पर भी पड़ सकता है. जब तक ओबामा प्रशासन अफगानी राष्ट्रपति हामिद करजई को सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के लिए नहीं मना लेता, तब तक वित्तीय सुविधाओं को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी. इस समझौते के तहत 2014 के बाद भी कुछ अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में रह सकेंगे. करजई ने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. अमेरिका चाहता है कि करजई जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दें. ऐसा नहीं होने पर अफगानिस्तान को दी जा रही मदद अमेरिका वापस ले सकता है. वर्ष 2001 में तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद से अमेरिका अफगानिस्तान को मदद के तौर पर 88 अरब डॉलर दे चुका है. अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव के बाद अफगानिस्तान में हालात किस तरह के रहते हैं. तालिबान शासन की तुलना में अफगानिस्तान में काफी हद तक अमन-चैन कायम हो गया है. हालांकि छिटपुट घटनाएं होती रहीं, लेकिन इसका उदाहरण सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि तमाम इस्लामिक देश हैं.

अफगानिस्तान में चुनाव के बाद अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यह तो बाद की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि हामिद करज़ई ने जिस जिम्मेदारी के साथ अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण किया है, उसे शायद ही कोई उसी ढंग से आगे बढ़ा पाए. करज़ई ने विकास का एक ऐसा खाका खींचा है, जिसके नक्शे कदम पर कोई भी अगला राष्ट्रपति बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है. हालांकि यह चुनाव बाद देखने वाली बात होगी.

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ हमेशा विरोधी रुख अपनाती रही है. दूसरी तरफ अमेरिका ने भी पाकिस्तान को खुश रखने के लिए भारत को अफगानिस्तान से हमेशा दूर ही रखा. भारत ने भी अफगानिस्तान में अपना सहयोग पुनर्निर्माण तक ही सीमित रखा. भारत और अफगानिस्तान के सम्बन्ध आपस में हमेशा ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं. पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत विरोधी रुख हो. दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि वह अफगानिस्तान में एक ऐसी सत्ता स्थापित करे, जो अमेरिका विरोधी न हो, लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के कुछ ऐसे सहयोगी हैं, जो अमेरिका के कट्टर विरोधी हैं. ऐसे में अपने सपने को साकार करने के लिए अमेरिका को अफगानिस्तान में भारत कि भूमिका को स्वीकार करना होगा. यह सब करज़ई जैसे अच्छे शासक ही कर सकता है, जो चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगा.

अफगानिस्तान के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत ने पिछले एक दशक के भीतर अपना काफी कुछ दांव पर लगाया है. इस दौरान भारत ने वहां दो अरब डॉलर से भी ज्यादा के निवेश किए हैं, जिसके तहत वहां न केवल 220 किमी लंबी सड़क बनाई गई है, बल्कि बिजली ट्रांसमिशन लाइन और सलमा बांध भी बनाया है. इसके अलावा काबुल में अफगानिस्तान की संसद के भवन का निर्माण भी किया है. इसलिए अफगानिस्तान में चुनाव बाद बनने वाले राष्ट्रपति का महत्व भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.

हाल के घटनाक्रम को देखा जाए तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने अमेरिका को खरी-खरी सुना दिया है. करजई ने कहा है कि वे अमेरिका के साथ सुरक्षा के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के समझौते को तभी स्वीकार करेंगे, जब अमेरिका अफगानिस्तान में शांति के लिए तालिबान से बातचीत की शुरुआत में सहायता करे. उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वे अमेरिका के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे और न ही उनका देश किसी तरह का दवाब सहेगा. क्या करज़ई की नीतियों को चुनाव में निर्वाचित राष्ट्रपति लागू कर सकेंगे, यह देखने वाली बात होगी.

साल 2001 में तालिबान के पतन के बाद से देश में करजई का शासन है. उन पर कई बार जानलेवा हमले किए गए. करजई द्वारा तीसरे कार्यकाल के लिए मना करने के बाद 5 अप्रैल को वोटिंग की राह साफ हो गई है. हो सकता है कि इन चुनावों के बाद मई के आखिर में दो मजबूत दावेदारों के बीच दूसरा रन ऑफ हो. अब्दुल्ला साल 2009 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे. तब करजई की जीत हुई थी और चुनावों में धांधली होने का आरोप लगा था. अब्दुल्ला अब्दुल्ला पूर्व विदेश मंत्री हैं और उन्हें पद के मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है.

तालिबान का रुख

तालिबान ने अफगानिस्तान में पांच अप्रैल को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को नामंजूर कर दिया है. साथ ही इसमें बाधा डालने के लिए हमले भी तेज कर दिए हैं. तालिबान ने अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों में कई आत्मघाती बम हमले भी करने शुरू कर दिया है. पिछले दिनों तालिबान ने कम सुरक्षा वाले रेस्टोरेंट पर हमला कर 21 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी. 2001 के बाद से ही तालिबान इस कोशिश में है कि वह दोबारा से अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाए. हालांकि, वर्तमान राष्ट्रपति करज़ई ने तालिबान की इस कोशिश पर पानी फेर दिया और उसके खिलाफ हर कड़ी कार्रवाई की. अब तालिबान यह चाहता है कि करज़ई के जाने के बाद वह किसी दूसरे शासक को मजबूती से वहां पांव न जमाने दे. हालांकि, राष्ट्रपति उम्मीदवारों में प्रबल दावेदार अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी तालिबानियों के भुग्तभोगी रह चुके हैं. इसलिए वह कभी नहीं चाहेंगे कि तालिबान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हों. अब्दुल्ला की यह सोच भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के हित में है, जो अफगानिस्तान में एक नई सुबह लेकर आएगी ■

feedback@chauthiduniya.com

साई

साई बाबा में भी ये सारे गुण विद्यमान थे. उन्होंने भक्तों की इच्छा–पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था. उनकी कृपा (दया) बड़ी ही विचित्र थी. वे भक्तों को स्वयं अपने पास आकर्षित करते थे, अन्यथा उन्हें कोई कैसे जान पाता. भक्तों हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते, जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस नहीं कर सकतीं. एक और रोचक कथा है.

एक बार...

साई राम साई श्याम

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा बड़े ही दयालु हैं. बाबा भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. वह भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और उन्हें पापों से मुक्त करते हैं. भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्तिपूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अन्त:करण वाले भक्त द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं.

यदि भक्त सचमुच में साई बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई, तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे. आज आपको इसी से जुड़ी एक कथा के बारे में बताते हैं. गुरु तो अनेक हैं, कुछ गुरु ऐसे हैं, जो द्वार–द्वार हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं. वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं. वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग ही करते हैं. वे वस्तुत: अपवित्र और

वे शिरडीवासी धन्य हैं, जिन्होंने साई बाबा की ईश्वर-रूप में उपासना की. सोते-जागते, खाते-पीते, वाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे. साई बाबा के अतिरिक्त दूसरे किसी ईश्वर को वे मानते ही न थे. शिरडी की नारियों के प्रेम माधुरी का तो कहना ही क्या है. वे बिल्कुल भोली-भाली थीं. उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था.

अधार्मिक होते हैं. साई बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया. दैहिक बुद्धि उन्हें किंचिंत मात्र भी छुई नहीं थी, लेकिन उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था.

गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत. अनियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक में वृद्धि होती है, जिसे वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, लेकिन नियत गुरु की संगति मात्र से बुद्धि का ह्रास शीघ्र हो जाता है. गुरु अनेक प्रकार के होते है, जो भिन्न–भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं. यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भव सागर से पार उतार दे, वही सदगुरु है. साई बाबा इसी कोटि के सदगुरु थे. उनकी महानता अवर्णनीय है. जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा–पूरा विवरण कह देते थे. वे समस्त भूतों में ईश्वर–दर्शन किया करते थे. मित्र और शत्रु उन्हें दोनों एक समान थे. वे नि:स्वार्थी तथा दृढ़ थे. भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था. वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए. देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र चिंता न थी. देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था. यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे.

वे शिरडीवासी धन्य हैं, जिन्होंने साई बाबा की ईश्वर–रूप में उपासना की. सोते–जागते, खाते–पीते, वाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे. साई बाबा के अतिरिक्त दूसरे किसी ईश्वर को वे मानते ही न थे. शिरडी की नारियों के प्रेम माधुरी का तो कहना ही क्या है. वे बिल्कुल भोली–भाली थीं. उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था. यद्यपि वे शिक्षित न थीं तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी. यह कोई विद्धता न थी, वरन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरक था. कविता तो सच्चे प्रेम का प्रगट स्वरूप ही है, जिसमें चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन या रसिकता का अनुभव करते हैं. सर्वसाधारण को इन लौकिक गीतों की बड़ी आवश्यकता है.

बाबा की विनयशीलता

ऐसा कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं, जैसे कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता. साई बाबा में भी ये सारे गुण विद्यमान थे. उन्होंने भक्तों की इच्छा–पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था. उनकी कृपा (दया) बड़ी ही विचित्र थी. वे भक्तों को स्वयं अपने पास आकर्षित करते थे, अन्यथा उन्हें कोई कैसे जान पाता. भक्तों हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते, जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस नहीं कर सकतीं. एक और रोचक कथा है. बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दासानुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारे दर्शन मात्र से मुझे सांत्वना मिली. यह तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार है कि जो मुझे तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ. तुम्हारे दर्शन कर मैं अपने को धन्य समझता हूं. कैसी विनम्रता है.

यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा विषय–पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, लेकिन उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और न ही उनके उपभोग का ज्ञान था. वे खाते अवश्य थे, लेकिन उनकी जिव्हा को कोई स्वाद न था. वे नेत्रों से देखते थे, लेकिन उस दृश्य में उनकी कोई रुचि न थी. काम के संबंध में वे हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे. उन्हें किसी पदार्थ में रुचि न थी. वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहां समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थीं. संक्षेप में वे नि:स्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

हृदय रोग संबंधी कुछ वैज्ञानिक अध्ययन

डॉ. अभय बंग

भारतीय लोगों में हृदय रोग के आधिक्य, इंसुलिन रेजिस्टंस एवं सिंड्रोम एक्स–इन विषयों के अध्ययनों का उल्लेख इससे पूर्व किया ही जा चुका है. कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन इस प्रकार हैं:–

फ्रामिंगहैम स्टडी: अमेरिका में बॉस्टन शहर से 20 मील की दूरी पर 24,000 की जनसंख्या वाले फ्रामिंगहैम नामक छोटे से शहर का चुनाव किया गया एवं 1949 में वहां हृदय रोग क्यों और किसे होता है, इसका अध्ययन प्रारंभ किया गया. इस शहर में 30 से 62 वर्ष की आयु के 5209 स्त्री–पुरुष सैंपलिंग की पद्धति से चुनकर उनकी पूरी जांच की गई. उनके खाने–पीने–रहने संबंधी सैकड़ों बातों की विस्तृत जानकारी नोट की गई. इन 5209 लोगों की हर दो वर्षों में जांच एवं उनकी जीवनशैली का विस्तृत लेखा–जोखा, यह सब गत 52 वर्षों से लगातार चल रहा है. उनमें से कई व्यक्तियों का इस दौरान देहांत हो गया अथवा उन्हें हृदय रोग अथवा अन्य रोग हो गए. वे उनके डॉक्टरों द्वारा अथवा हर दो वर्षों में होने वाली अध्ययन जांच से ज्ञात होते रहे. 5000 लोगों के जीवन की सैकड़ों बातों की जानकारी रखने की वजह से उनमें से हृदय रोग क्यों और किन्हें होते हैं, इस विषय में अमूल्य जानकारियां प्राप्त हुईं. हृदय रोग होने के ख़तरे का निम्न घटकों से संबंध सिद्ध हुआ, (1) पुरुष होना, (2) हृदय रोग की आनुवंशिकता, (3) बढ़ती हुई आयु–ये हमारे नियंत्रण से बाहर के तीन घटक तथा (4) रक्त में बढ़ा हुआ कॉलेस्ट्रोल, (5) कम हो गया एचडीएल, (6) धूम्रपान, (7) मोटापा, (8) व्यायाम का अभाव, (9) मधुमेह एवं (10) बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर–ये पांच हमारे द्वारा नियंत्रित हो सकने वाले घटक. इन दोनों तरह के घटकों का हृदय रोग से कारण संबंध प्रस्थापित हो गया. मेडिकल खोजों में इस खोज को काफी ऊंचा स्थान दिया गया. (मैं और रानी फ्रामिंगहैम जाकर इसे देख आए हैं.) इन 5209 लोगों के बाल–बच्चे हुए. उन्हें भी इस अध्ययन में शामिल किया गया. अब तो उनके पोते–पोतियों का भी अध्ययन हो रहा है. तीन पीढ़ियों की जानकारी के कारण जीवनशैली के अतिरिक्त आनुवंशिकता का हृदय रोग से संबंध भी देखा जा सकता है. आज भी अध्ययन निरंतर जारी है. फ्रामिंगहैम स्टडी द्वारा मिली काफी जानकारी का उपयोग (आपकी हृदय रोग कुंडली) (प्रकरण 7.2) बनाने में किया गया है.

सेवन कंट्री स्टडी: अन्य देशों में हृदय रोग के क्या कारण हैं, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए फिनलैंड, इटली, ग्रीस, जापान, हॉलैंड, यूगोस्लाविया एवं अमेरिका आदि में यह सप्तदेशीय

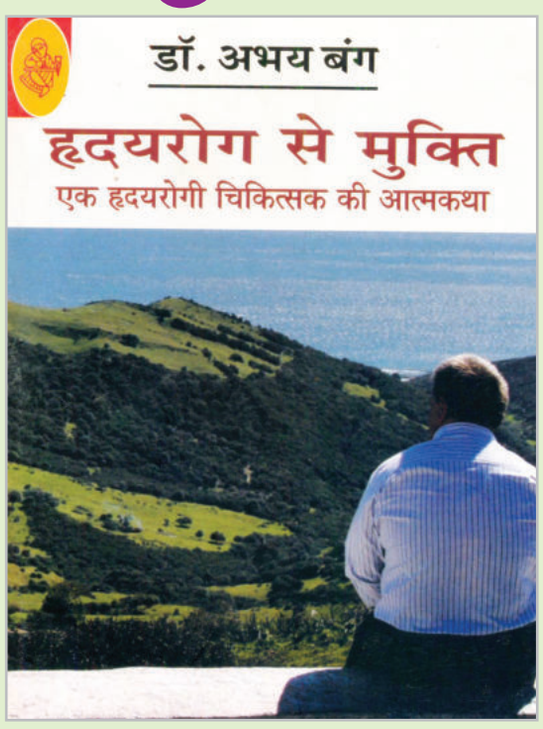

अध्ययन 1950–60 के दौरान प्रारंभ हुआ. इन सात देशों में भिन्न–भिन्न जीवनशैली के 12,000 मध्यम आयु के व्यक्तियों को अध्ययन के लिए चुना गया. अनेक दशकों तक यह अध्ययन चला. इससे ऐसा ज्ञात हुआ कि हृदय रोग होने का परिमाण फिनलैंड एवं अमेरिका में सबसे अधिक, तो जापान, इटली एवं ग्रीस में सबसे कम है. ग्रीस एवं इटली की जीवनशैली (मेडिटरेनियन लाइफ स्टाइल) को हृदय रोग से सुरक्षित मानकर उसके संरक्षक घटकों की खोज शुरू हुई.

रोजेटो स्टडी: अमेरिका के पेंसिलवेनिया प्रांत के रोजेटो शहर में बड़ी संख्या में इटली से लोग आकर बस गए थे. 1960 के आसपास तक इन लोगों ने आपसी प्रेम संबंध, मजबूत पारिवारिक रिश्तों एवं पारंपरिक इटालियन जीवनशैली को बरकरार रखा था. इसके भीतर वे सुरक्षित रहे. रोजेटो के गोरे इटालियंस और एक मील दूर के बैंगोर शहर के गोरे अमेरिकनों के हृदय रोग के परिमाण में खूब फर्क नज़र आया. इटालियन गोरों की हृदय रोग से सुरक्षा करने वाले कारण थे, आहार में आलिव ऑयल एवं मछली का उपयोग, पारिवारिक नाते–रिश्ते, सामूहिक जीवन की परंपरा, तनावरहित जीवन (नाचना, गाना, उन्मुक्त व्यवहार, काम का सारा तनाव भूलकर दोपहर के खाने के बाद एक झपकी). बोल्फ नामक एक वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की (या श्राप) कि समय के साथ रोजेटो के इन इटालियन लोगों का पारंपरिक, कौटम्बिक जीवन टूट जाएगा तथा वे भी तनावग्रस्त स्पर्धात्मक अमेरिकन बन जाएंगे और तब उनमें भी हृदय रोग बढ़ जाएगा. आने वाले 25 सालों में यही हुआ, रोजेटो तथा बैंगोर में हृदय रोग का अनुपात एक जैसा हो गया.

मायग्रण्ट स्टडीज: जापान में जापानियों को हृदय रोग बहुत कम होता था. क्या यह आनुवंशिक विशेषता थी? उनका अध्ययन करने पर पता चला कि अमेरिकन जीवनशैली अपनाने पर जापानियों में हृदय रोग का अनुपात बढ़कर करीब–करीब अमेरिकन लोगों जैसा ही हो गया. दीपक भटनागर एवं उनके सहकर्मियों द्वारा पंजाब और इंग्लैंड में किए गए अध्ययनों से ऐसा पता चला कि एक ही परिवार के जो लोग पंजाब के गांव में रह रहे थे, उनमें हृदय रोग का अनुपात कम था, लेकिन उन्हीं के जो भाई–बहन चंडीगढ़ अथवा ऐसे ही बड़े शहरों में रहने लगे अथवा इंग्लैंड में जा बसे, उन सबमें हृदय रोग का अनुपात बढ़ गया. इंग्लैंड में रहने वाले काले एवं गोरे लोगों से भी वह कहीं अधिक हो गया. अर्थ स्पष्ट था, ग्रामीण जीवनशैली अपनाए रहने तक ये भारतीय लोग सुरक्षित थे, लेकिन उनके शरीर में ऐसे कुछ ख़तरनाक जैविक घटक हैं कि वे चाहे भारत के किसी शहर में रहें अथवा इंग्लैंड में, वहां की जीवनशैली अपनाने पर यह ख़तरा एकदम उबर आता है. आप भारत में हैं अथवा इंग्लैंड में, यह महत्व नहीं रखता. कहीं भी रहें, सुशिक्षित, आरामवाली आधुनिक जीवनशैली ख़तरे की जननी है.

अलॉमेडिया स्टडी: बर्कमन एवं साइम ने इससे आगे का अध्ययन किया कैलिफोर्निया प्रांत के ॲलामेडिया काउंटी के 4775 गोरे अमेरिकन्स की विस्तृत जांच करके. उन्हें विवाह, रिश्तेदारी, मित्र, चर्च और अन्य सामाजिक समूहों में हिस्सेदारी आदि विविध सामाजिक संबंधों (सोशल नेटवर्क इंडेक्स) के आधार पर अंक दिए गए. नौ वर्ष बाद फिर से वहां जाकर उनमें मृत्यु का अनुपात देखा गया. सोशल नेटवर्क इंडेक्स के अनुसार, जिन्हें कम अंक मिले थे, वे अधिक अंक वालों की अपेक्षा दोगुनी संख्या में मरे थे. सामूहिक वृत्ति एवं जीवनशैली हमारे हृदय की रक्षा करती है. स्वार्थी, संकुचित, अकेलेपन की वृत्ति मृत्यु को जल्दी न्योता देती है.

स्पर्धात्मक बंदर: प्रयोगशाला में बंदरों के एक झुंड को भरपूर फैट आहार पर रखा गया. स्वाभाविक था कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहने से उन्हें हृदय रोग जल्दी होने की संभावना बढ़ गई. उसमें से आक्रामक, दादागीरी करने वाले बंदरों में से कुछ को उनके स्पर्धकों के साथ रखने की वजह से सतत तनाव में जीना पड़ा. उनके जैसे ही कुछ आक्रामक बंदरों को शांत, कलहमुक्त झुंड में रखा गया. आहार सबका समान ही रखा गया. 22 महीनों के बाद स्पर्धात्मक जीवन जीने वाले बंदरों में हृदय रोग का परिमाण दूसरे झुंड की अपेक्षा दोगुना था.(रजनीश की कुत्ते वाली कहानी वास्तव में सच निकली!) ■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

संयम का महत्व

दार्शनिकों ने इंद्रियों के संयम को जीवन की सफलता का प्रमुख साधन कहा है. मन पर नियंत्रण करके ही इंद्रिय संयम संभव है. वाणी का जितना हो सके, कम उपयोग करने में ही कल्याण है. वाणी पर संयम करने वाला किसी की निंदा के पाप, कटु वचन बोलकर शत्रु बनाने की आशंका, अभिमान जैसे दोषों से स्वत: बचा रहता है.

एक बार भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे एकाग्र चित्त बैठे हुए थे. उनसे द्वेष रखने वाला एक कुटिल व्यक्ति उधर से गुजरा. उसने वृक्ष के पास खड़े होकर बुद्ध के प्रति अपशब्दों का उच्चारण किया. बुद्ध मौन रहे. उन्हें शांत देखकर वह वापस लौट आया. रास्ते में उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा कि एक शांत बैठे साधु को गाली देने से क्या मिला? वह दूसरे दिन फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मैं कल अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूं. बुद्ध ने कहा, मैं कल जो था, आज वैसा नहीं हूं. तुम भी वैसे नहीं हो, क्योंकि जीवन प्रति पल बीत रहा है. नदी के एक ही पानी में दोबारा नहीं उतरा जा सकता. जब वापस उतरते हैं, तो वह पानी बहकर आगे चला जाता है. तुमने कल क्या कहा, मुझे नहीं मालूम और जब मैंने कुछ सुना ही नहीं, तो वे शब्द तुम्हारे पास वापस लौट गए. बुद्ध के शब्दों ने उसे सहज ही वाणी के संयम का महत्व बता दिया. ■

शिक्षा: किसी को बुरा–भला नहीं कहना चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

औद्योगिकीकरण, खनिजों के दोहन, बड़े–बड़े बांधों के निर्माण, शहरीकरण के नाम पर किसान, आदिवासी और दलितों के विस्थापन से जुड़े सवाल पर्यावरण विषय के सामाजिक पक्ष हैं. चूंकि यह संग्रह उत्तराखंड की त्रासदी का गवाह है इसलिए लेखक ने पहले लेख 'लोगों का गुस्सा बादल की तरह फटेगा' में इस भयावह त्रासदी की वजहों पर एक बहस पैदा करने की कोशिश है. बजली पैदा करने के नाम पर बड़े–बड़े बांध तो बनाए जा रहे हैं लेकिन बांध बनने से जो विस्थापन हो रहा है, उसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही बड़े–बड़े उद्योग घरानों के पास.

यौनिकता पर हो राष्ट्रीय बहस

अनंत विजय

अपनी आत्मकथा बियांड द लाइंस में कुलदीप नैयर ने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े कई बेहद दिलचस्प प्रसंग लिखे हैं. शास्त्री जी के सोवियत रूस के दौरे के दौरान उनके सम्मान में वहां की सरकार ने लेनिनग्राद में बैले नृत्य का आयोजन किया था. कुलदीप नैयर, लालबहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी ललिता शास्त्री नृत्य देखने पहुंचे. पूरे समारोह के दौरान शास्त्री जी बेहद असहज दिखे. नृत्य के बीच में शास्त्री जी से जब कुलदीप नैयर ने इसकी वजह जाननी चाही तो शास्त्री जी ने संकोच के साथ बताया कि वो इस वजह से असहज हैं कि नर्तकियों के पांव बहुत पर तक बगैर कपड़ों के और खुले हुए हैं . शास्त्री जी की दलील थी कि चूंकि उनकी पत्नी भी साथ बैठकर इस तरह का नृत्य देख रही हैं लिहाजा वो सहज नहीं महसूस कर रहे हैं . इसके अलावा एक और प्रसंग से सामाजिक स्थिति को समझने में मदद मिल सकती है. पंडित जवाहर लाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त ही नोबोकोब का मशहूर उपन्यास लोलिता का प्रकाशन हुआ था. तब लालबहादुर शास्त्री ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर लोलिता को भारत में प्रतिबंधित करने की वकालत की थी. शास्त्री के पत्र के जवाब में नेहरू जी ने एक लंबा पत्र लिखा और लोलिता को देश में प्रतिबंधित करने से मना कर दिया. नेहरू तो अपने खत में एक और कदम आगे चले गए और सलाह दी कि डी एच लॉरेंस का उपन्यास– लेडी चैटर्लीज लवर– भी पाठकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए. तो ये दो तरह की धारा साफ तौर पर देखी जा सकती है. कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा में शास्त्री जी को रूढ़िवादी करार दिया है. अब भी स्त्री देह के सार्वजनिक प्रदर्शन और साहित्य में यौनिकता का खुला वर्णन आलोच्य है. हिंदी साहित्य में तो यौनिकता को लेकर बहस ही छिड़ी हुई है. कामसूत्र के रचियता वात्सयायन के देश में लोग यौनिकता पर बात करने में परहेज करने लगे हैं. कालिदास की कृतियों में जिस तरह की सेंसुअलिटी है वो विश्व की किसी भी भाषा की श्रेष्ठ कृतियों को टक्कर दे सकती है. खैर यह एक अवांतर प्रसंग और यह विषय विस्तार से विमर्श की मांग करता है. इस पर फिर कभी चर्चा होगी.

बैले नृत्य में शास्त्री जी की असहजता उस भारतीय मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है जो स्त्री देह के सार्वजनिक प्रदर्शन को अश्लीलता मानता रहा है. हमारे देश में लंबे समय से चली आ रही यही मानसिकता हमारी फिल्मों में भी प्रदर्शित होती रही है. वक्त बदलने के साथ साथ फिल्मों में खुलापन आने लगा. लेकिन सेंसर बोर्ड ने कुछ वर्जनाओं को कायम रखा. भारत में प्रदर्शित होनेवाली फिल्मों में चुंबन दृश्यों को तो आधुनिकता के नाम पर मंजूरी मिलनी शुरू हो गई लेकिन कामक्रीडा को दर्शाने की इजाजत अभी भी नहीं है. कम कपड़ों में या फिर पारदर्शी कपड़ों में कहानी की मांग के नाम पर कुछ निर्देशक छूट लेते रहे हैं. राजकपूर ने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली में बड़े गले के या फिर पारदर्शी कपड़ों में नायिकाओं को दिखाने की छूट सेंसर बोर्ड से हासिल कर ली थी. उस वक्त माना गया था कि निर्देशकों ने इस तरह के दृश्य को दिखाकर दर्शकों में उद्दीपन पैदा करने की कोशिश की है. इसी तरह जब 1973 में बी.के आदर्श ने गुप्त ज्ञान नाम की फिल्म बनाई थी तो सेंसर बोर्ड के सामने धर्मसंकट खड़ा हो गया था. उस फिल्म में कई दृश्य ऐसे थे जिनको लेकर निर्माताओं की दलील थी कि वो यौनिकता को लेकर जनता को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से फिल्म में डाली गए हैं . लेकिन बोर्ड के कई सदस्यों को लग रहा था कि ये जनता की यौन भावनाओं को भड़का कर पैसा कमाने की एक चाल है. लंबी बहस के बाद गुप्त ज्ञान को बगैर किसी काट–छांट के प्रदर्शन की इजाजत मिल गई. सिनेमाघरों में प्रदर्शन के बाद उस फिल्म के अंतरंग दृश्यों को लेकर बवाल बढ़ा तो चंद महीनों के भीतर उसको वापस लेना पड़ा था. सेंसर बोर्ड के सदस्यों ने एक बार फिर से फिल्म गुप्त ज्ञान को देखा और उसपर जमकर कैंची चलाने के बाद ही प्रदर्शन की इजाजत मिली. 1974 में अपने प्रदर्शन के चंद महीनों में वापस ली गई ये फिल्म 1977 में सिनेमाघरों में पहुंच पाई. भारतीय सिनेमा में चाहे कितना भी खुलापन आ जाए नग्नता को अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है चाहे वो आंशिक ही क्यों ना हो? 1994 में फूलन देवी की जिंदगी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन में भी स्त्री देह की नग्नता को लांग शॉट में ही दिखाने की इजाजत दी गई थी.

इतने सालों बाद अब लगता है कि भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड में खुलेपन की बयार बहने लगी है. 2013 में बनी विदेशी फिल्म– 12 इयर्स अ स्लेव – को भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शन की इजाजत मिली तो स्त्री देह की नग्नता को दिखाने की मंजूरी के साथ. ऐतिहासिकता को केंद्र में रखकर बनाई गई स्टीव मैक्वीन की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने वयस्क फिल्म का प्रमाण पत्र दिया है. हमारे यहां वयस्क फिल्मों में भी स्त्री के शरीर के ऊपरी हिस्से को पूर्ण रूप से नग्न दिखाने पर एक रोक है. इस फिल्म में इस तरह के दृश्यों की इजाजत के पीछे तर्क वही है कि गुलामों पर बर्बर अत्याचार के दौरान उनको सार्वजनिक तौर पर नंगा करके जलील किया जाता था. निर्देशक का तर्क है कि इस तरह के दृश्य फिल्म की मांग हैं. सेंसर बोर्ड पूर्व में इस तरह के तर्कों को खारिज करता रहा है. विदेशी फिल्मों पर भी उसकी कैंची चलती रही है लेकिन 12 इयर्स अ स्लेव में गुलामों के अत्याचार के नाम पर इस तरह के दृश्यों की इजाजत देना हैरान करनेवाला है. यहां सवाल यह उठता है कि क्या हमारा समाज इस तरह के दृश्यों को देखने और उसको सही परिपेक्ष्य में समझने के लिए परिपक्व हो चुका है? हमारी सामाजिक संरचना और समाज को प्रतिबिंबित करनेवाले मानदंड तो यह बताते हैं कि हमारा समाज इतने खुलेपन के लिए अभी तैयार नहीं है. समाज में शिक्षा की स्थिति, महिलाओं को लेकर सामाजिक वर्जनाएं और फिर यौनिकता को समझ नहीं पाने से पैदा हुई कुंठा इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत का समाज अभी फिल्मों में स्त्री देह के आंशिक रूप से नग्न प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं है. कई समाज विज्ञानियों की तो दलील है कि फिल्मों में इस तरह के दृश्यों और अशिक्षा के मेल से जो मानसिकता बनती है वो स्त्रियों के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देती है. कई ऐसे मामले सामने भी आए हैं जब स्त्रियों के खिलाफ होनेवाले अपराध के पीछे इस तरह की वजहें सामने आई हैं. सेंसर बोर्ड को इस तरह के खुलेपन और नग्नता के सार्वजनिक प्रदर्शन के पहले समाजिक संरचना को भी ध्यान में रखना चाहिए. फिल्मों में इजाजत के बाद अब तो टेलीविजन पर भी देर रात एक खास वक्त और टाइम बैंड पर वयस्क फिल्मों और वयस्क कार्यक्रमों को दिखाने के लिए मुहिम शुरू हो गई है. हमारा मानना है कि इस तरह के फैसले के पहले एक राष्ट्रव्यापी बहस की जानी चाहिए ताकि पूरे देश की सहमति हासिल हो सके. चंद लोगों की कमेटी को कमरों में बैठकर इस तरह सार्वजनिक रूप से नग्नता के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है. ■

बैले नृत्य में शास्त्री जी की असहजता उस भारतीय मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है जो स्त्री देह के सार्वजनिक प्रदर्शन को अश्लीलता मानता रहा है. हमारे देश में लंबे समय से चली आ रही यही मानसिकता हमारी फिल्मों में भी प्रदर्शित होती रही है. वक्त बदलने के साथ साथ फिल्मों में खुलापन आने लगा. लेकिन सेंसर बोर्ड ने कुछ वर्जनाओं को कायम रखा. भारत में प्रदर्शित होनेवाली फिल्मों में चुंबन दृश्यों को तो आधुनिकता के नाम पर मंजूरी मिलनी शुरू हो गई लेकिन कामक्रीडा को दर्शाने की इजाजत अभी भी नहीं

(लेखक आईबीएन–7 में डिप्टी एडिटर हैं)

anant.ibn@gmail.com

कविताएं

शबनम खान

तू सिर्फ इंसान है

पैदाइश के फौरन बाद
मैं खुद ब खुद हिस्सा हो गई
कुल आबादी के
आधे कहलाने वाले
एक संघर्षशील समुदाय का,
कानों से गुज़रती
हर एक महीन से महीन आवाज़
ये एहसास दिलाती रही
तुझे कुछ सब्र रखना होगा
कुछ और सहना होगा
कुछ और लड़ना होगा..
और दिल से आती
हर ख़ामोश सदा ने कहा,
नहीं! तुझे नहीं बदलना
बिगड़ा नज़रिया किसी बेअक़्ल का
तुझे नहीं बनानी नई दुनिया
अपने समुदाय विशेष के लिए
और न ही
तुझे करना है साबित
किसी को कुछ भी..
इस ज़िंदगी में इक काम बस
तुझे करना होगा
अपने लिए
हां, सिर्फ अपने लिए
एक छोटा सा काम
तुझे सीखना होगा
पैदाइश के उस पाठ को भूलना
जो तुझे सबसे पहले पढ़ाया गया था
कि तू लड़की है
स्त्री है, औरत है
ज़िम्मेदारी है, कभी बोझ है कभी खुशी है
कभी गुड़िया कभी देवी भी है..
तुझे सीखना होगा खुदको
सिर्फ और सिर्फ
एक इंसान समझना.

अपने हिस्से का प्यार

चांद तारों की महफिल लगने से
आसमान में सूरज लहराने तक
बादल के आखिरी टुकड़े से
बारिश की हर बूंद निचुड़ जाने तक
घर के बाहर लगे गुलाब के पौधे में
एक नया फूल उग के सूख जाने तक
सड़क पर लगे गाड़ियों के मजमे से
उसके ख़ामोश सुनसान हो जाने तक
चूड़ियों की सजी खनखनाहट से
ड्राउर के लकड़ी के केस में रखे जाने तक
करीने से बनी ज़ुल्फों के
कंधों पर बिखर जाने तक
सुबह जैसी चमकती आखों में
रात का अंधेरा पसर जाने तक
मैंने कर लिया तेरा इंतज़ार
मैंने कर लिया, अपने हिस्से का प्यार

तेरी सांसों में कैद मेरे लम्हे

वो लम्हे
तेरी सांसों में क़ैद
जो मेरे थे
सिर्फ मेरे,
जिनमें नहीं थी
मसरूफियत ज़माने की
रोज़ी–रोटी कमाने की
और
जिसमें नहीं थी
कोई रस्म दिखावे की,
कहां गुम गए
सभी, एकदम से
एकसाथ..
क्या सच है
बुज़ुर्गो की वो बात
जो कहते हैं
कुछ मिल जाने के बाद
उसकी चाह
होने लगती है ख़त्म,
या फिर
ये एक वहम ही है
जैसा
हमेशा कहते हो तुम
लेकिन फिर भी,
मैं अक्सर
दिन के किसी उदास पल में
उन लम्हों को
याद करती हूं
जो मेरे थे
सिर्फ मेरे
तुम्हारी सांसों में क़ैद
मेरे लम्हें..!

khanshab.369@gmail.com

किताब मिली

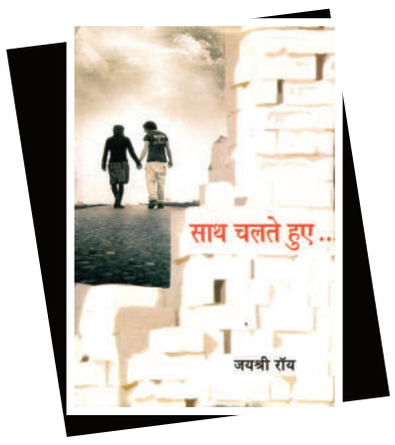

पुस्तक	लेखक
साथ चलते हुए...	जयश्री रॉय
प्रकाशक	**मूल्य**
सामयिक बुक्स, नई दिल्ली	250 रुपये

युवा कथाकार जयश्री रॉय का यह उपन्यास अपर्णा के साथ–साथ एक ऐसी कथा से जोड़ता है जहां स्त्री का दुख स्त्री ही समझ पाती है. जहां मां की तकलीफ उसी के साथ, उसके भीतर बजती रहती है. जहां पुरुष अपने सामंती रूप में मौजूद है और संबंध की आत्मीयता को पल भर में झटक किसी दूसरी स्त्री का साथ अपना सकता है. यहां उदासी भीतर से बाहर और बाहर से भीतर भाषा में सफर करती है. यह किसी सहज, सरल, निश्चिंत चरित्र की कहानी नहीं है. प्रश्नाकुल आत्मा का संघर्ष है जिसके कौशल का साथ मिलता है तो उत्तर भी आने लगते हैं. ऐसे में भावुकता की जगह सच की भाषा सामने हो आती है. व्यक्ति से समाज की कथा बनाने का यह अंदाज ही युवा रचनाकार जयश्री रॉय को बड़ा बनाता है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई–मेलः feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक समीक्षा

पर्यावरण ही नहीं मानव जीवन भी हो रहा तबाह

अमित चमड़िया

पर्यावरण का संतुलन मानव जाति के विकास से जुड़ा हुआ है. भारत से पर्यावरण और इससे जुड़े मुद्दे स्कूल और कॉलेज में विज्ञान की किताबों तक ही सीमित रह गए हैं. इन्हें सामाजिक संदर्भो से जोड़ने के कोई खास प्रयास नहीं दिखते हैं. किसी भी विषय की उपयोगिता इसकी सामाजिक उपयोगिता में निहित है इसलिए पर्यावरण विषय को सामाजिक संदर्भो में देखने की ज्यादा आवश्यकता है. स्वतंत्र मिश्र द्वारा लिखित किताब 'जल जंगल और जमीन : उलट–पुलट पर्यावरण' इस दृष्टिकोण से एक सार्थक कोशिश है. इस पुस्तक द्वारा पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणाम को सामाजिक परिपेक्ष्य में देखने की कोशिश की गई है. लेखक यह बार–बार गंभीरतापूर्वक लिखते हैं कि कैसे नवउदारवाद के दौर में पूंजीवादी मॉडल का विकास पर्यावरण संतुलन के लिए घातक साबित हो रहा है. किताब में संकलित कुल 43 लेख लेखक के जनपक्षीय विचारों के साथ खड़े होने का प्रमाण देते हैं. पर्यावरण का संबंध केवल जल, जमीन और वायु के दूषित होने भर का मामला नहीं है. औद्योगिकीकरण, खनिजों के दोहन, बड़े–बड़े बांधों के निर्माण, शहरीकरण के नाम पर किसान, आदिवासी और दलितों के विस्थापन से जुड़े सवाल पर्यावरण विषय के सामाजिक पक्ष हैं. चूंकि यह संग्रह उत्तराखंड की त्रासदी का गवाह है इसलिए लेखक ने पहले लेख 'लोगों का गुस्सा बादल की तरह फटेगा' में इस भयावह त्रासदी की वजहों पर एक बहस पैदा करने की कोशिश है. बजली पैदा करने के नाम पर बड़े–बड़े बांध तो बनाए जा रहे हैं लेकिन बांध बनने से जो विस्थापन हो रहा है, उसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही बड़े–बड़े उद्योग घरानों के पास. लेखक तथ्यों एवं आंकड़ों की सहायता से अपनी बात को प्रमाणिकता भी देते हैं. वैचारिक स्पष्टता और सहज भाषा इस पुस्तक को सामाजिक सरोकार से जोड़ने में मदद करती है. पानी, प्रकृति का एक उत्पाद है. हमारे पूर्वजों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि पानी से लबालब धरती पर भी पानी भी खरीद कर पीना पड़ सकता है. तकनीकी विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन का दोहन किया जा रहा है इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं. सिंगूर, नंदीग्राम आदि प्रकरणों पर लिखे गए विभिन्न लेखों – 'उदारीकरण में 'उदारता' किसके लिए', 'पुनर्वास की हो राष्ट्रीय नीति', 'कहां जाएं किसान' आदि के माध्यम से स्वतंत्र वामपंथी पार्टियों के विरोधाभासी चरित्र को भी उजागर करते हैं. इस पुस्तक में पर्यावरण एवं उससे जुड़े मुद्दे को व्यापक फलक में देखने की कोशिश की गई है. स्वतंत्र एक लेख में लिखते हैं–'बड़ी परियोजनाओं की प्रस्तावना में योजनाकार हमेशा बड़े सपने दिखाने की कोशिश करते हैं जबकि वे लंबे दौर में बेरोजगारी, विस्थापन, प्रदूषण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म देनेवाले साबित हुए हैं.' सरकार की तमाम नीतियां जो जल, जंगल और जमीन से जुड़ी हुई हैं वह जनविरोधी होने के साथ–साथ पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है. चाहे मामला सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) का हो या वन संरक्षण के नाम पर रिजर्व पार्क या वन अभ्यारण्य बनाने का. संक्रमित बीज एवं खास प्रकार के कीटनाशक को बढ़ावा देने की योजना हो या बड़ी–बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित आयोडीनयुक्त नमक को बिकवाने की. इस सब मामलों में सरकार की नीयत साफ दिखाई देती है. सरकार की इन जनविरोधी नीतियों के आरोप को स्वतंत्र तथ्य एवं तर्कों के आधार पर पुष्ट करते हैं. 'पुनर्वास के नाम पर एक 'नई' आस' लेख में इस बात का जिक्र है कि 'आजादी के बाद से लेकर आजतक केवल बांध बनाने के नाम पर लगभग चार करोड़ लोग उजाड़े जा चुके हैं. सभी को समझना होगा कि विस्थापन के साथ वहां की भाषा, आबोहवा और कुल मिलाकर पूरी संस्कृति तहस–नहस हो जाती है. स्वतंत्र जनपक्षीय तरीके से मुद्दों पर अपनी पैनी नजर रखने के सुबूत 'साधारण नमक बचाने के लिए' और 'सरकारी उपेक्षा के शिकार रिक्शे' आदि लेखों के माध्यम से देते हैं और इन मुद्दों को भी पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करते हैं. साधारण नमक का आम आदमी की पहुंच से बाहर होने की तथा आयोडीन युक्त नमक का भार आम आदमी पर थोपने की चिंता को लेखक अपने चिंतन से जोड़ते हैं. नदी जोड़ो परियोजना की आलोचना करते हुए स्वतंत्र लिखते हैं, 'बाढ़ का प्रबंधन नदी–जोड़ो' से हो सकता है या नहीं इसमें सच या झूठ खोजने की जरूरत नहीं है. लोगों में उतावलापन होता है कि हम अपने समय में सब ठीक करके जाएं परंतु प्रकृति का कैलेंडर हमारे कैलेंडर से मेल नहीं खाता. नदियां हजारों–लाखों साल में अपना रास्ता बनाती हैं. उन्हें जब अपने को जोड़ना होता है, वह जोड़ लेती है इसलिए नदी को जोड़ने–तोड़ने का काम प्रकृति पर ही छोड़ देना चाहिए.' लेखों के प्रकाशन के वर्ष का जिक्र किसी भी लेख के अंत में नहीं किया गया है, जो पाठकों को परेशान कर सकती है. हालांकि लेखक ने अपनी किताब की भूमिका में यह संकेत दिया कि है कि इन्होंने पिछले एक दशक के दौरान अलग–अलग अखबारों और पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को ही किताब में जगह दी है. कई लेखों में मुद्दों की पुनरावृत्ति भी दिखाई देती है लेकिन इसके बावजूद पर्यावरण को साामाजिक परिपेक्ष्य में समझने के लिए यह एक उपयोगी पुस्तक साबित होगी. ■

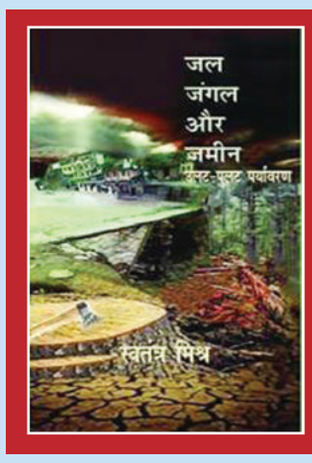

पुस्तक :	जल जंगल और जमीन : उलट–पुलट पर्यावरण
लेखक :	स्वतंत्र मिश्र
प्रकाशक :	स्वराज प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली
मूल्य :	295 रुपये

इस टैब में किड्स राडार नामक एप्प है, जो बच्चों के लिए उपयुक्त सर्च इंजन है. इस टैबलेट में पैरेंट्स बच्चों के लिए टाइम भी सेट कर सकते और साथ ही विषय भी, ताकि बच्चे कितने समय तक टैबलेट का उपयोग करें और किस विषय पर ज्यादा फोकस करें, यह उनके माता–पिता को निश्चित कर सके. 1024 गुणा 600 पिक्सल रेज्योलूशन वाले इस 7 इंची स्क्रीन के टैबलेट में 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है.

अब डीजल वाली बाइक

बाइक की ख़ासियत: बाइक को ख़ास तौर पर कस्बों और देहात की ज़रूरतों को देखते हुए डिजाइन किया है.

-150 सीसी क्षमता है बाइक की.
-70 किमी प्रति घंटा होगी अधिकतम स्पीड.

देश में दोपहिया वाहनों की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी 150 सीसी की डीजल कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल पेश की है. इसके अलावा कंपनी ने चार अन्य मॉडल पेश किए हैं, जिनमें एक स्कूटर भी शामिल है. कंपनी हीरो लीप नामक स्कूटर बाज़ार में उतारेगी. यह स्कूटर 2012 के एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था. पेट्रोल आधारित इस स्कूटर की इंजन क्षमता 125 सीसी है और इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है. हीरो ने 250 सीसी की लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल एचएक्स–20आर लांच की है. हीरो आरएनटी कंसेप्ट में 150 सीसी डीजल इंजन है, जो इसे 13.5 पीएस का पावर देता है. यह ऐसी पहली बाइक होगी, जिसमें 2 इंजन होंगे यानी 150 सीसी का पावरफुल डीजल इंजन एवं इलेक्ट्रिक इंजन. डीजल मॉडल आरएनटी को छोड़कर कंपनी अन्य चार मॉडलों को अगले वित्तीय वर्ष में पेश करेगी. हीरो ने डैश नामक स्कूटर लांच किया है, जिसका लुक मैजिस्ट्रो की तरह है. डैश में 111 सीसी का इंजन लगा है, जो इसे 8.5 का पावर देता है. इसमें 6 लीटर का फ्यूल टैंक है. इसके अलावा, मोबाइल चार्जिंग शॉकिट भी है. कंपनी का कहना है कि वह 2014 के ऑटो एक्सपो में अपने और अधिक प्रॉडक्ट्स लाएगी. ■

सुजुकी का 110 सीसी स्कूटर

टीवीएस से अलग होने के बाद जापानी टू व्हीलर कंपनी सुजुकी बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की लगातार कोशिश में है. इसके चलते कंपनी ने ऑटो एक्सपो से पहले ही भारतीय बाज़ार में अपने दो नए प्रोडक्ट्स पेश किए हैं. कंपनी ने एक तरफ़ 155 सीसी इंजन क्षमता वाली गिक्सर बाइक पेश की है और दूसरी तरफ़ 110 सीसी का लेट्स स्कूटर. सुजुकी लेट्स 110 सीसी स्कूटर बॉलीवुड की अभिनेत्री परिणिति चोपड़ा ने पेश किया, जिन्हें सुजुकी ने अपना ब्रांड एंबेसडर चुना है. सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अतुल गुप्ता का कहना है कि कंपनी भारतीय ग्राहकों को हर प्राइस रेंज में प्रॉडक्ट देना चाहती है. सुजुकी लेट्स की क़ीमत का खुलासा ऑटो एक्सपो में किया जाएगा, जहां पर कंपनी यह स्कूटर पेश करेगी. सुजुकी लेट्स में 112.8 सीसी, 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 63 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है. सुजुकी लेट्स के फ्यूल टैंक में 5.2 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता है. ■

डेल के नए टैबलेट

यह टैबलेट भी एंड्रॉयड 4.2 जेलीबीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. कैमरा फीचर्स वेन्यू–8 में ज़्यादा अच्छे हैं. 5 मेगा पिक्सल के रियर कैमरे के साथ इस टैबलेट में 1080 पिक्सल पावर की रिकॉर्डिंग होती है. साथ ही 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है. 17499 रुपये की रेंज में यह टैबलेट महंगा नहीं है. इसमें 4100 एमएच की बैटरी, 3जी, वाई–फाई, ब्लूटूथ एवं जीपीएस हैं. डेल के ये दोनों टैबलेट जल्द ही बाज़ार में आएंगे.

भारत में लगातार आ रहे स्मार्ट फोन और टैबलेट के बाज़ार में नई कंपनियां अपने हाथ आजमा रही हैं. अपने लैपटॉप एवं कंप्यूटर के लिए लोकप्रिय कंपनी डेल ने भी भारत में 4 नए टैबलेट लॉन्च किए हैं. गौरतलब है कि अमेरिकी कंपनी डेल ने पहली बार भारत में ऐसा कोई गैजेट लॉन्च किया है. वेन्यू सीरीज के टैबलेट पहले से ही अमेरिका एवं बाकी देशों में लोकप्रिय हैं. भारत में लॉन्च हुए इन टैबलेट्स में से दो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं और दो एंड्रॉयड पर.

विंडोज: विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले वेन्यू–8 प्रो और वेन्यू–11 प्रो टैबलेट हाई बजट रेंज में होंगे. इनमें से वेन्यू–8 प्रो की क़ीमत 26,499 रुपये है और वेन्यू–11 प्रो की क़ीमत के बारे में अभी तक बताया नहीं गया है.

एंड्रॉयड: इंटेल के एटम प्रोसेसर पर काम करने वाले ये दोनों टैबलेट मीडियम बजट रेंज में लॉन्च किए गए हैं. इन दोनों टैबलेट के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा कंपनी ने कर दी है. वेन्यू–7 और वेन्यू–8 नामक इन टैबलेट्स की क़ीमत 10,999 और 17,499 रुपये है. गौरतलब है कि डेल के लैपटॉप भारत में पहले से ही काफी लोकप्रिय हैं. ऐसे में, ब्रांड के कारण हो सकता है कि ये टैबलेट्स भी भारतीय बाज़ार में सफल साबित हों. इंटेल का पावर प्रोसेसर होने के कारण इन टैबलेट्स से अच्छे रिस्पांस की उम्मीद की जा सकती है. खास बात यह कि डेल के ये टैबलेट्स गूगल के नेक्सस–7 को सीधी टक्कर दे सकते हैं. वेन्यू–7 टैबलेट 11000 रुपये की रेंज में मिलेगा. इसमें 7 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन है, जो 1200 गुना 800 मेगा पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इस टैबलेट में 1.6 जीएचजेड का इंटेल एटम जेड 2760 डुअल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसी के साथ टैबलेट में 2 जीबी रैम है. डेल का यह टैबलेट आजकल आ रहे क्वाड–कोर प्रोसेसर से भले ही कम लगे, लेकिन पावर फीचर्स इस टैबलेट में अच्छे हैं. 2 जीबी रैम गेमिंग के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है. 3 मेगा पिक्सल के रियर कैमरे के साथ इस टैबलेट में वीजी फ्रंट कैमरा भी है. 16 जीबी इंटरनल मेमोरी के साथ इस टैबलेट की मेमोरी कार्ड के जरिए 32 जीबी तक बढ़ाई जा सकती है. वेन्यू–7 में 4100 एमएच की बैटरी है, जो 10 घंटों का एचडी वीडियो प्लेबैक टॉकटाइम देती है. इस टैबलेट में वाई–फाई, ब्लूटूथ एवं जीपीएस जैसे फीचर्स हैं. इसी के साथ एंड्रॉयड 4.2 जेलीबीन ऑपरेटिंग सिस्टम है. वेन्यू–8 में 8 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन के साथ 1200 गुना 800 मेगा पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है. वेन्यू–7 की तरह इंटेल एटम जेड 2760 डुअल कोर प्रोसेसर के साथ आता है, जिसका पावर 1.6 जीएचजेड का है. इसी के साथ 2 जीबी रैम भी है.

यह टैबलेट भी एंड्रॉयड 4.2 जेलीबीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. कैमरा फीचर्स वेन्यू–8 में ज़्यादा अच्छे हैं. 5 मेगा पिक्सल के रियर कैमरे के साथ इस टैबलेट में 1080 पिक्सल पावर की रिकॉर्डिंग होती है. साथ ही 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है. 17499 रुपये की रेंज में यह टैबलेट महंगा नहीं है. इसमें 4100 एमएच की बैटरी, 3जी, वाई–फाई, ब्लूटूथ एवं जीपीएस हैं. डेल के ये दोनों टैबलेट जल्द ही बाज़ार में आएंगे. उम्मीद की जा रही है कि वेन्यू–8 प्रो का 64 जीबी वाला वर्जन भी उपलब्ध होगा. 5 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ इस टैबलेट में 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है. 1920 गुना 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन और 10 फिंगर मल्टीटच सपोर्ट के साथ यह टैबलेट लॉन्च हुए चारों टैबलेट्स में सबसे ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ है. पावर के मामले में इसमें 2.4 जीएचजेड का इंटेल एटम प्रोसेसर है. यह 64 जीबी इंटरनल मेमोरी देता है. 8 मेगापिक्सल के रियर कैमरे के साथ इसमें 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. वाई–फाई, ब्लूटूथ, यूएसबी 3.0 एवं एचडीएमआई पोर्ट के साथ–साथ इसमें कई तरह के कनेक्टिविटी विकल्प मौजूद हैं. इस टैबलेट की बैटरी 8 से 10 घंटों का टॉकटाइम देती है. ■

फेसबुक का न्यूजपेपर ऐप

फेसबुक ने एक नया ऐप पेपर लॉन्च किया है. यह ऐप स्मार्टफोन पर आर्टिकल्स एवं दूसरे कॉन्टेंट देखने और शेयर करने के लिए ऑनलाइन न्यूजपेपर की तरह काम करेगा. फेसबुक ने इस सर्विस के बारे में कहा है कि शानदार डिजाइन, फुलस्क्रीन और सरल लेआउट के साथ पेपर स्टोरीटेलिंग को खूबसूरत बनाएगा. फेसबुक क्रिएटिव लैब्स का यह पहला प्रॉडक्ट आईओएस पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. बाद में इसके एंड्रॉयड पर भी आने की उम्मीद है. पेपर स्टोरीज और थीम्ड सेक्शंस देगा, जिसमें लोग न्यूज हेडलाइंस, फूड, स्पोर्ट्स और साइंस जैसे कई टॉपिक चुन सकते हैं. इसका डिजाइन टाइल्स की तरह बनाया गया है, जिसमें यूजर पर्सनल फेसबुक फीड पाने के लिए डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हैं. हर सेक्शन में जाने–माने लोगों और पब्लिकेशंस से मिला–जुला कॉन्टेंट रहेगा. फेसबुक के वीडियो में इस ऐप पर द न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स मैगजीन, यूएसए टुडे, द हफिंगटन पोस्ट का कॉन्टेंट दिख रहा है. फेसबुक ने कहा, सब कुछ आपके टच से होगा. आप हाई–रेज्योलूशन पनोरमिक फोटो देखने के लिए अपना फोन घुमा सकते हैं. इसमें आपको फोटो में डीटेल एक कोने से दूसरे कोने तक साफ़ दिखेगी. ऐप में वीडियो को फुलस्क्रीन पर देखा जा सकेगा. जब आप कुछ कहना चाहेंगे, तो पहले ही जान सकेंगे कि आपकी पोस्ट या फोटो कैसे दिखाई देंगी, क्योंकि आप शेयर करने से पहले लाइव प्रिव्यू कर सकते हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

चैट ऐप मिक्सिट भारत में लॉन्च

साउथ अफ्रीका की सबसे लोकप्रिय मेसेजिंग सर्विस मिक्सिट भारत में लॉन्च हो गई है. मेसेजिंग ऐप्स की भीड़ में इसकी कुछ खूबियां हैं, जो इसे औरों से अलग बनाती हैं. मसलन आप इसे किसी भी साधारण फीचर फोन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, भले ही वह साधारण 2जी हो. यानी फीचर फोन पर भी स्मार्टफोन का फायदा ले सकते हैं. अभी यह अंग्रेजी और हिंदी में है. 6 महीनों के भीतर इसमें 10 अन्य भारतीय भाषाएं शामिल की जाएंगी.

मिक्सिट के इंडिया सीईओ सैम रूफस नल्लराज ने कहा कि वह इसे फीचर फोन कैटेगरी पर खास तौर से टारगेट करेंगे. यह 8000 तरह के फोन पर चल सकता है. इस फ्री ऐप के अंदर भी कई तरह के ऐप हैं, जिनमें एजुकेशन से लेकर काउंसलिंग जैसी खासियतें शामिल होंगी. इसके लिए कई एनजीओ से बात चल रही है. इसमें ग्रुप चैट के अलावा अलग–अलग टॉपिक पर डिस्कशन रूम हैं. साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एवं दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच गैरी कर्स्टन इसके ब्रैंड एम्बेसडर हैं और वह भी इस पर क्रिकेट टिप्स देंगे. वॉट्स ऐप की तरह एड्रेस बुक इंटिग्रेशन फीचर भी है. वॉइस मेसेजिंग अभी ऐपल वर्जन में है, जल्द ही औरों में भी आएगा. ■

बच्चों के लिए नया एजुकेशनल टैबलेट

मेटिस ने बच्चों के लिए बाज़ार में एजुकेशनल टैबलेट उतारने की योजना बनाई है, जिसका नाम एड्डी रखा गया है. यह टैबलेट चीन में बनाया गया है, जो 2 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है. 9,999 रुपये में मिलने वाले टैबलेट एड्डी में काफी ऐसे कंटेंट डाले गए हैं, जो बच्चों को कुछ न कुछ सीखने में मदद करेंगे. कंपनी के अनुसार, इस टैबलेट में ऐसे करीब 150 गेम्स हैं, जो बच्चों को सीखने में मदद करेंगे और इसे स्कूल के सिलेबस से भी जोड़ा गया है. बच्चे इस पर गेम खेल सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और दुनिया को जान–समझ सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर से पैरेंट्स इसमें अतिरिक्त एप्प भी जोड़ सकते हैं. इस टैब में किड्स राडार नामक एप्प है, जो बच्चों के लिए उपयुक्त सर्च इंजन है. इस टैबलेट में पैरेंट्स बच्चों के लिए टाइम भी सेट कर सकते और साथ ही विषय भी, ताकि बच्चे कितने समय तक टैबलेट का उपयोग करें और किस विषय पर ज्यादा फोकस करें, यह उनके माता–पिता को निश्चित कर सके. 1024 गुणा 600 पिक्सल रेज्योलूशन वाले इस 7 इंची स्क्रीन के टैबलेट में 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है. इसमें 3200 एमएएच की बैटरी भी है, जो एक फुल चार्ज पर 4 घंटे का टॉकटाइम देने का दावा करती है. इसमें 1.6 जीएचजेड डुअल कोर प्रोसेसर, 1 जीबी रैम और एंड्रायड 4.2 जेली बिन ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसमें 8 जीबी की इंटरनल मेमोरी है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के सहारे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. भारतीय बाज़ार में बच्चों के लिए इंटेल भी इसी प्रकार का गेम प्ले लांच करने की कोशिश कर रहा है, वहीं चिप मेकर ने भी इसी तरह का एंड्रायड आधारित एजुकेशन टैबलेट विद्यार्थियों के लिए लांच किया है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

आईसीसी का केंद्रीकरण

एक ओर दुनिया भर में जहां सत्ता के विकेंद्रीकरण की हवा चल रही है. उसके ठीक उलट आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) सत्ता के केंद्रीकरण की ओर जा रही है. आईसीसी की कार्यकारिणी में व्यापक पैमाने पर बदलाव प्रस्तावित हैं, जिनके मूर्त रूप लेने पर वैश्विक क्रिकेट में प्रमुख निर्णय लेने का अधिकार भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे धनी क्रिकेट बोर्डों के बीच केंद्रित हो जाएगा. इसके बाद अन्य देशों की विश्व क्रिकेट के संचालन में क्या भूमिका होगी, यह बड़ा सवाल है. क्या ये बदलाव क्रिकेट के हित में होंगे?

नवीन चौहान

आजकल आईसीसी में बदलाव की बयार चल रही है. आईसीसी के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे में व्यापक पैमाने पर बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है. इसे लेकर दुनिया भर के देशों के बीच खींचतान चल रही है. इन बदलावों के मूर्त रूप लेने पर विश्व क्रिकेट में फैसले लेने के अधिकांश अधिकार वित्तीय रूप से सुदृढ़ भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों में आ जाएंगे और क्रिकेट जगत में इन तीन देशों का दखल बढ़ जाएगा. इसके बाद अधिकांश मामलों में इनकी भूमिका निर्णायक होगी. इस प्रस्ताव को लेकर टेस्ट खेलने वाले देश दो धड़ों में बट गए हैं. दोनों धड़ों के बीच बड़े पैमाने पर खींचतान हो रही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) प्रस्तावित बदलावों का खुले तौर पर मुखालफत कर रहा है. दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंकाई बोर्ड पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. कुछ बोर्ड अभी भी अनिर्णय की स्थिति में हैं. वहीं न्यूजीलैंड इन बदलावों को सकारात्मक और अपने हित में बता रहा है और इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है. कोई क्रिकेट को बचाने की गुहार कर रहा है तो कोई व्यक्तिगत फायदे-नुकसान के आधार पर पोजीशन ले रहा है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आईसीसी में इस तरह के बदलाव करने की किसे और क्यों सूझी और वह इन बदलावों से क्या हासिल करना चाहता है?

सबसे पहले आईसीसी में रद्दोबदल का यह प्रस्ताव आईसीसी का कॉमर्शियल राइट्स मीटिंग ग्रुप लेकर आया था. उसे लगा था कि इस तरह के बदलाव करने से आईसीसी की आय में कई गुना इज़ाफा होगा. इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने की कवायद आईसीसी ने शुरू कर दी है. फिलहाल बीसीसीआई अपने कद में इज़ाफा होने से खुश है. बीसीसीआई इस प्रस्ताव को अपनी जीत के रूप में देख रहा है. उसके अनुसार यह भारत की पैसे बना सकने की क्षमता को स्वीकृति मिलना (रिकग्नाइजेशन) है. बीसीसीआई आज दुनिया का सबसे धनवान क्रिकेट बोर्ड है. डीआरएस (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) जैसे मुद्दों पर भारत के विरोध की वजह से आईसीसी इसे वैश्विक स्तर पर लागू नहीं कर सका, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हमेशा इसके समर्थन में रहे हैं. यदि प्रस्ताव के पारित होने के बाद इस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती है, तब भारत क्या रुख अख्तियार करेगा. इस प्रस्ताव को पारित करवाकर भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे एशियाई सहयोगियों से दूर हो जाएगा. ये तीनों देश हमेशा बीसीसीआई के साथ खड़े दिखाई दिए. अब भारत सुपर थ्री में शामिल होने के बावजूद कई मुद्दों पर अकेला खड़ा दिखाई देगा, जहां उसके पास बचाव का कोई रास्ता भी नहीं होगा. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को क्रिकेट कैलेंडर में विंडो दिए जाने की पैरवी हमेशा से बीसीसीआई करता रहा है, ताकि दुनिया भर के क्रिकेटर उसमें खेल सकें और बीसीसीआई का खजाना भरता रहे, लेकिन निर्णायक भूमिका मिलने के बाद क्या भारत ऐसा कर पाएगा? उसके साथ वे देश निर्णायक भूमिका में होंगे, जो अपने खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने पर पांबदी लगाते रहे हैं. क्या सुपर थ्री में भारत अपने व्यावसायिक हित साध पाएगा? यह बात अभी साफ नहीं हो पा रही है.

इस प्रस्ताव के विरोध में सबसे तीखी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने दी है. इमरान ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बदलावों का विरोध किया है. उनके अनुसार ये बदलाव विवादास्पद हैं. यदि इन बदलावों को स्वीकृति मिल जाती है तो क्रिकेट एक बार फिर से औपनिवेशिक दौर में लौट जाएगा. इमरान का कहना है कि इस प्रस्ताव से उन दिनों की याद ताजा हो गई, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास आईसीसी में वीटो पावर होती थी. उस दौर में भारत और पाकिस्तान की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही थी. दोनों ही आईसीसी में साम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए लड़ रहे थे और इसे लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के पक्षधर थे, लेकिन आज भारत पैसे के प्रभाव तथा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के समर्थन से इसे पुराने रूप में लाना चाहता है. यदि आज मैं पीसीबी का अध्यक्ष होता तो मैं इस औपनिवेशिक प्रणाली का खुलकर विरोध करता. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ज़का अशरफ ने आईसीसी मीटिंग के दौरान कहा कि यह देखना है कि हमें पैसा चाहिए या क्रिकेट. यदि क्रिकेट का वजूद बना रहेगा तो सभी बोर्डों को पैसा भी मिलता रहेगा, लेकिन यदि हम केवल पैसे के पीछे भागने लगेंगे तो यह क्रिकेट को वापस नहीं ला पाएगा. हो सकता है कि बांग्लादेश इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश को व्यक्तिगत फायदे दिखाई दे रहे होंगे. उन्हें निकटवर्ती ही नहीं, दूरगामी परिणामों के बारे में भी सोच-विचार करना चाहिए. उन्हें इस बात का भी आकलन करना चाहिए कि इन बदलावों से हमारे देश और हमारे बोर्ड को क्या फायदा होगा. यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है. इससे पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य भी प्रभावित होगा. इसलिए हम इसे हल्के में नहीं लेंगे और इन प्रस्तावों को लागू होने से रोकने की हरसंभव कोशिश करेंगे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी में प्रतिनिधि मार्क स्नीडेन ने बीसीसीआई और प्रस्तावित बदलावों का बचाव करते हुए कहा है कि इन बदलावों से हमें फायदा होगा. ऐसा नहीं है कि वित्तीय फायदों के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हमेशा आपस में क्रिकेट खेलते रहेंगे और बाकी टीमें आपस में खेलती रहेंगी. हमें अगले एक दशक में इन तीनों देशों के साथ बहुत क्रिकेट खेलनी है. पिछले कुछ सालों में आईसीसी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि भारत उनके खेमे में होने के बजाए बाहर रहता था. फिलहाल जो हो रहा है, वह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भारत को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश है, ताकि आईसीसी में समय-समय पर खड़ी होने वाली अनिर्णय की स्थिति से निजात मिल सके. इन बदलावों से हमें आर्थिक फायदा भी मिलेगा. इन संशोधनों के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट का राजस्व 5.20 करोड़ डॉलर से बढ़कर लगभग सात से दस करोड़ डॉलर के बीच का हो जाएगा.

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बदलावों की समीक्षा करने के लिए एक उपसमिति का गठन किया है. बोर्ड के अंदर इस संबंध में अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अधिकांश पदाधिकारी आईसीसी में होने वाले बदलाव के प्रस्ताव के खिलाफ हैं. लगभग सभी सदस्यों का मानना है कि इन बदलावों के लागू हो जाने से विश्व क्रिकेट पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दबदबा हो जाएगा. श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति ने इस संबंध में आपात बैठक के बाद कहा कि वह अपने मौजूदा अधिकारों और विशेषाधिकारों का बचाव करेगी. कई लोग इन बदलावों को धनी बोर्डों द्वारा पोषित कट्टरपंथी शासन व्यवस्था की स्थापना बता रहे हैं, क्योंकि बदलावों की वजह से पैसा और पॉवर दोनों ही भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्डों के बीच केंद्रित हो जाएगा. दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसका कड़ा विरोध कर रहा है और इसे वापस लेने की मांग कर रहा है. फेडेरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष पॉल मार्श भी प्रस्तावित बदलावों को असंवैधानिक बताते हुए आलोचना कर रहे हैं.

आईसीसी के प्रशासन और इसके राजस्व बंटवारे में आमूलचूल बदलाव की मांग का अगर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश और दक्षिण अफ्रीका विरोध करते हैं तो यह प्रस्ताव विफल हो जाएगा, क्योंकि इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए आईसीसी के 10 पूर्ण सदस्यों में से कम से कम सात सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है. भारत, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे का समर्थन मिलना तय लग रहा है, जबकि वेस्टइंडीज भी इस विवादास्पद प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर सकता है. इस प्रस्ताव को आईसीसी से पारित कराने के लिए दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में से किसी एक देश को समर्थन में वोट देना होगा.

नए बदलाव के बाद भारत को आठ गुना ज्यादा आमदनी आईसीसी से होगी. इससे बीसीसीआई की आमदनी 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी. बदलाव से बीसीसीआई को तात्कालिक फायदा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबे समय में क्या कुछ होगा, इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है. बीसीसीआई के लिए पैसे और पावर के लिहाज से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा. फिलहाल बीसीसीआई केवल अधिकारों की बात कर रहा है. उसके अनुसार इन बदलावों की वजह से वैश्विक क्रिकेट गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं आएगा. न ही अन्य देशों की भूमिका खत्म हो जाएगी. अन्य देशों को भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किए जाने के भी कई तरह के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, जिससे कि निर्णय लेने में अन्य देशों की भूमिका बनी रह सके. आईसीसी में इस तरह के बड़े बदलाव से क्रिकेट को फायदा होगा या नुकसान या फिर क्रिकेट एक वैश्विक खेल में परिवर्तित हो पाएगा, इन सलावों का कोई स्पष्ट जवाब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है. यहां सबसे बड़ी चुनौती टेस्ट क्रिकेट के वजूद को बचाए रखने और टी-20 के माध्यम से क्रिकेट को वैश्विक खेल में परिवर्तित करने की है. इन दोनों चुनौतियों का एक साथ सामना करना और उनके बीच तालमेल बना पाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं. बदलाव का लक्ष्य केवल धन उगाही नहीं होना चाहिए. खेल की गुणवत्ता को बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है. क्रिकेट को केवल रन और पैसे के खेल या कहें कि बेसबॉल जैसे खेल में बदलने से रोकना होगा. क्रिकेट में रोमांच ऑन फील्ड गतिविधियों की वजह से आना चाहिए, न कि ऑफ फील्ड एक्टीविटी से. फिलहाल जो बदलाव हो रहे हैं, उनसे ऑफ फील्ड गतिविधियां क्रिकेट पर हावी होती दिख रही हैं. यदि आगे ऐसा होगा तो क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित नहीं रह जाएगा. ■

रुपहले पर्दे से राजनीति के मंच तक

फिल्मी सितारों की लोकप्रियता को भुनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां कभी उन्हें चुनाव मैदान में उतारती हैं तो कभी स्टार प्रचारक के रूप में. राजनीति का अनुभव न होने के बावजूद इन स्टार्स को आसानी से टिकट मिल जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का मुख्य मकसद सिर्फ़ इनके सहारे चुनाव जीतना होता है.

प्रियंका प्रियम तिवारी

अभिनेता सन्नी देओल जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाले हैं. अब उनके पास बॉलीवुड में करने के लिए कुछ ख़ास बचा भी नहीं है. हालांकि बॉलीवुड में टिके रहने के लिए उन्होंने फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी कीं, लेकिन इसमें भी उन्हें नाक़ामयाबी ही मिली. ऐसे में अब उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी है. पिता धर्मेंद्र और मां हेमा भी राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं. धर्मेंद्र ने 2004 में राजस्थान के बीकानेर से भाजपा के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीते भी थे. वहीं हेमा मालिनी भी भाजपा से राज्यसभा सांसद चुनी गईं.

बॉलीवुड कलाकारों की लोकप्रियता को भुनाने की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने की. पार्टी की जीत के लिए स्टार छवि को भुनाने से उन्हें कोई परहेज नहीं था. 1962 के आम चुनाव में बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से खड़े थे लोकप्रिय राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी और उनके अपोजिट एक बेहद आम महिला थी दिल्ली की सुभद्रा जोशी. अटल जी की लोकप्रियता से नेहरू भी वाकिफ थे. तब उन्होंने अटल बिहारी बाजपेयी को मात देने के लिए उस समय के बड़े स्टार बलराज साहनी की मदद ली. बलराज साहनी के जादू के आगे आख़िर अटल बिहारी वाजपेयी हार गए. इसके बाद तो सभी पार्टियों में स्टार्स छवी को भुनाने का ट्रेंड चल निकला. जहां स्टार्स रिटायरमेंट के बाद विकल्प के तौर पर राजनीति में आने लगे, वहीं राजनीतिक पार्टियों को भी उनकी बदौलत जीत की उम्मीद नजर आने लगी. चुनावी सभाओं में राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा और उनके वायदे लोग कम देखते हैं और अपने प्रिय कलाकार की एक झलक देख लेने के लिए हुजूम उमड़ पड़ता है. भीड़ इकट्ठी करने के लिए राजनीतिक पार्टियां लोकप्रिय कलाकारों को अपने साथ जोड़ने की होड़ में लगी रहती हैं. वहीं फिल्म कलाकारों को राजनीति में आने के अलग फ़ायदे नज़र आते हैं. अपने जमाने में लोगों के दिलों पर राज करने वाले फिल्म स्टार्स नर्गिस, सुनील दत्त, अमिताभ, रेखा, शबाना आजमी, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई कलाकारों ने राजनीति में किस्मत आजमाई. जाने-माने फिल्म कलाकार और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म कलाकरों के राजनीति में आने की वजह मानते हैं कि वे लोकप्रिय होने के साथ ही आर्थिक रुप से मज़बूत भी हैं, जिससे पार्टी पर ज़्यादा दबाव नहीं रहता. इसके अलावा, फ़िल्म स्टार्स राजनीति में राजकीय सम्मान पाने की लालसा से आते हैं, जबकि राजनीतिक पार्टियां उनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती हैं. दोनों ही एक-दूसरे की ज़रुरत को पूरी करते हैं. हालांकि अधिकतर स्टार्स को सियासी दुनिया रास नहीं आती. भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके अभिनेता धर्मेंद्र कहते हैं कि फ़िल्म स्टार्स अगर राजनीति से दूर ही रहें तो अच्छा है. उनकी राय में अभिनेता को अभिनय तक ही रहना चाहिए और राजनीति में नहीं जाना चाहिए. हालांकि उन्हीं के बेटे सन्नी अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही कलाकरों के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में करियर ख़त्म होने के बाद राजनीति की राह पकड़ी, लेकिन एक राजनेता के रूप में वह कितने सफल हुए...

सुनील दत्त-नर्गिस दत्त : सुनील दत्त ने कई बेहतरीन फिल्में की. अभिनेत्री नर्गिस से विवाह कर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिशाल कायम की. उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी. उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने. वे यहां से लगातार पांच बार चुने गए. उनकी गिनती प्रभावशाली नेताओं में होती थी. मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त उनकी विरासत संभाल रही हैं. वहीं नर्गिस ने फिल्मों को अलविदा कहा और सामाजिक कार्यों में जुट गईं. पति सुनील दत्त के साथ अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप की स्थापना भी की. यह दल सीमाओं पर जाकर जवानों के मनोरंजन के लिए स्टेज शो करता था. नर्गिस को उनके योगदान के लिए पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले. उनके योगदान और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया.

अमिताभ बच्चन-जया बच्चन : राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ ने राजनीति में क़दम रखा था. अभिनय से कुछ दिनों का ब्रेक लेकर उन्होंने अपने शहर इलाहाबाद से चुनाव लड़ा. उनके सामने एक बड़ा नाम था एच.एन. बहुगुणा. अमिताभ की लोकप्रियता काम आई और उन्होंने बहुगुणा को भारी अंतर से हराया. सुपरस्टार अमिताभ राजनीति में कुछ ख़ास नहीं कर पाए और उनके दामन पर दाग़ लगे सो अलग. इस छोटे से सफ़र में बोफोर्स कांड में उनके भाई अजिताभ का नाम भी आया. वह जल्द ही समझ गए कि नेतागिरी उनके लिए नहीं है और उन्होंने राजनीति से विदा लेने में ही भलाई समझी. हालांकि सपा से उनकी नजदीकियां थीं. अमर सिंह उनके अच्छे मित्र थे और मददगार भी. अमर सिंह के कहने पर ही जया ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की.

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी : फिल्मों में अभिनय के अलावा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई. वर्ष 2004 में धर्मेंद्र और हेमा दोनों भाजपा में शामिल हुए. भाजपा के टिकट पर धर्मेंद्र ने राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन धर्मेंद्र राजनीति में सक्रिय नहीं रहे. संसद के किसी भी सत्र में वह शामिल नहीं होते थे. इससे उन्हें कई तरह के आरोपों का सामना भी करना पड़ा.

गोविंदा : गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर उत्तरी मुंबई से वर्ष 2004 में सांसद चुने गए थे. बॉलीवुड में कामयाबी के बाद उन्होंने पांच साल का ब्रेक लिया और राजनीति में आए, पर बाद में उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला उनके जीवन का सबसे ख़राब फ़ैसला था. गोविंदा ने कहा कि उनके लिए यह वाकई चुनौतीपूर्ण था कि वह करिश्मा कपूर और बॉलीवुड की हॉट हसीनाओं के जगह नेताओं के साथ काम करना. और तो और वह यह भी कहते हैं कि राजनीति में रहते उनका वजन बढ़कर 108 किलोग्राम हो गया था और जब उन्होंने राजनीति छोड़ने का फ़ैसला किया तो वजन घटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था. वह यह भी मानते हैं कि राजनीतिक बैकग्राउंड के बिना यहां रहना काफ़ी मुश्किल है, पर वह खुशनसीब मानते हैं ख़ुद को कि बिना उनके दामन पर कोई दाग़ लगे उन्होंने राजनीति से विदाई ले ली.

जया प्रदा : जयाप्रदा को 1994 में उनके पूर्व साथी अभिनेता एन.टी. रामराव ने तेलुगू देशम पार्टी में लाए, पर बाद में उन्होंने एन.टी. रामराव से नाता तोड़ लिया और चंद्रबाबू नायडू गुट में शामिल हो गईं. 1996 में उन्हें आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया. पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेदों के कारण, उन्होंने तेदेपा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं. 2004 के आम चुनावों के दौरान रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सफल रहीं.

शत्रुघ्न सिन्हा : शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं. वर्ष 1996 में शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार राज्य सभा के सदस्य चुने गए. 2002 में उन्हें दोबारा राज्यसभा सदस्य का पद प्रदान किया गया. 2004 में शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिनेता शेखर सुमन को हरा कर पटना निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता. केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवार कल्याण मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय संभाला. वर्ष 2009 में वह पंद्रहवें लोकसभा चुनाव में भी विजयी रहे और उन्हें पर्यटन, संस्कृति, और यातायात समिति का सदस्य बनाया गया. वह बॉलीवुड छोड़ पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय रहे. शत्रुघ्न सिन्हा जय प्रकाश नारायण के अनुयायी माने जाते हैं. शत्रुघ्न सिन्हा ने असहायों के लिए गृह निर्माण और लोगों को नेत्र दान के लिए प्रेरित करने के लिए कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया. इसके अलावा वह दहेज प्रथा और श्रमिकों पर होने वाले अत्याचार को उजागर करने के लिए कालका और बिहारी बाबू नामक सामाजिक फिल्मों का निर्माण भी कर चुके हैं. उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार रत्न सम्मान से भी नवाजा गया है.

संजय दत्त : जेल से रिहा होने के पश्चात संजय दत्त की नजदीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ने लगीं. वर्ष 2009 के आम-चुनावों से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पर चल रहे मुक़दमों को स्थगित करने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा.

वैजयंति माला : वर्ष 1989 के चुनाव के दौरान राजीव गांधी ने उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. उन्होंने चुनाव लड़ा और 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज कराई. इसके बाद वह दो बार राज्यसभा से सांसद भी रहीं.

विनोद खन्ना : विनोद खन्ना 1997 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े. अगले ही वर्ष पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विनोद खन्ना लोकसभा सदस्य बने. 1999 में हुए चुनावों में वह एक बार फिर इस निर्वाचन क्षेत्र से जीते. जुलाई 2002 में विनोद खन्ना को केंद्रीय मंत्री के तौर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया. वर्ष 2004 में हुए लोकसभा चुनावों में विनोद खन्ना की जीत हुई, लेकिन 2009 में पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव में विनोद खन्ना नहीं जीत पाए.

चिरंजीवी : तेलुगू सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी ने 2008 में प्रजाराज्यम नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई थी. इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय दिलाना था. 2009 के चुनाव में आंध्र प्रदेश के स्टेट असेंबली से यह पार्टी जीती थी. 2011 में उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया.

बॉलीवुड के खान्स का राजनीति प्रेम

हालांकि कुछ कलाकार सीधे राजनीति में प्रवेश करते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष तरीके से पार्टी के साथ खड़े होते हैं. बॉलीवुड के तीनों खान में सलमान वैसे तो राजनीतिक पार्टियों से बचते हैं, लेकिन हाल ही में वह गुजरात में मोदी के साथ थे. उन्होंने मोदी को गुड मैन तक कहा. इससे उनके मोदी से नजदीकियों की चर्चा होने लगी. हालांकि वह अपनी फिल्म जय हो के प्रमोशन के लिए वहां थे.

शाहरुख खान की कांग्रेस से नजदीकियों के बारे में कहा जाता है. शाहरुख और गौरी राहुल-प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के साथ कई मौकों पर नजर आ चुके हैं, जबकि अपनी फिल्म मैं हूं ना के स्पेशल शो का आमंत्रण सोनिया को देने शाहरुख खुद उनके घर गए थे. आने वाले समय में वह कांग्रेस में शामिल हो जाएं या पार्टी का प्रचार करते नजर आएं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी. वहीं आमिर खान आम आदमी पार्टी के समर्थक कहे जाते हैं. वह आंदोलन की शुरुआत से साथ थे और उन्होंने तब बयान दिया था कि देश में एक तरह की पार्टी की जरूरत है और यह काम आम आदमी पार्टी बखूबी कर सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

KHARA SAUDA
Issey Behtar Aur Nahin
011-64000222 / 333
"SMART AND USEFUL WOMEN & MEN COMBO"

Women's Combo

Handbag Features:
• 2 Main Compartments Inside
• 1 Zip Compartment Outside
• Faux Leather
• Matte Black Smooth Finish
• Twin Grab Handles

Wrist Watch Features:
• Steel Case
• Faux Leather Strap
• SL 65 Moment
• Three Hands (Hour: Minute: Second)
• Stainless steel dial material
• Round Dial Shape
• Function: Analog

Sunglass Features:
• Lens type: Polycarbonate lens
• Frame type: Plastic full frame and plastic arms
• High bridge and fixed nose pads
• Style Note: This trendy sunglasses emit an English vibe combined with a retro inspiration. Made from high quality materials, these sunglasses make sure you stay comfortable and stylish with box packing
• UV Protected

Ladies Clutch Features:
• 2 Compartments
• Dimension: 6 x 8 x 2 cm (LxWxH)
• Faux Leather

MRP- ~~Rs. 2999/-~~
Special Price Rs. 999/-

Freebie: Na
Warranty: Na

Men's Combo

Wallet Features:
• 100% Genuine Leather
• 2 Main Compartments
• 1 Coin Pocket
• 3 Slots for Credit Card
• 1 Pocket for Driving License/ PAN Card
• Dimensions: 9 x 3.5 inches

Wrist Watch Features:
• Fibre Case
• Black Seude Strap
• SL 65 Moment
• Three Hands (Hour: Minute: Second)
• Alluminium- dial material
• Round- Dial Shape
• Function: Analog

Sunglass Features:
• Lens type: Polycarbonate lens
• Frame type: Gun Metal
• High bridge
• With Box packing
• UV Protected
• 58 Cms

Belt Features:
• 100% Genuine Leather
• Fits Waist size 30 to 38
• Steel Buckle
• Smooth Finish

MRP- ~~Rs. 2999/-~~
Special Price Rs. 999/-

Freebie: Na
Warranty: Na

Call/SMS : 011-64000222 & 011-64000333
PAY CASH ON HOME Delivery
Offer open till stock lasts
'Products and warranty by 3rd party vendors. Brands. Logos. Creative, trademarks, copyrights are owned by their respective vendors'
*Terms & Condition Apply

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

17 फरवरी –23 फरवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार – झारखंड

दम दिखाएंगे कुशवाहा

शांडिल्य कहते हैं कि विषधर से मेरा तात्पर्य उन जातियों से है जो सत्ता सुख ले चुकी हैं और कोइरी भी इसी समूह में आते हैं. बताते चलें कि नीतीश ने पंचायतों में अतिपिछड़ों को बीस प्रतिशत आरक्षण दिया, महिलाओं को पचास प्रतिशत. एक और बात गौर करने वाली है कि हाल में नीतीश ने तीन लोगों को राज्यसभा भेजा जिनमें से पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी शामिल हैं जो अतिपिछड़ा समुदाय से आते हैं. इसके बाद से यह माना जा रहा है कि नीतीश को भी इस बात की चिंता है कि आने वाली राजनीति अतिपिछड़े के इर्दगिर्द ही घूमेगी.

शशि सागर

गया वाले प्रभात शांडिल्य ने लगभग बाईस साल पहले एक लेख लिखा था, बिहार के बीस विषधर. उन दिनों यह लेख काफी चर्चित भी हुआ था. इसमें कहा गया था कि पहले बिहार की सात जातियों ने सत्ता सुख लिया. इनमें ब्राह्मण, राजपूत, भुमिहार, कायस्थ, सैयद, शेख और पठान थे. इसके साथ ही जब गांधी व कांग्रेस ने स्वदेशी का नारा दिया, खिलाफत का समर्थन किया और असहयोग आंदोलन चलाया तो स्वदेशी के नारे की वजह से जुलाहे 1917 से 47 के बीच मजबूत हुए और उन्हें आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी मिली. और ये आठवें विषधर हुए. बाद में संविधान में आरक्षण का प्रावधान आया तो धोबी, पासी, चमार और दुसाध सशक्त हुए, और अनुसूचित जनजातियों की तीस जातियों में से चार संथाल, हो, उरांव और मुंडा ही इसका लाभ ले पाईं. इसके बाद जब कर्पूरी और मंडल के आरक्षण का दौर आया तो यादव, कुर्मी, कोइरी, बनिया सत्ता के भागीदार बने. शांडिल्य समझाते हैं कि इस तरह ये बीस जातियां अपने हिस्से का लाभ ले चुकी हैं. कहते हैं कि आप देखिए चपरासी से लेकर आईएएस तक आपको इन्हीं बीस जातियों से मिलेंगे और इन बीस जातियों के अलावा जितनी भी जातियां हैं वे लगभग 90 के दौर तक उपेक्षित ही रहीं. लेकिन हमारी बहस जहां से शुरू होती है फिर वहीं आ जाती है कि बिहार में सवर्णों के खिलाफ समीकरण बना तो लालू सत्ता में आए. यादव जब सत्ता की जाति में समाहित हो गया तो गैर–यादव बैकवर्ड का नारा लगा. नीतीश ने कोइरी–कुर्मी (लव–कुश समीकरण) के साथ अन्य पिछड़े वर्गों का नेतृत्व किया और सीएम की कुर्सी तक पहुंचे. बताते चलें कि नीतीश कुर्मी जाति से आते हैं. अब जबकि बिहार में अतिपिछड़े के समीकरण पर हर दल काम कर रहा है तो क्या कोइरी जाति सत्ता में आ पायेगी? शांडिल्य कहते हैं कि लवकुश समीकरण बिखर चुका है. नीतीश के राज में कोइरी खुद को सबसे उपेक्षित महसूस कर रहा है. शांडिल्य कहते हैं कि विषधर से मेरा तात्पर्य उन जातियों से है जो सत्ता सुख ले चुकी हैं और कोइरी भी इसी समूह में आते हैं. बताते चलें कि नीतीश ने पंचायतों में अतिपिछड़ों को बीस प्रतिशत आरक्षण दिया, महिलाओं को पचास प्रतिशत. एक और बात गौर करने वाली है कि हाल में नीतीश ने तीन लोगों को राज्यसभा भेजा जिनमें से पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी शामिल हैं जो अतिपिछड़ा समुदाय से आते हैं. इसके बाद से यह माना जा रहा है कि नीतीश को भी इस बात की चिंता है कि आने वाली राजनीति अतिपिछड़े के इर्दगिर्द ही घूमेगी और इसी वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश ने रामनाथ को राज्यसभा भेजा है. कई दलों के नेताओं से बात होती है सबका लब्बोलुआब यही होता है कि आने वाले समय में अतिपिछड़े ही निर्णायक होंगे. लेकिन रालोसपा के वरिष्ठ नेता रामबिहारी सिंह कहते हैं कि बिहार में पिछड़े अतिपिछड़े का बंटवारा हुआ है और नीतीश ने अतिपिछड़ा कार्ड खेला है. लेकिन लालू के बाद नीतीश आए और इसके बाद अगर कहीं संभावना है तो उपेंद्र कुशवाहा में. लेकिन इसके लिए उपेंद्र को नए संस्करण में आना होगा. रामबिहारी कहते हैं कि यह तय है कि जहां उपेंद्र की राजनीति निर्णायक होगी वहां कुशवाहा समाज उन्हीं को वोट करेगा और शेष जगहों पर नीतीश के विरोध में. बताते चलें कि बिहार में दस प्रतिशत कुशवाहा जाति की संख्या है. कुशवाहा समाज के एक भी बड़े नेता जैसे नागमणि, शकुनी चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ नहीं हैं. हमने यही सवाल कि क्या कोइरी राजनीति की संभावना नीतीश खत्म कर चुके हैं, एनसीपी के नागमणि से किया. नागमणि कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है आज सारे बैकवर्ड नेताओं को इस बात का भय है कि अगर कुशवाहा नेतृत्व उभरा तो उनका क्या होगा? नागमणि कहते हैं कि खुद नीतीश की पार्टी की कुशवाहा जाति के नेता उनसे नाराज हैं वे घुटन महसूस करते हैं. वे कहते हैं कि बड़े अरमान से लवकुश समीकरण ने उन्हें सीएम बनाया था लेकिन नीतीश ने कुशवाहा समाज को ठगा है और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना होगा.

बहरहाल यह देखा गया है कि जब–जब चुनाव का समय आता है कुशवाहा राजनीति अंगड़ाई लेती है और ऐसे समय में जब बिहार में कोइरी राजनीति की सुगबुगाहट तेज हो रही है तो उनके तीनों बड़े नेता नागमणि, शकुनी और उपेंद्र नीतीश के साथ नहीं हैं. यह नीतीश के लिए मुश्किल की घड़ी कही जाएगी कि जिस लवकुश समीकरण के वे नेता है उसमें से कोइरी उनसे नाराज चल रहा है. सत्येंद्र नारायण कुशवाहा भाजपा से विधान पार्षद हैं. भाजपा में कुशवाहा समुदाय के बड़े चेहरे हैं. कुशवाहा का कहना है कि इस बार कुशवाहा समुदाय का नब्बे फीसदी वोट भाजपा को जाएगा. उनका मानना है कि जिस तरह से भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद के प्रत्याशी के रूप में आगे किया है इससे कोइरी समुदाय काफी उत्साहित है. कुशवाहा यह संकेत भी देते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से कम से कम पांच सीट कुशवाहा समुदाय को दी जाएगी. बताते चलें कि जब–जब चुनाव का समय आता है प्रत्येक दल इस समुदाय को साधने की कोशिश करता है. इसके पीछे बड़ी वजह भी है. 243 विधान सभा सीट में से 200 सीट ऐसी हैं जहां कुशवाहा जाति के वोटों की संख्या दस हजार से पचास हजार तक है. वहीं 90 से 95 सीट ऐसी हैं जहां से 1952 के बाद से अभी तक कुशवाहा समुदाय प्रतिनिधित्व कर चुका है. वहीं चालीस में से बारह लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां से इस समुदाय का प्रतिनिधित्व रह चुका है.

हम फिर से लौटते हैं प्रभात शांडिल्य की बीस विषधर जातियों पर. बिहार में दो सौ से अधिक जातियां हैं और यही बीस जातियां यहां हर क्षेत्र शिक्षा, राजनीति, खेल व अन्य में आगे रही हैं. बाकी 180 जातियां अभी भी उपेक्षित हैं. समाजशास्त्रियों का मानना है कि हर जाति एकबार अपनी पारी अवश्य खेलती है. सबसे पहले सवर्णों ने सत्ता सुख लिया. इसके बाद गैर सर्वणवाद की राजनीति और पिछड़ों के उभार की बदौलत लालू ने सत्ता का आनंद लिया. जब गैर यादव पिछड़े गोलबंद हुए तो नीतीश सत्ता में आए और पिछले आठ साल से कोइरी के साथ मिलकर कुर्मी सत्ता में है. कोइरी और कुर्मी की आपस में गुत्थम–गुथाई इस तरह की है कि लोग दोनों को साथ मानकर ही चलते हैं. दोनों का साथ 1952 से ही है जब कोइरी–कुर्मी और यादवों ने मिलकर त्रिवेणी संघ बनाया था. तो अब सवाल उठता है कि क्या कोइरी इस स्थिति में हैं कि वे गोलबंद हो सकें. इतना ही नहीं बिहार में पिछड़ों की राजनीति सालों से चल रही है सबसे पहले मुख्यमंत्री केबी सहाय ने 1967 में ही तीन पिछड़ों को मंत्रिमंडल में जगह दी थी. और बिहार की राजनीति में 90 से पिछड़े ही अपनी पारी खेल रहे हैं. पंद्रह साल तक यादवों ने पारी खेली इसके बाद आठ साल से कुर्मी सत्ता में हैं. अब दो जातियां बनिया और कोइरी बच जाते हैं. बनिया और लाला के बारे में कहा जाता है कि ये भाजपा के स्वभाविक वोटर रहे हैं, तो बचती है एक मात्र कोइरी जाति. तो फिर से सवाल यही उठता है कि क्या कोइरी समुदाय गोलबंद हो सकेगा. वो भी तब जब नीतीश पिछले आठ सालों में अतिपिछड़ों का उभार कर चुके हैं. राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन कहते हैं कि इतिहास सपोर्ट नहीं करता है कि कोइरी सत्ता में आएगा. भारतीय जाति व्यवस्था ही ऐसी है कि हमेशा सोशल इंजिनीयरिंग का नया फार्मूला आता है पुराना रिपीट नहीं होता है. सुमन यह भी कहते हैं कि नीतीश के साथ ही ओबीसी की पारी खत्म है और अब अतिपिछड़ों की बारी है. बहरहाल देखना यह है कि कुशवाहा राजनीति की जो सुगबुगाहट तेज हुई है वह क्या रंग लाती है, क्योंकि हर दल की कोशिश जारी है कि कैसे इस समुदाय को अपनी ओर मोड़ा जा सके. पिछले दिनों कोइरी समुदाय के अबतक के सबसे बड़े नेता शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती को सभी दलों ने प्रमुखता से मनाया. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

विशेष राज्य का दर्जा दिलाना ही उद्देश्य

जदयू तकनीकी प्रकोष्ठ की महासचिव व प्रवक्ता अनुपम कश्यप ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना ही हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है. हम बिहारवासी मेहनती और ईमानदार होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिल पाने के कारण न तो उद्योग धंधे लग पा रहे हैं और न ही पर्याप्त संसाधन मिल पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो हम अन्य राज्यों से आगे निकल जाएंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव में सभी बिहारवासियों को साथ देना है. यही हमारा संकल्प है. – *अमृता कुमारी*

निर्माण कार्य शुरू नहीं

शहर के माधुरी चौक एवं बहादुरपुर मालगोदाम चौक को जोड़ने वाले जर्जर पुल के नवीनीकरण के कार्य का शिलान्यास 23 जनवरी 2014 को समस्तीपुर के सांसद महेश्वर हजारी ने किया. लेकिन अबतक काम शुरू नहीं हो सका है. एक करोड़ छब्बीस लाख रुपये की राशि से बनने वाले पुल में दो पहिया वाहन के गुजरने हेतु रैम्प भी बनाया जाना है. क्षेत्र में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही शिलान्यास के मामले ने जोर पकड़ लिया है.

लीगल सर्विस का उद्घाटन

नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (नालसा) ने देश भर में एक साथ प्रत्येक तालूके के एक गांव में विलेज लीगल सर्विस क्लीनिक सेवा का उद्घाटन किया. जिसका सीधा प्रसारण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के न्यायिक पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने देखा. न्याय को सुलभ बनाने व कोर्ट में बढ़ रहे मुकदमों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से विलेज लीगल सर्विस क्लीनिक खोला गया है. समस्तीपुर सदर के लगुनिया सूर्यकंठ, पटोरी के मोहनपुर, रोसड़ा के भिरहा एवं दलसिंहसराय के केउटा में खुला है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम, पेट्रन इन चीफ नालसा जस्टिस आर एम लोढ़ा, कार्यकारिणी अध्यक्ष नालसा जस्टिस ए के पटनायक ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विलेज लीगल सर्विस क्लीनिक का उद्घाटन किया. समारोह के सीधे प्रसारण के दौरान डीजे अरविन्द कुमार, सीजेएम शिवानंद मिश्र समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित थे.

प्रशस्ति पत्र दिया गया

प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत ने 23 नवम्बर 2013 को उत्कृष्ट कार्य करने वाले न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायिक लिपिकों, स्काउट गाइड के बच्चों एवं मीडिया कर्मियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर अरविन्द कुमार एवं सब जज प्रथम व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर संगीता ने संयुक्त रूप से प्रशस्ति पत्र दिया. एक समारोह में प्रशस्ति पत्र वितरण के बाद डीजे ने आगामी 12 अप्रैल 2014 को होने वाले द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत को भी सफल बनाने का आह्वान किया. समारोह में सीजेएम शिवानंद मिश्र, रजिस्ट्रार रामजी सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमार ऋशिकेश, अधिवक्ता किरण सिंह, नंद कुमार सिंह नवीन, अशोक कुमार सिंह, प्रभात कुमार सिंह, यशवंत कुमार सिंह, कुमार रविशंकर, ओम प्रकाश पाण्डेय, शिव राम चौधरी, अजय कुमार झा, स्काउट गाइड जिला अध्यक्ष व सचिव उपस्थित थे. ■

– *यशवंत कुमार सिंह*

चढ़ने लगा अररिया का राजनीतिक तापमान

अजातशत्रु अग्रवाल/पंकज सम्राट

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है यहां का राजनीतिक तापमान भी चढ़ने लगा है. चुनाव लड़ने के इच्छुक विभिन्न दलों के उम्मीदवार अपनी-अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए पटना और दिल्ली तक की दौड़ लगाना शुरू कर चुके हैं. इसके इतर कुछ बड़े नेता क्षेत्र में लगातार दौरा कर मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं.

बताते चलें कि इस संसदीय क्षेत्र पर वर्तमान में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह का कब्जा है. आगामी लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिलेगा या नहीं फिलहाल इसपर संशय बरकरार है. एक ओर जहां प्रदीप अपने टिकट को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं, वहीं फारबिसगंज के पूर्व भाजपा विधायक लक्ष्मीनारायण मेहता, नरपतगंज के पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव, गत लोकसभा चुनाव में अपना चुनावी भाग्य आजमा चुके राजा रमण भास्कर उर्फ रंटू मंडल, विश्व हिन्दू परिषद के प्रदेश मंत्री (प्रचार-प्रसार विभाग) विद्यासागर केशरी उर्फ मंचन केशरी के अलावा इस सीमावर्ती क्षेत्र के कद्दावर नेता व समाजसेवी अजय झा भी यहां से टिकट पाने की जुगत में भिड़े हुए हैं.

अजय झा — अरविंद गोयल — जनार्दन यादव — लक्ष्मी मेहता — प्रदीप सिंह — रंटू मंडल

इस संसदीय क्षेत्र पर वर्तमान में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह का कब्जा है. एक ओर जहां प्रदीप अपने टिकट को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं, वहीं फारबिसगंज के पूर्व भाजपा विधायक लक्ष्मीनारायण मेहता, नरपतगंज के पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव, गत लोकसभा चुनाव में अपना चुनावी भाग्य आजमा चुके रंटू मंडल, विश्व हिन्दू परिषद के प्रदेश मंत्री (प्रचार-प्रसार विभाग) विद्यासागर केशरी के अलावा इस सीमावर्ती क्षेत्र के कद्दावर नेता व समाजसेवी अजय झा भी यहां से टिकट पाने की जुगत में भिड़े हुए हैं.

वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह जहां अपनी दावेदारी में अररिया संसदीय सीट पर भाजपा का पुनः कब्जा कर लेने की बात पार्टी आला नेताओं को समझा रहे हैं वहीं टिकट को आतुर अन्य उम्मीदवार बड़े नेताओं को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर श्री सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया गया तो भाजपा इस बार अररिया में अपनी सीट बचा नहीं पाएगी. इन उम्मीदवारों का मानना है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में प्रदीप का चौतरफा विरोध हो रहा है, जिसका खामियाजा पार्टी को पराजय के रूप में झेलना पड़ेगा. राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चा के अनुसार अररिया संसदीय क्षेत्र से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन एवं विधान पार्षद राजेन्द्र गुप्ता भी चुनाव लड़ने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं. अगर ये दोनों नेता भी अररिया संसदीय क्षेत्र से अपनी दावेदारी को लेकर सक्रिय हुए तो वर्तमान सांसद का टिकट कटना लगभग तय माना जाएगा यहीं नहीं यहां से किसी भी अन्य इच्छुक प्रत्याशी की संभावनाओं को भी झटका लग जाएगा. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत स्वाभिमान संगठन के प्रमंडलीय आयुक्त प्रो. कमलकिशोर यादव भी टिकट प्राप्ति की दौड़ में शामिल है.

राष्ट्रीय जनता दल से पूर्व केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री मो. तसलीमुद्दीन भी सशक्त उम्मीदवार के रूप में सामने हैं. अपने कई अलग-अलग संबोधन में स्वयं तसलीमुद्दीन इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व उन्हें जहां से भी कहेगी वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं. राजद के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरविंद गोयल एवं राजद जिलाध्यक्ष अनिल कुमार यादव का कहना है कि मो. तसलीमुद्दीन के नेतृत्व में अररिया संसदीय क्षेत्र से राजद के विजय को कोई नहीं रोक सकता है. जदयू से पूर्व राज्यमंत्री विजय कुमार मंडल की दावेदारी लगभग तय है. विजय मंडल का कद इसी से जाना जा सकता है कि जिस वक्त बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक आनंद मोहन के द्वारा प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था तब सिर्फ विजय ने ही अररिया विधानसभा से विपिपा का झंडा बुलंद किया था. उनके समर्थकों का कहना है कि विजय को अगर नीतीश कुमार के द्वारा चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो अररिया संसदीय क्षेत्र से जदयू ही चुनाव जीतेगी. लोक जनशक्ति पार्टी के जाकीर अनवर बैराग भी अपनी चुनावी तैयारी को पूरा कर चुके हैं. इस क्षेत्र से उनका दावा भी काफी मजबूत है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में अनवर ने ही भाजपा के प्रदीप सिंह को तगड़ी टक्कर दी थी और जीत हार का अंतर महज कुछ हजार वोटों का ही रहा था. जाकीर अनवर को भी मुस्लिमों के साथ अन्य वर्गों के लोगों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त होने की बात लोजपा के जिलाध्यक्ष सुनिल झा एवं उनके समर्थक कहते हैं. हालांकि सबकुछ चुनावी गठजोड़ पर ही निर्भर करेगा. बहरहाल कांग्रेस के उम्मीदवार भी चुनावी रणभूमि में उतरने को तैयार हैं बशर्ते कांग्रेस का गठबंधन किसी भी दल के साथ न हो, क्योंकि अगर कांग्रेस का गठबंधन राजद, लोजपा, जदयू या किसी भी एक राजनीतिक दल से हो जाता है तो कांग्रेस के खाते में तो यह सीट नहीं आएगी. फिलहाल यह माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा में टक्कर भाजपा व अन्य दलों के बीच ही होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

सारण में सूरमाओं की भरमार

चन्द्रप्रकाश राज

सारण का राजनीतिक तापमान इन दिनों काफी बढ़ गया है और सियासतदां अपनी-अपनी दुकानें सजाने लगे हैं. लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. प्रतिदिन टिकट के दावेदारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. सभी अपने को दूसरे से बेहतर बताने में जुटे हैं. इस सीट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सांसद थे. लेकिन चारा घोटाले में सजा हो जाने से सारण संसदीय लोकसभा सीट रिक्त है. राजद के लिए इस कब्जे को बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण है. चुनावी सुगबुगाहट को लेकर राजद में संभावित प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने लगी है. यही वजह है कि पिछले कार्यकाल की पक्ष व विपक्ष दोनों तरफ से समीक्षा हो रही है. भाजपा के राज्यसभा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. रूड़ी द्वारा दौरे के पूर्व एसएमएस का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है. वहीं राजद का अभियान चुपचाप चल रहा है. जदयू लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करा रही है. पटना की रैली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रूड़ी द्वारा नरेन्द्र मोदी को सारण से चुनाव लड़ने के आमंत्रण के बाद महराजगंज के दबंग सांसद प्रभुनाथ सिंह ने कहा था कि यदि नरेन्द्र मोदी सारण से लोकसभा का चुनाव लड़े तो मैं सारण से चुनाव लड़कर श्री मोदी को हरा दूंगा. इस बयान के बाद छपरा के इस लोकसभा क्षेत्र की राजनीति और भी गर्मा गई है. इस लोकसभा क्षेत्र में छह विधानसभा क्षेत्र छपरा सदर, गड़खा, मढ़ौरा, अमनौर, परसा व सोनपुर है. छपरा सदर से भाजपा के पूर्वमंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गड़खा सुरक्षित से भाजपा के ज्ञानचंद मांझी, मढ़ौरा से राजद के जितेन्द्र कुमार राय, अमनौर से जदयू के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार मंटू, परसा से जदयू के छोटेलाल राय व सोनपुर से भाजपा प्रदेश महामंत्री विनय कुमार सिंह विधायक हैं. इस प्रकार भाजपा का तीन, जदयू का दो व राजद का एक सीट पर कब्जा है.

इस लोकसभा क्षेत्र का इतिहास काफी रोचक है. यहां प्रदेश व देश की लहर के खिलाफ ही लोकसभा चुनाव में मतदान होते रहे हैं. 84 में लोकसभा चुनाव की इंदिरा लहर में समाजवादी नेता रामबहादुर सिंह ने जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजयश्री हासील की थी. वहीं 89 में वीपी सिंह की लहर में भी चन्द्रशेखर, वीपी सिंह व देवीलाल की अपील के बावजूद लालू प्रसाद को चुनाव जीतने में काफी कठीन परिश्रम जनता पार्टी जेपी के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह से करना पड़ा था. पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में भाजपा-जदयू गठबंधन की लहर के बावजूद प्रत्याशी राजीव प्रताप रूड़ी को लगभग पचास हजार मतों से पराजय का मुंह देखना पड़ा. भाजपा की ओर से इस बार भी राजीव प्रताप रूड़ी को ही प्रत्याशी के तौर पर स्थानीय नेताओं द्वारा पेश किया जा रहा है. लेकिन आरएसएस के एक पुराने स्वंयसेवक ने बताया कि हम लोग नागपुर व अहमदाबाद से सोनपुर के विधायक विनय कुमार सिंह व छपरा सदर के विधायक जनार्दन सिंह सिग्रिवाल को प्रत्याशी बनाने की मांग कर रहे हैं. यदि ऐसा होता है तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा.

जदयू की ओर से जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार मंटू व विधान परिषद के उपसभापति सलीम परवेज भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं. जदयू के वरिष्ठ नेता जेपी सेनानी सम्मान योजना बिहार सरकार के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार सिंह ने यह कहकर कि यदि जदयू सुप्रीमो ने कहा तो लोकसभा चुनाव लड़ विजयश्री हासिल करूंगा. इस बयान ने चुनाव को काफी रोचक बना दिया है. इस लोकसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार के आधार मत के बगैर कोई भी राजपूत उम्मीदवार लोकसभा नहीं पहुंच सका है. जदयू यदि राजपूत उम्मीदवार को मैदान में उतार देगी तो यह परिणाम काफी रोचक हो जाएगा.

आम आदमी पार्टी भी इस क्षेत्र में दस्तक दे रही है. इस पार्टी के भाजपा के ही दो बड़े नेता व एक राजद के पूर्व प्रवक्ता संगठन को खड़ा कर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. भाजपा के प्रदेश किसान मोर्चा के पूर्व नेता परमात्मा सिंह क्षेत्र में सघन दौरा कर रहे हैं. वहीं उमेश्वर सिंह मुन्नी और प्रोफेसर लालबाबू यादव भी आप के जप में पूरी ताकत से लगे हैं. वहीं राजद की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद सुप्रीमो की पुत्री मीसा भारती सहित किसी परिजन के ही मैदान में आने के कयास लगाए जा रहे हैं. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अशोक कुशवाहा व पार्थ यादव पार्टी के आधार मतों कि चर्चा करते हुए बताते हैं कि हमारे समर्थन के बिना कोई दिल्ली नहीं पहुंच सकता. जबकि कांग्रेस नेता व जिला समन्वयक अनिल कुमार सिंह भी अपने संगठनात्मक ढांचे के आधार पर यूपीए उम्मीदवार की ही जीत को पक्का बता रहे हैं. यदि भाजपा, जदयू व राजद, कांग्रेस स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं व समाज के प्रबुद्ध वर्ग से फीडबैक लेकर प्रत्याशियों का चयन करती हैं, तो सारण का लोकसभा चुनाव त्रिकोणात्मक हो जाएगा व परिणाम आश्चर्यजनक होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

अधर में जलापूर्ति योजना

यशवंत कुमार सिंह

feedback@chauthiduniya.com

नदियों को जोड़ने व राज्य के प्रत्येक गांवों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का दावा किया था बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने. लेकिन उनके ही गृह जिले में प्यासों को भी पानी नहीं मिल रहा है. ठेकेदारों की मनमानी व अभियंताओं की कार्य संस्कृति ने मंत्री जी के दावों की हवा निकाल दी है.

इस संदर्भ में ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत जलमीनार के निर्माण कार्य में व्यापक अनियमितता व लूट का खुलासा सूचना कार्यकर्ता व इनौस जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा मांगी गई सूचना से हुई है. लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल समस्तीपुर क्षेत्र के जटमलपुर गांव में जलापूर्ति योजना अन्तर्गत जलमीनार के निर्माण कार्य का आवंटन संवेदक राकेश कुमार को दिया गया था. इस योजना के शुरुआत की तिथि 10 जुलाई 2012 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 9 अप्रैल 2013 तक थी. 10 माह में पूरा होने वाले जलमीनार निर्माण कार्य जनवरी 2014 बीत जाने पर भी पूरा नहीं हो सका है. उक्त कार्य को करने हेतु अवर प्रमंडल पदाधिकारी लोक स्वास्थ्य अवर प्रमण्डल समस्तीपुर ने संवेदक को कई बार पत्र लिखा. 17 दिसंबर 2012 पत्रांक संख्या- 1002, 24 मार्च 2013 को पत्रांक संख्या- 121 एवं 15 जुलाई 2013 को पत्रांक संख्या- 252 द्वारा संवेदक को कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया. परन्तु उक्त संवेदक ने अभियंता के बार-बार लिखित आदेश की अवहेलना की. कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल समस्तीपुर के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य पूरा नहीं किए जाने पर सहायक अभियंता को संवेदक को काली सूची में डालने हेतु पत्र प्राप्त हुआ. इसी संवेदक को ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन के विशेष मरम्मत कार्य 26 मई 2010 से 25 जून 2011 के बीच 2842 मीटर लंबी पाईप लाईन की करनी थी लेकिन 570 मीटर का ही मरम्मत कार्य किया जा सका है, बाकी कार्य करने हेतु सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल समस्तीपुर द्वारा संवेदक को कई बार लिखा जा चुका है. पाइप लाईन का मरम्मत नहीं होने से रिसाव के कारण प्रत्येक दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है. जबकि संवेदक को जल मीनार निर्माण कार्य हेतु 8,98,092 रुपये एवं पाइप लाईन मरम्मत कार्य हेतु कुल 2,31,788 रूपये भुगतान किया जा चुका है. जिले के हरपुर एलौथ में भी इसी संवेदक द्वारा 4620 मीटर पाइपलाईन बिछाना था, जबकि 1590 मीटर पाइप लाईन ही बिछाई जा सकी है. यह कार्य 25 मई 2010 से 5 मई 2011 के बीच ही पूरा हो जाना था.

सहायक अभियंता समस्तीपुर ने संवेदक को शेष कार्य करने हेतु 6 मई 2012 को पत्रांक संख्या 444 द्वारा, 8 अगस्त 2012 को पत्रांक संख्या 683 द्वारा, 31 अक्टूबर 2012 को पत्रांक संख्या 863 द्वारा एवं 17 जनवरी 2013 द्वारा व 26 फरवरी 2013 को भी बार-बार रिमाइन्डर दिया गया. संवेदक को कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति योजना को 6 माह तक चलाया जाना भी था परन्तु 15 दिनों तक ही इसे चलाया जा सका. संवेदक को हरपुर एलौथ ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जलमीनार व पाइप लाईन बिछाने वास्ते 1,30,20,386 रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है. बताते चलें कि अभियंताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत का ही नतीजा है कि काली सूची में डालने की अनुशंसा के बाद भी उक्त संवेदक द्वारा काम लिया जा रहा है. मंत्री के गृह जिले में जलपूर्ति योजना की यह दुर्दशा है तो सूबे के अन्य जिले व गांवों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है. सूचना कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2013 को पत्रांक संख्या- 56 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल समस्तीपुर से मांगी गई सूचना के जवाब दिनांक 9 दिसंबर 2013 पत्रांक संख्या 1753 एवं 1754 यह बताने के लिए काफी है कि जबतक जलापूर्ती योजना में सुधार नहीं होगा कृषि रोड मैप कारगर नहीं होगा. यह जान लें कि इसके लिए कई बार सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन भी किया. लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है. ■

एक नज़र

सुभाष चन्द्र बोस की जयंती मनी

आजाद हिन्द फौज के संस्थापक नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पूर्वी चंपारण में मनायी गई और उनकी जीवनी पर विस्तार से चर्चा की गई. सुभाष पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्हें शिद्दत से याद किया गया. मौके पर बंगला इन्स्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉ. देवाशीष मुखर्जी, जॉर्ज ऑरवेल कमेमोरेटिव कमेटी के अध्यक्ष देव प्रिय मुखर्जी, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश चौधरी, सुप्रिया मित्रा, जितेन्द्र प्रसाद, अभय कुमार ,मुकेश कुमार, सुमित मित्रा, निरूपमा कुमार सिन्हा, श्याम सुन्दर राम, डा. भाष्कर राय, डॉ. ए कुमार, अर्पण मुखर्जी, अभिजीत दास, मनिन्द्र नाथ दास, राम कुमार, नील राय, आयुश दास, विश्वजीत मुखर्जी, अम्बर राय, आदि उपस्थित थे. मौके पर रक्त दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां बीस सदस्यों ने रक्त दान किया.

– *इंतेजारुल हक*

भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन

प्रखंड व अंचल कार्यालय में बढ़ते भ्रष्टाचार व घूसखोरी पर रोक लगाने, पीएचसी में महिला चिकित्सक का नियुक्ति करने, बिजली से वंचित गांवो को बिजली से जोड़ने, बाढ़ एवं सुखे पीड़ित किसानों के सभी ऋण माफ करने सहित 24 सूत्रीय मांगों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी. उक्त बातें राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश महासचिव डॉ. उर्मिला ठाकुर ने परबत्ता प्रखंड मुख्यालय स्थित धरना एवं आमरण अनशन को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में भारी लूट-खसोट चल रही है. सभी महादलित परिवारों को तीन डिसमील जमीन उपलब्ध कराने सहित बंद पड़े सभी नलकूपों को चालू कराने की मांग की. श्रीमति ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मुद्दों पर विफल साबित हो रही है. धरना की अध्यक्षता कर रहे राजद के प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश्वर दास ने कहा कि नीतीश की सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार बन कर रह गई है. मौके पर जितेन्द्र यादव, दशरथ दास, अंजनी यादव, उमेश शर्मा, राय बहादुर यादव, विलाश मुनी, मसहरू मुनी, सहदेव पंडित सहित अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

शिक्षक नेता आप में शामिल

भ्रष्टाचार, राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ तथा स्वराज स्थापना को लेकर दिल्ली में लोगों ने जो जज्बा दिखाया है, उससे भी बढ़कर बिहार में आम आदमी पार्टी की आंधी चलेगी. उक्त बातें शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा. उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में आप की हवा चल रही है. मौके पर विप्लव रंधीर सहित दर्जनों लोगों ने आम आदमी की सदस्यता ग्रहण किया.

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

इंडियन पब्लिक स्कूल गुलाब नगर बाजार समिति खगड़िया के प्रांगण में विद्यालय के सातवीं वर्षगांठ को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें स्कूल के दर्जनों छात्र-छात्राएं अंजली, रीचा, अनुपम, सोनम, नीरज आदि ने नृत्य प्रस्तुत किया. वहीं कार्यक्रम की शुरूआत अंजली के द्वारा प्रस्तुत गीत मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, रीचा, तान्या एवं पलक कुमारी के द्वारा राधा तेरी चुनरी पर नृत्य करके लोगों को खूब झुमाने का काम किया. कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रो. अरविन्द कुमार सिंह, विशेष अतिथि प्राणेश कुमार ने विद्यालय के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय के निदेशक विकास कुमार के ही अथक प्रयास के ही परिणाम हैं कि गुणवत्ता शिक्षा, क्विज प्रतियोगिता, खेल-कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर और समय-समय पर गरीब असहाय एवं मेधावी छात्र-छात्राओं के विकास के लिए निशुल्क विद्यालय में नामांकन व शिक्षा दान की जो मिसाल कायम की है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

प्रतियोगिता सम्पन्न

गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन से लेकर दर्जनों विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जहां जेएनकेटी इंटर विद्यालय के प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया. वहीं एनपीएस पब्लिक स्कूल उत्तरी राजेन्द्र नगर खगड़िया में विद्यालय के प्राचार्य व व्यवस्थापक अभिनन्दन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में क्विज प्रतियोगिता का महासंग्राम बच्चों और अभिभावकों के बीच आयोजित कर एक नई मिसाल कायम की है. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक उपेन्द्र कुमार सहनी एवं सहकारिता बैंक के अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों एवं अभिभावकों के बीच जिले में पहली बार देखने को मिला है. कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय डोली कुमार, आराधना कुमारी, ज्योति कुमारी, कुणाल कुमार, मुकेश कुमार, महेश कुमार, साक्षी कुमारी सहित अन्य छात्र एवं छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

धरना आयोजित

एसटीईटी एवं टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन संघ के जिलाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित कुमार ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण तृतीय चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है कि नियोजन प्रक्रिया स्थगित करने की घोषणा कर शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार ठगने का काम रही है. जिला सचिव बृजेश कुमार ने कहा कि अगर जल्द ही नियोजन प्रक्रिया पूरा नहीं किया जाता है तो जिले में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा. इस अवसर पर भावेश कुमार सुमन, अमलेश, अजय, विकास, ललन, अमर, विभाष कुमार सहित दर्जनों शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित थे. – *नन्द किशोर शर्मा*

आपका शानदार घर बर्बाद ना हो !

घर बनाने से पहले आइये कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें

- क्या आप जानतें हैं बिल्डिंग मेटेरियल्स पर करीब 28 से 30 परसेन्ट टैक्स लगा रहता है। सभी अच्छी कम्पनी का सामान का वैट बिल लेने पर आपको कोई टैक्स देना नही पड़ता है। सभी अच्छी कम्पनियां सभी टैक्स पेड माल अपने डीलर या रिटेलर को सप्लाई करती है।
- आप अपना घर बनाने में अगर 25 लाख खर्च करते हैं तो उस पर करीब 7 लाख टैक्स भारत सरकार एवं राज्य सरकार को मिलता है। जो वापस आपके लिए ही सरकार खर्च करती है।
- आप बिल्डिंग मेटेरियल्स खरीदते समय वैट बिल नही लेते हैं तो आपका रुपया तो जाता ही है, आपको नकली सामान भी मिलता है, जैसे आप 20 किलो का वॉल पुटटी जिस पर कीमत रु0. 800 लिखा है उस पर कम्पनी रु0.69 एक्साईज डयूटी एवं वैट 96 रुपया टोटल 165 रु0 टैक्स कम्पनी लिए हुए रहती है। परन्तु आपके छोटी सी भूल से आप बिना वैट बिल का नकली सामान खरीद लेते हैं। जिससे जिस सामान की लाईफ 10 साल होनी चाहिए वह सामान साल भर में ही खराब होने लगता है। अपने शानदार घर को बर्बादी से बचाने के लिए सभी सामान का वैट बिल अवश्य ले लें। आपकी सावधानी से आपके घर की लाईफ कई गुणा बढ़ जायेगी।

राजस्थान के चुनिन्दा जिप्सम से बना बेहतरीन क्वालिटी का

विश्वस्तरीय क्वालिटी एवं पैकिंग में

ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस

Made from Imported Chemicals

ITALIAN Beauty Wall Putty

ईम्पोंटेड केमिकल से तैयार क्वालिटी एवं पैकिंग में भारत का नं0 1 वॉल पुटटी

सबसे किफायती 40 किलो पैक

ईटालियन ईन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण पेरिस की अपेक्षा आपके दीवारों एवं मकानों को ज्यादा सुन्दर बनाता है ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादा बारीक होने के कारण यह ज्यादा फैलता है, कड़े क्वालिटी कन्ट्रोल में बना हुआ सुपर स्ट्रौंग, सुपर स्ट्रैंथ एवं सुपर कवरेज वाला भारत का सबसे बेहतरीन ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस ।

लक्की ड्रॉ में 1 किलो 24 कैरेट सोना

24 कैरेट 10 ग्राम सोने का 100 सिक्का 100 लोगों को

डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप

अपने फर्म का नाम पूरा पता एवं वैट नं० के साथ एस.एम.एस या मेल करें

Mob-09549663640 E-mail- shalimarpop@gmail.com *शर्तें लागू

प्लास्टर ऑफ पेरिस

- प्लास्टर ऑफ पेरिस खरीदते समय बोरी का वजन जरुर चेक करें, क्योंकि साधरण प्लास्टर ऑफ पेरिस 20 किलो के बोरी में 16 किलो ही आता है, बिना वैट बिल का प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिटटी मिला हो सकता है। जिससे आपके फाल्स सिलींग या पी0 ओ0 पी0 का काम साधारण क्वालिटी का होगा।।।।।
- प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके पूरे घर की सुन्दर पेन्टिंग का बेस होता है, अगर वही साधारण क्वालिटी का होगा तो आपके कीमती पेन्टिंग का भविश्य क्या होगा आप खुद सोचिये ।।।।
- ईटालियन व्हाईट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो साधारण प्लास्टर ऑफ पेरिस की तुलना में दुगुणा फैलता है, शानदार क्वालिटी शानदार पैकिंग साथ ही 1 किलो 24 कैरेट सोना* के साथ।

वॉल पुटटी के बारे में जानिए

वॉल पुटटी के बोरी में अधिकतर कम्पनियां रुपये का कूपन डालती है जांच करें बिना वैट बिल का वॉल पुटटी नकली हो सकता है, जिसमें केमिकल की सही मात्रा नही होती है, जबकि असली वॉलपुटटी में केमिकल 200 से 450 रुपये किलो का लगता है, एक बोरी ऑरिजीनल वाल पुटटी पर करीबन 200 रुपये टैक्स लगा रहता है जो सभी कम्पनी को देना होता है लेकिन नकली माल बनाने बाले टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन आपसे पूरा कीमत वसूल लेते हैं। आपकी जरा सी सावधानी से वैट बिल के साथ खरीदारी पर आप हमेशा असली सामान ही खरीदेगें।

प्रिय ग्राहक कृपया ध्यान दें

हमारी कम्पनी सभी माल टैक्स पेड देती है, आपको अलग से कोई टैक्स नही देना है, ऑरिजीनल सामान के लिए वैट बिल अवश्य ले लें तभी आप 1 किलो सोना के लक्की ड्रा स्कीम में शामिल हो सकते हैं।

अपने देश हित में, अपने राज्य हित में वैट बिल अवश्य लें
वैट बिल लेना आपका अधिकार है, ओरिजीनल सामान की पहचान है।

Required: Sales Manager & Asst. Sales Manager for Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, M.P., Chhatisgarh, Haryana. Punjab, Bihar, Jharkhand, J&K, U.P, Mumbai, Delhi & Himachal Experienced person with P.O.P. marketing knowledge. Send Resume by mail only. e-mail. shalimarpop@gmail.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

Breastriim Oil

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें 9304291051

किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें।

REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

> अरुण इस बात से सहमत नहीं हैं कि पार्टी का जनाधार खिसका है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि भाकपा को दूसरे दलों से गठबंधन नहीं करना चाहिए. अरविंद प्रसाद कहते हैं कि स्वर्गीय झा की वास्तविक श्रद्धांजलि तब ही मानी जा सकती है जब उनका सपना पूरा होगा. इसके लिए जरूरी है कि कोसी के वराह क्षेत्र में प्रस्तावित हाई डैम निर्माण को अविलम्ब पूरा कराने की दिशा में पार्टी आंदोलन करे.

निर्माण कंपनी कर रही किसानों की हकमारी

वाल्मीकि कुमार

भूमि अधिग्रहण और उससे जुड़ी समस्याएं बिहार के लगभग हर जिले में है. हाल के कुछ सालों में जहां-जहां भी औद्योगिक निर्माण के लिए किसानों से जमीन ली गई वहां से भी विरोध की खबरें आईं. उचित मुआवजे का नहीं मिल पाना, निर्माण कंपनियों की मनमानी के साथ-साथ कई मसले आए दिन चर्चा में रहते हैं. निर्माण कंपनियों की मनमानी और स्थानीय प्रशासन की ला-परवाही की वजह से पनपा असंतोष हिंसक विरोध में बदल जाता है. इसके कई उदाहरण भी हैं. ऐसा ही एक मामला सीतामढ़ी जिले में हो रहे अघवारा तटबंध के निर्माण कार्य का है. किसानों के हक की अनदेखी को लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार केंद्र ने निर्माण एजेंसी के खिलाफ डीएम को स्मरण पत्र देकर निदान की गुहार लगाई थी. तकरीबन एक माह बाद तक कोई परिणाम सामने नहीं आने पर केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद नवल किशोर राय ने पुन: डीएम से मुलाकात की है. ऐसी सुगबुगाहट जोर पकड़ने लगी है कि हजारों किसानों की परेशानी को लेकर केंद्र के बैनर तले व्यापक सत्याग्रह एवं आंदोलन किया जाएगा.

डीएम डॉ. प्रतिमा एस वर्मा

बताते चलें कि सरकारी फरमान के बाद भी अघवारा समूह की नदियों पर तटबंध निर्माण का कार्य जोरों पर है. इतना ही जोर निर्माण कार्य के कार्य प्रणाली को लेकर सत्याग्रह व आंदोलन की तैयारी पर है. पिछले 4 दिसंबर को जन नायक कर्पूरी ठाकुर विचार केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद नवल किशोर राय ने डीएम डॉ. प्रतिमा एस वर्मा को एक स्मार पत्र सौंपा था. जिसमें डीएम को यह बताया गया था कि सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में अघवारा समूह की प्रमुख नदी माधोपुर तुरकौलिया पंचायत से पुपरी प्रखंड के हरदिया पंचायत की अंतिम सीमा रामपुर पचासी गांव तक नदी के दोनों तरफ पुराने तटबंध का पुनर्निर्माण जल संसाधन मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा कराया जा रहा है. निर्माण कार्य में लगी ब्रम्हपुत्र कंस्ट्रक्शन द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत भी की गई थी. परंतु एक माह बीतने के बाद भी उक्त मामले में स्थानीय प्रशासन ने कोई खास रुचि नहीं ली है. वहीं दूसरी ओर संबंधित क्षेत्र के किसान अपनी दशा पर चिंतित हैं. सौंपे गए स्मार पत्र में बताया गया था कि प्राकल्लन के हिसाब से मिट्टी नहीं दी गई है. जिसका खुलासा विविध प्राकल्लन के हिसाब से जांच करने पर स्पष्ट होगा. कम्पैक्शन पर सवाल उठाते हुए बताया गया था कि प्राकल्लन के हिसाब से हर प्रथम फीट

बसहा गांव के पीड़ित किसान

सरकारी फरमान के बाद भी अघवारा समूह की नदियों पर तटबंध निर्माण का कार्य जोरों पर है. इतना ही जोर निर्माण कार्य के कार्य प्रणाली को लेकर सत्याग्रह व आंदोलन की तैयारी पर है. पिछले 4 दिसंबर को जन नायक कर्पूरी ठाकुर विचार केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद नवल किशोर राय ने डीएम डॉ. प्रतिमा एस वर्मा को एक स्मार पत्र सौंपा था. जिसमें डीएम को यह बताया गया था कि सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में अघवारा समूह की प्रमुख नदी माधोपुर तुरकौलिया पंचायत से पुपरी प्रखंड के हरदिया पंचायत की अंतिम सीमा रामपुर पचासी गांव तक नदी के दोनों तरफ पुराने तटबंध का पुनर्निर्माण जल संसाधन मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा कराया जा रहा है.

पूर्व सांसद नवल किशोर राय

मिट्टी पर पानी व रोलर का प्रयोग भी नहीं किया गया है. भारत सरकार की पुस्तिका इंडियन स्टैंडर्ड में वर्णित मिट्टी काटने के मापदंड का उल्लंघन का आरोप निर्माण एजेंसी पर लगाते हुए बताया गया था कि मार्गदर्शिका को पूर्णत: किनारा कर कार्य कराया जा रहा है. मार्गदर्शिका के अनुसार नदी के तटबंधों के निर्माण में नदी या कंट्री साइड दोनों ही तरफ लगभग 80 मीटर के अंदर मिट्टी काटने पर रोक है. कारण कि इससे तटबंध को कमजोर होने की संभावना के साथ ही नदी का धारा भी बदलने की उम्मीद बढ़ जाती है. स्मार पत्र में यह भी कहा गया था कि अब तक प्रोजेक्ट के तहत जितना भी काम हुआ है, उसमें 80 प्रतिशत मिट्टी किसानों की लहलहाती फसलों वाली जमीन जो तटबंध के किनारे हैं इससे काटी गई है. नतीजतन लाखों रुपये मूल्य की फसल बर्बाद हुई है. किसानों के खेत गैर उपजाऊ जमीन में तब्दील हो गए हैं. हद तो यह है कि किसानों की सहमति के बगैर काटी गई मिट्टी का अब तक किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया गया है. वहीं विरोध करने वाले किसानों को भयभीत किया जा रहा है. विचार केंद्र ने डीएम से उच्चस्तरीय जांच टीम का गठन कर 15 दिनों के अंदर मामले की जांच कराने एवं किसानों को मुआवजा के साथ सुरक्षा दिलाने की मांग की थी. साथ ही मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह भी डीएम से किया था. जब दो माह बाद तक स्थानीय प्रशासन के स्तर पर कोई विशेष रुचि नहीं ली गई तब पुन: केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष ने 3 फरवरी को एक स्मार पत्र डीएम को सौंपा है. इस बार यह भी बताया गया है कि निर्माण एजेंसी द्वारा किसान राम विलास राय, भाग्यनारायण यादव, वीरेंद्र कुमार व हरेंद्र कुमार को पुलिस बल का दुरुपयोग कर धमकाया जा रहा है. केंद्र ने अगाह करते हुए साफ तौर पर कहा है कि अगर किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया तो संगठन के बैनर तले व्यापक स्तर पर सत्याग्रह व आंदोलन शुरू करने से परहेज नहीं करेगी. इधर केंद्र से जुड़े कार्यकर्ताओं की बातों पर यकीन करें तो जन समस्याओं के निदान समेत अन्य मसलों को लेकर केंद्र वृहद स्तर पर आंदोलन की तैयारी में गुप-चुप तरीके से लगा है. संभव है कि अबकी बार का आंदोलन वर्ष 1998 के समाहरणालय गोली कांड को भी पीछे छोड दे. कुल मिला कर जिले में आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. वहीं राजनीतिक गलियारों में चुस्की लेने वालों की बातों पर यकीन करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर तकरीबन सभी दल के नेता व कार्यकर्ता अपने-अपने स्तर से जन समस्याओं का चिट्ठा तैयार करने में लग गए हैं. अब देखना यह है कि किस दल का नेता अपनी नेतागिरी का परचम किस हद तक लहरा पाता है. वैसे विचार केंद्र इस मसले को गैर राजनीतिक रूप में मजबूत आंदोलन का रूप देने का प्रयास कर रही है. ऐसे में वर्तमान जिला पदाधिकारी किस हद तक मसले का निदान में सफल हो पाते हैं यह तो समय ही बतागा. परंतु इतना तो साफ है कि अगर आंदोलनों की श्रृंखला बढ़ी तो जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के लिए सरदर्द साबित हो सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रबंधन की मनमानी से कर्मचारी हलकान

अवधेश कुमार शर्मा

पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज स्थित न्यू स्वदेशी शुगर मिल में प्रबंधन की धांधली इनदिनों चरम पर है. यहां कार्यरत कर्मचारियों व मजदूरों का केवल शोषण ही नहीं किया जाता है बल्कि विरोध करने वालों को बाहर का रास्ता भी प्रबंधक दिखा देती है. खुलेआम औद्योगिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रशासनिक पदाधिकारी जान कर अनजान बने हुए हैं. हालत यह है कि मिल प्रबंधन किसी को भी कभी भी बाहर का रास्ता दिखा देता है. यहां तक कि कर्मियों से स्पष्टीकरण तक नहीं पूछा जाता है.

कर्मचारी मदन किशोर श्रीवास्तव, विनोद कुमार व पवन कुमार आदि के साथ हुई घटना प्रबंधन के मनमानी को उजागर करती है. जानकार बताते हैं कि मिल प्रबंधन ने मदन किशोर को 22 फरवरी को 2001 को मैनेजर पर धमकी देने के आरोप में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए चार्जशीट दे दी और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया. घरेलू जांच की प्रक्रिया चालू सत्र में ही समाप्त करने का प्रावधान औद्योगिक अधिनियम के तहत है. जबकि यह मामला चार वर्षों तक जांच के नाम पर चलता रहा और 2004 के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया. राज्यपाल की टिप्पणी भी श्रम न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी को सौंपा गया किन्तु इसपर भी कार्रवाई नहीं हुई. इसी तरह का मामला सीजनल (मौसमी कर्मचारी) क्लर्क विनोद कुमार का है. उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में जिले में ख्याति पाने वाले विनोद कुमार को मिल प्रबंधन ने 1988-1989 से अपनी कंपनी में काम लेना प्रारम्भ किया. बेहतर काम को देखते हुए मिल प्रबंधन द्वारा 01 फरवरी 1994 को मौसमी कर्मी के रूप में स्थायी तौर पर उनकी नियुक्ति कर दी. करीब 17 वर्ष तक स्थायी तौर पर निष्ठापूर्वक काम करने वाले विनोद कुमार व पवन कुमार शर्मा पर प्रबंधन की निगाहें टेढ़ी हो गई. बताते चलें कि वित्त विभाग के कार्यपालक उपाध्यक्ष बनवारीलाल हिम्मत सिंह और लेखा प्रबंधक मुकेश कुमार झुनझुनवाला के बीच आपसी रंजिश चल रही है. जानकार बताते हैं कि उपाध्यक्ष हिम्मतसिंह ने पवन को अपने कार्यालय में बुलाकर मुकेश कुमार झुनझुनवाला और विनोद कुमार के विरुद्ध लिखित बयान देने का दबाव बनाया. किन्तु विनोद ने लिखित देने से इंकार कर दिया तब मामला आगे बढ़ गया और इसी के बाद से उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. उधर विनोद कुमार से बिना पत्रांक के एक पत्र दिनांक 26 अप्रैल 2011 द्वारा गन्ना भुगतान के कुछ प्रपत्र कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. जिसका जवाब विनोद ने दिनांक 28 अप्रैल 2011 को दिया और अवगत कराया कि उन्होंने पेआॅफ होने के पूर्व ही प्रधान लिपिक अवधेश सिंह को सारे प्रपत्र(वाउचर) जमा कर दिए थे. इसके बाद प्रबंधन ने पत्रांक 942 दिनांक 16 मई 2011 द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया. निलंबन पत्र के डाक से 28 मई 2011 को मिलने के बाद 30 मई 2011 को पुन: सिजनल कर्मचारी ने जवाब में नियमानुसार प्रक्रिया के तहत दस्तावेज प्रबंधन को दिए. इसके बाद से साढ़े छह माह तक प्रबंधन ने इस बावत कोई पत्राचार उक्त कर्मी से नहीं किया. प्रबंधन ने पुन: पेराई सत्र 2011-2012 में दिनांक 14 दिसंबर 2011 से विनोद को ड्यूटी पर लगा दिया. इसके बाद 22 दिसंबर 2011 को पुन: बनवारीलाल हिम्मत सिंह ने पत्रांक 517 द्वारा दिए गए जवाब को संतोषजनक नहीं बताते हुए 72 घंटे में फिर से पुराने वाउचर की मांग की. पीड़ित कर्मचारी ने इस पत्र का जवाब 24 दिसम्बर 2012 को दिया. इसके बाद प्रबंधन ने पत्रांक 535 दिनांक 28 दिसम्बर 2011 द्वारा कंपनी के स्थायी आदेश की धारा 47 (ग)(त)(ज) के माध्यम से घरेलू जांच का निर्देश देते हुए पुन: निलंबित कर दिया. गौरतलब है कि कंपनी एक्ट के तहत घरेलू जांच के दौरान मामले का निपटारा मौसमी कर्मचारी के मामले में इसी पेराई सत्र में पूरी कर लेने का प्रावधान है. लेकिन पवन कुमार शर्मा और विनोद कुमार से जुड़े इस मामले की जांच करीब 19 माह में पूरी हुई. जांच के दौरान जब विनोद कुमार ने आरोप को गलत ठहराने संबंधी सुबूत पेश किया तब इस वर्ष 2008-09, 2009-2010 का वाउचर नहीं मिलने का मामला बनाकर कार्यपालक अध्यक्ष चन्द्रमोहन ने शिकारपुर थाने में दिनांक 26 अगस्त 2010 को एक सनहा दर्ज करा दिया. उल्लेखनीय है कि वित्त प्रबंधक मुकेश कुमार झुनझुनवाला ने बनवारीलाल हिम्मत सिंह के वित्तीय अनियमितता में सहयोग नहीं किया और पवन ने इनकी बात नहीं मानी, पवन व विनोद घनिष्ट मित्र हैं. इसके अलावा भी मिल प्रबंधक की मनमानी की शिकायतें आती रहती हैं. ■

विनोद कुमार

मदन किशोर

पवन शर्मा

feedback@chauthiduniya.com

आत्ममंथन से दूर भाकपा

कपिल कुमार

भोगेंद्र झा की पहचान देश भर के बड़े कम्युनिस्टों में रही है. उनके नाम ढेरों उपलब्धियां भी हैं. कहा जाता है कि उनकी पहचान मात्र एक दल के नेता के तौर पर ही नहीं थी. वे सभी के लिए एक समान प्रिय थे. पिछले दिनों मधुबनी में भाकपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया. ऐसे में यह उम्मीद की जा रही थी कि भाकपा आत्मविश्लेषण करेगी और अपनी चूक पर चर्चा करेगी, भविष्य की रणनीति पर विचार करेगी. लेकिन दुर्भाग्यवश यह सब नहीं हुआ. हुई तो सिर्फ भाषणबाजी. वक्ताओं का ध्यान सिर्फ इस ओर ही लगा रहा कि कैसे इस बात को प्रमाणित करें कि वे उनके कितने करीब थे.

प्रसिद्ध स्वतंत्रा सेनानी और पूर्व सांसद डॉ. भोगेन्द्र झा की पांचवी पुण्यतिथि पर स्थानीय भाकपा कार्यालय में कुछ ऐसा ही करते नजर आए भाकपा के नेता व कार्यकर्ता. सभी ने उनके त्याग और बलिदान की चर्चा की. लेकिन इस बात पर मंथन नहीं हुआ कि आखिर कैसे सर्वहारा वर्ग के अंदर झा ने पार्टी को मजबूत जनाधार दिलाया. आखिर कैसे कामरेड भोगेंद्र सर्वहारा के लिए भोगेंद्र भगवान हो गए. बताते चलें कि जनता ने उन्हें एक-दो बार नहीं अपितु पांच बार लोकसभा का सदस्य भी बनाया था. उनकी मेहनत और त्याग का ही प्रतिफल था कि मधुबनी को पार्टी के लिए सुरक्षित गढ़ के तौर पर जाना जाता था. वर्तमान में वह कारण क्या हैं कि पार्टी यहां दम तोड़ती नजर आ रही है, मंथन इस बात पर भी नहीं हुई. इलाके के बुद्धिजीवियों का मानना है कि धीरे-धीरे भाकपा सरोकार और संघर्ष के मुद्दे से दूर होती चली गई और यही वजह रही कि पार्टी से सर्वहारा और मेहनतकश दूर होते चले गए. लेकिन उन कारणों पर मनन करने की बजाए नेता कुछ और ही कर रहे थे. जिला मंत्री डॉ. हेमचंद्र झा का मानना हैं कि पिछले चुनाव में हमें कुल मतदान का 10 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुआ था. ऐसी स्थिति पिछले तीन लोकसभा से चली आ रही है. झा का मानना है कि दूसरे दलों के द्वारा धर्म और जाति की राजनीति की जाती है इसी वजह से पार्टी पर प्रतिकूल असर पड़ा है. झा की इस बात से पार्टी के ही कई सदस्य सहमत नहीं दिखते हैं. अरुण कुमार ठाकुर सीपीआई के अधिवक्ता शाखा के सहायक सचिव हैं. उनका मानना है कि पार्टी ने जनसरोकार से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना बंद कर दिया है और खुद को आंदोलनों से दूर कर लिया है. अरुण का मानना है कि अब भी जिले में कई तरह की समस्याएं हैं मसलन बिजली और इसके फर्जी बिल की समस्या, चिकित्सा की समस्या, मनरेगा में लूट, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या आदि और इन सब पर पार्टी को आंदोलन करना चाहिए. अरुण इस बात से सहमत नहीं हैं कि पार्टी का जनाधार खिसका है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि भाकपा को दूसरे दलों से गठबंधन नहीं करना चाहिए. पार्टी के वरिष्ठ नेता व जिला सचिव मंडल सदस्य अरविंद प्रसाद कहते हैं कि स्वर्गीय झा की वास्तविक श्रद्धांजलि तब ही मानी जा सकती है जब उनका सपना पूरा होगा. इसके लिए जरूरी है कि कोशी के वराह क्षेत्र में प्रस्तावित हाई डैम निर्माण को अविलम्ब पूरा कराने की दिशा में पार्टी आंदोलन करे. और अगर ऐसा होता है तो नेपाल सहित संपूर्ण मिथिला को बाढ़ और सूखे जैसी गंभीर समस्या से न सिर्फ स्थायी निदान मिल जाएगा अपितु बिजली की समस्या से भी निदान मिलेगा. वे कहते हैं कि भोगेंद्र झा अंतिम समय तक इस बात को लेकर चिंतित थे लेकिन अब पार्टी इस मुद्दे से बचना चाह रही है. यह भी एक सत्य है कि पार्टी ने इनके जीवन काल में ही उनके त्याग और बलिदान को अधिक महत्व नहीं दिया और गठबंधन और राजनीतिक दबाव को मानते हुए उन्हें लोकसभा के टिकट से वंचित कर चतुरानंद मिश्र को अपना उम्मीदवार बनाया और यह कदम आगे चलकर पार्टी के लिये आत्मघाती बन गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

17 फरवरी –23 फरवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

संजय सक्सेना

यूपी भाजपा की झोली में गिरे कई 'नगीने'

मोदी लहर ने उत्तर प्रदेश भाजपा को 'मालामाल' कर दिया है. इसकी झोली में तमाम ऐसे 'नगीने' आ गए हैं, जिनके सहारे आम चुनाव की वैतरणी पार करना इसके लिए और भी आसान हो सकता है. हवा का रुख़ भांप कर विभिन्न दलों के तमाम नेता भाजपा की छत्रछाया में आ गए हैं. बाहर से आकर भगवा खेमे को मजबूती देने का सिलसिला अभी तो मात्र चल भर रहा है, चुनाव की तारीख आते-आते आगे इसमें और तेजी आ सकती है.

उत्तर प्रदेश भाजपा नेताओं के चेहरे गदगद हैं. इन्हें लगता है कि राज्य में भाजपा का सुनहरा दौर लौटने वाला है. आम आदमी पार्टी का खतरा भी जो कम हो गया है. विधानसभा चुनाव के बाद जो संकेत मिल रहे थे, इससे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी (आप) यूपी में भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है, लेकिन पिछले एक माह में हालात तेजी से बदले हैं.'आप' की छवि और नियत अब बेदाग नहीं रह गई है. इस बात का प्रमाण है राज्य में 'आप' का सदस्यता अभियान का धीमा पड़ना. 'आप' से टिकट चाहने वालों के भी ग्राफ में कमी आई है, जो नेता कल तक 'आप' की तरफ उम्मीदों के साथ देख रहे थे, अब उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुड़ गई है. राजनीतिक पटल पर पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे नाम सामने आए हैं, जो भाजपा के साथ या तो जुड़ गए हैं या फिर जुड़ने वाले हैं. इसमें से कई अपनी पुरानी पार्टियों से नाराज चल रहे हैं तो कुछ हासिये पर थे. पूर्व से लेकर पश्चिम तक भाजपा का दामन थामने वाले नेताओं की बाढ़ आ गई है.

मोदी के उभार के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रति आकर्षण का पहला नजारा सपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पेश किया था. बात पूर्व की कि जाए तो कैसरगंज सीट से सपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ही दल के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं. दलबदल कानून इनके पांव थामे हुए है, लेकिन इन्होंने इसका तोड़ निकालते हुए अपने पुत्र प्रतीक भूषण को कमल खिलाने के लिए आगे कर दिया है. ब्रजभूषण परिवार के बाद भाजपा का दामन थामने वालों की लिस्ट में कई नये नाम शामिल हो गए. सिलसिलेवार बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो ताउम्र समाजवाद की पैरोकारी करते रहे लेकिन पिता के विचारों के विपरीत जाते हुए उनके पुत्र पंकज शेखर ने भाजपा का दामन थाम लिया है. पंकज से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं. पंकज के सांसद भाई नीरज शेखर इस बार भी साईकिल की ही सवारी करेंगे. नीरज पिता चन्द्रशेखर की मौत के बाद इनकी विरासत संभाले हुए थे. यह बात दूसरे भाई पंकज को हजम नहीं हो रही थी. सपा में पंकज के लिए कोई जगह नहीं बन रही थी, सो वह भाजपाई हो गए. भोजपुरी गायक मनोज तिवारी पिछला लोकसभा चुनाव गोरखपुर से भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सपा से लड़े थे. इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था. इसके बाद वह दिल्ली में अन्ना के आंदोलन के दौरान इनके साथ खड़े दिखे थे, लेकिन चुनावी बेला में इनको भाजपा रास आने लगी. अब वह मोदी की शान में गीत सुनाते हैं और नमो को पीएम की कुर्सी पर विराजमान करने का बीड़ा उठाये हुए हैं. कुरेदने पर वह कहते हैं कि अगर भाजपा आलाकमान आदेश देता है तो इन्हें चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी.

दो बार विधायक रहे दबंग नेता चंद्रभान सिंह उर्फ सोनू सिंह सुल्तानपुर की सियासत में अच्छी पकड़ रखते हैं. एक संत की हत्या के आरोप भी इन पर लगे. सपा से राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले सोनू बसपा से होते हुए भाजपा में आ गए हैं. टिकट के दावेदारों में वह अपना नाम बताते नहीं तो छिपाते भी नहीं हैं. लालगंज में सपा के एक ताकतवर नेता हुआ करते थे दरोगा प्रसाद सरोज. यहां से दो बार सपा के टिकट से संसद तक में पहुंचे. सपा ने इस बार से इनका टिकट काट दिया. यह बात दरोगा को रास नहीं आई और अब वह मुलायम को कोसते हुए मोदी का गुणगान कर रहे हैं. एक अन्य नेता दुर्गा प्रसाद मिश्र, जो मुलायम सरकार में मंत्री थे, इनको जब लगा कि समाजवादी चोला ओढ़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है तो इन्होंने भी अपनी हसरतों को उड़ान देने के लिए भगवा चोला पहन लिया. गाजीपुर के बसपा नेता और पूर्व विधायक पशुपति नाथ राय का भी नाम भाजपा की गोद में बैठने वालों में शामिल है. राय को बसपा की उठापटक रास नहीं आई तो इन्हें मायावती खामियों का पुतला नजर आने लगीं. कौशाम्बी संसदीय सीट से सांसद रहे अमृतलाल भारती भी यू-टर्न लेते हुए भाजपा में लौट आए हैं. भाजपा छोड़कर बसपा में जाने वाले भारती मोदी मैजिक से काफी प्रभावित लगते हैं.

बात पूर्वांचल की ही कि जाए तो कई दलों का दौरा करके समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले भदोही के ताकतवर नेता रामरति बिंद ने भी चुनावी संध्या में सपा को बाय-बाय कह दिया. भगवा रंग में रंगे बिंद के सहारे भाजपा अति पिछड़ा वोट हासिल करना चाहती है. घोसी क्षेत्र के विधायक रहे फागू चौहान बसपा सरकार में राजस्व मंत्री थे. भ्रष्टाचार के आरोप लगे. इस बार विधायकी का चुनाव हार गए. अब भाजपा से लोकसभा से टिकट की आस लगाए हैं. घोसी से ही वर्ष 1999 में बसपा सांसद रहे बालकृष्ण चौहान भी बहन जी के कोप के बाद सपा की शरण में जाने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट से लड़ना चाहते हैं. बसपा से निष्कासित पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू की बलरामपुर के आसपास अच्छी-खासी पकड़ है. भाजपा में आने से पूर्व वह लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ने की बात कहा करते थे. अभी भी इनके इरादों में कोई परिवर्तन नहीं आया है. राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के नेताओं को भाजपा काफी रास आ रही है. रालोद के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद रहे मुंशीराम का भाजपा के प्रति हृदय परिवर्तन होना इस बात का प्रमाण है. भाजपा लहर में इनको अपना तम्बू उखड़ता दिखा तो हैंडपम्प छोड़कर 'कमल' की पूजा करने लगे. इन्हें उम्मीद है कि इनकी लोकप्रियता का फायदा भाजपा को मिलेगा. मुंशीराम नगीना लोकसभा क्षेत्र से विजय पताका फहरा कर लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं. रालोद में अजीत सिंह के काफी करीबी रहे पूर्व विधायक गजेन्द्र सिंह मुन्ना भी छोटे चौधरी का साथ छोड़कर 'नमो' का जाप कर रहे हैं. मुन्ना की ख्वाहिश है कि लोकसभा चुनाव में अजित सिंह को इनके पराक्रम से पराजय का मुंह देखना पड़ जाए. मुन्ना की तरह ही रालोद के एक अन्य ताकतवर नेता बाबूलाल ने भी रालोद से नाता तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है. वह अपनी मंशा जगजाहिर तो नहीं करते हैं, लेकिन इनके करीबी जानते हैं कि बाबूलाल फतेहपुर या मथुरा में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ने का सपना दिल ही दिल में संजोये हुए हैं. रालोद नेता और बागपत में अच्छी पकड़ रखने वाले पूर्व विधान परिषद सदस्य केपी सिंह पहले ही भाजपाई हो चुके हैं. केपी भी मुन्ना की तरह बागपत से चुनाव लड़कर अजीत सिंह को धूल चटाना चाहते हैं. पश्चिमी यूपी का एक और जाना-माना नाम है ओमवती. ओमवती यानी पूर्व आईएएस आर के सिंह की पत्नी. ओमवती कभी कांग्रेसी हुआ करती थीं. 1985 में वह कांग्रेस के टिकट से पहली बार विधानसभा पहुंचीं. तीन बार एमएलए और एक बार सांसद रह चुकीं ओमवती का जब कांग्रेस से मन हटा तो इन्होंने सपा-बसपा का दामन थाम लिया. बसपा सरकार में मंत्री भी बनीं. बदले हालात ने इनको पति के साथ भाजपा में पहुंचा दिया. ओमवती बिजनौर की इसी नगीना संसदीय सीट का टिकट चाहती हैं, जिस पर मुंशीराम भी दावेदारी ठोंक रहे हैं. मुजफ्फरनगर की जानसठ सीट से विधायक रहे यशवंत सिंह कभी मायावती का गुणगान किया करते थे. माया ने इन्हें वफादारी के ईनाम के तौर पर मंत्री बना कर रखा. बसपा सत्ता से बाहर हुई तो सिंह साहब का बसपा से मोह भंग हो गया. मोदी की लोकप्रियता इन्हें लुभाने लगी. अब वह मोदी के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं. बदायूं के आसपास के जिलों में कभी भगवान सिंह शाक्य भाजपा का एक जाना-पहचाना नाम हुआ करता था. पिछले विधानसभा चुनाव के समय इन्हें लगा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के सहारे वह अपनी वैतरणी पार लगा सकते हैं तो भाजपा से बागी हो गए, लेकिन विधायकी का सपना पूरा नहीं हुआ. गलती का एहसास हुआ तो फिर अपने पुराने घर भाजपा में आ गए. इसी प्रकार हाथरस जिले के सासनी क्षेत्र से तीन बार विधायक चुने गए हरिशंकर माहौर, हरदोई के पूर्व विधायक और सपा नेता सतीश वर्मा, बदायूं के बसपा नेता और पूर्व विधायक रामसेवक पटेल, बसपा से निकाले गए इटावा के नेता तथा पूर्व मंत्री अशोक दोहरे भी नरेन्द्र मोदी के मोहपाश में फंस कर भाजपा में खिंचे चले आए हैं. बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का बीड़ा उठाकर फिल्म जगत को तिलांजलि देने वाले पूर्व कांग्रेसी राजा बुंदेला भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के चमत्कार से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो गए हैं.

तमाम उठापटक के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर लखनऊ से भाजपा के पक्ष में आई. लखनऊ से लगी सुरक्षित लोकसभा सीट पर पांव पसारने के लिए भाजपा ने पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कम्युनिष्ट पार्टी के संस्थापक कौशल किशोर को अपने साथ जोड़ लिया. भाजपा की साम्प्रदायिक सोच पर लगातार सवाल खड़े करने वाले कौशल को किन हालातों में भगवा रंग में रंगना पड़ा, यह किसी से छिपा नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

दो बार विधायक रहे दबंग नेता चंद्रभान सिंह उर्फ सोनू सिंह सुल्तानपुर की सियासत में अच्छी पकड़ रखते हैं. एक संत की हत्या के आरोप भी इन पर लगे. सपा से राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले सोनू बसपा से होते हुए भाजपा में आ गए हैं. टिकट के दावेदारों में वह अपना नाम बताते नहीं तो छिपाते भी नहीं हैं. लालगंज में सपा के एक ताकतवर नेता हुआ करते थे दरोगा प्रसाद सरोज. यहां से दो बार सपा के टिकट से संसद तक में पहुंचे.

पौड़ी में महाराज से भिड़ेंगे दो जनरल

राजकुमार शर्मा

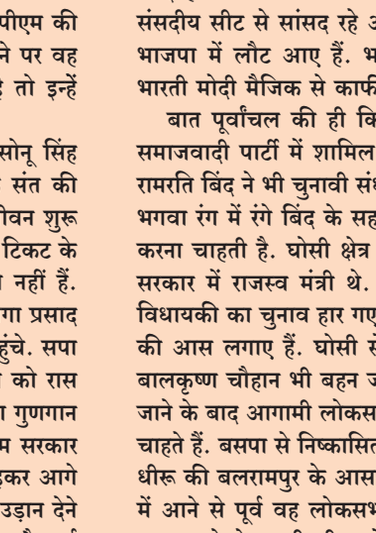

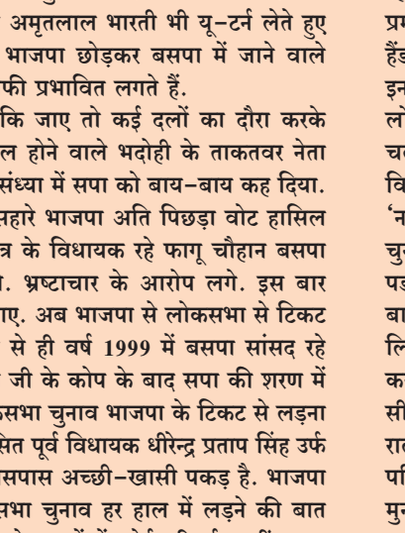

उत्तराखंड के सर्द मौसम को तपन देने का काम लोकसभा का चुनाव कर रहा है. लोकसभा के चुनाव की अभी तारीख घोषित नहीं हुई है, बावजूद इसके राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी अखाड़े में उतर कर ताल ठोकने लगे हैं. देश के दोनों राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग राज्य की पांचों संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों की स्थिति साफ कर दी है. इन दलों ने अभी अपने प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा नहीं की है. सूत्र बताते हैं कि पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के मौजूदा सांसद सतपाल महाराज से भाजपा नेता और पूर्व जनरल भूवन चन्द्र खंडूरी का मुकाबला होगा. इसी क्षेत्र से एक और पूर्व जनरल टीपीएस रावत के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है. दो पूर्व जनरलों की मौजूदगी से चुनावी मुकाबला त्रिकोणात्मक तो होने के साथ ही काफी रोचक भी होगा.

वर्तमान सांसद सतपाल महाराज 2009 के चुनाव में कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में गए तत्कालीन सांसद और पूर्व जनरल टीपीएस रावत को करारी शिकस्त दी थी. सतपाल महराज 1996 में भी यहीं से सांसद चुने गए थे. तब भी महाराज ने जनरल खंडूरी को ही हराया था. इस विजय के चलते कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें खुश होकर केन्द्र सरकार में लालबत्ती देकर सम्मानित किया था. महाराज को रेल राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया था. पूर्व सांसद जनरल खंडूरी 1991 में इसी संसदीय सीट से चुन कर संसद पहुंचे थे. इसी के साथ उनकी जीत का क्रम शुरू हुआ. इसके बाद 1998, 1999 और 2004 में इस क्षेत्र की जनता ने जनरल खंडूरी को जीता कर संसद भेजा. जनरल की ईमानदार कार्यशैली ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई को बहुत लुभाया. अटल जी ने जनरल खंडूरी को अपने कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान देने के साथ भूतल परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री का दायित्व सौंपा, जिसमें अपनी ईमानदारी की खूबी के कारण जनरल खंडूरी बेदाग छवि के नेता सिद्ध हुए.

सतपाल महाराज एवं जनरल खंडूरी 1991 से 2004 तक पौड़ी सीट पर लगातार आमने-सामने के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं. भाजपा के टिकट से टीपीएस रावत उप चुनाव में पौड़ी से सांसद चुने गए. जनरल रहे टिपीएस रावत की पहचान राज्य में एक दल-बदलू नेता की है. वे 2007 में कांग्रेस के टिकट से विधायक एवं मंत्री भी रहे. उनके राजनीतिक गुरु भी सतपाल महाराज ही रहे. अवसर मिलते ही पलटी मारना उनकी राजनीतिक कौशल का अंग रहा है. इस बार के चुनाव में सैन्य परिवारों के मतों का विभाजन करा कर अपने राजनीतिक गुरु को मदद करने का मकसद अभी से लोग समझने लगे हैं. राजनीति के अपने मध्यकाल में जनरल टीपीएस ने जनरल खंडूरी के लिए पाला बदलते हुए फौजी प्रेम के नाम पर अपने पद से त्यागपत्र देकर सीट खाली कर दी थी. इसी सीट से जीत कर जनरल खंडूरी ने मुख्यमंत्री का दायित्व सम्भाला. जनरल खंडूरी द्वारा खाली की गई सीट से टीपीएस को 2008 में भाजपा की सीट से सांसद बनने का मौका मिला. जनरल खंडूरी एवं भाजपा के व्यवहार से नाराज टीपीएस ने राज्य में अपना उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के नाम से एक राजनीतिक संगठन बना कर भाजपा को इसकी औकात बताने का संकल्प लिया. टीपीएस ने आम आदमी पार्टी के तर्ज पर भ्रष्टाचार और जनता की उपेक्षा को मुद्दा बना कर दोनों राष्ट्रीय दलों को उनकी हैसियत बताने का संकल्प लिया है. धर्म और राजनीति का महारथी रहे सतपाल महाराज को इस बार दो पूर्व जनरलों से दो-दो हाथ करना होगा. जनरल (खंडूरी) तो उनके धूर राजनीतिक विरोधी रहे हैं. दूसरा उनके घर का विभिषण है. टीपीएस जनरल खंडूरी के लिए विभिषण सिद्ध हुए तो सतपाल राम की तरह नायक बन कर उभरेंगे.

चेला-गुरु के लिए विभिषण बना तो जनरल रहे खंडूरी को महानायक बनने से कोई नहीं रोक सकता. त्रिकोणात्मक स्थिति में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है. भाजपा को सर्वाधिक संकट इसके अपने विभिषणों से ही रहा है. खंडूरी है जरूरी का नारा लगने के बाद किस तरह दल के कद्दावर नेताओं ने उनके पीठ में छूरा भोंक कर उन्हें धराशायी किया, इस घटना से मोदी को उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के संदर्भ में भी सीख लेनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

समाजवादी पार्टी की 'देश बचाओ-देश बनाओ' रैली

देश की जनता चाहती है कि उसका नेता ग़रीबों का नेता हो. उसका नेता किसानों का नेता हो. समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता खुशनसीब हैं कि उनके पास नेताजी (मुलायम सिंह यादव) हैं. लोकसभा चुनाव 2014 हमारे लिए एक मौक़ा है और हमारी जनता से अपील है कि इस मौके को हाथ से न जाने दें. समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपने सभी वायदे पूरे कर रही है. हमारी सरकार ग़रीबों, किसानों और युवाओं को फ़ायदा पहुंचा रही है. आसपास के अन्य प्रदेशों से तुलना कर लें, उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे बेहतर सरकार है. उक्त बातें रामनगर वाराणसी के रामबाग मैदान में आयोजित समाजवादी पार्टी की देश बचाओ-देश बनाओ रैली को सम्बोधित करते हुए सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने कही.

समाजवादियों को जगाने के लिए आयोजित इस जनसभा में लाखों के जनसैलाब को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने कहा कि लैपटॉप, किसान दुर्घटना बीमा, फ्री एम्बुलेंस सेवा, किसानों को मुफ़्त बिजली-पानी देने के साथ ही उनके खाद्य और बीज का ख्याल रखकर हम जनता का पैसा जनता को वापस लौटा रहे हैं. जनता ने सपा की सरकार बनाई और इसीलिए हम जनता की मदद कर रहे हैं. खचाखच भरे मैदान में लोगों से अपील करते हुए कहा कि सपा की ताक़त को दिल्ली तक पहुंचाने में मदद करें, तभी जो सपना हमने देखा है, वो पूरा होगा. तभी देश बचेगा और देश बनेगा. शिक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने

कहा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी यूपी में एमबीबीएस के लिए सिर्फ़ 1134 सीटें थीं, जिनमें 500 सीटों को और बढ़ा दिया गया है. हम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज की नींव डालना चाहते हैं, जिसमें जहां मेधावियों को शिक्षा देने के साथ ही रोज़गार के अवसर सुलभ कराए जाएंगे तो वहीं ग़रीबों को मुफ़्त इलाज भी होगा और इन्हें दवाएं भी बिना पैसे में ही दी जाएंगी. मुख्यमंत्री ने अपने पिटारे से वाराणसी और चन्दौली को भी मेडिकल कॉलेज का तोहफ़ा दिया. कहा कि अगला बजट आएगा तो इसमें वाराणसी और चन्दौली सीमा पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी. बसपा सरकार को हाशिये पर लेते हुए कहा कि हम कहीं पत्थर और स्मारक नहीं बनवा रहे. हम विकास की बात करते हैं और विकास में ही यक़ीन रखते हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री से सबसे ज़्यादा उम्मीदें चन्दौली की जनता को थी. जो डेढ़ दशक पहले जिला घोषित होने के बाद भी मुख्यालय के भवन के लिए तरस रहा है. उम्मीद भी थी कि इस बार मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय का शिलान्यास ज़रूर करेंगे और चन्दौली की झोली तोहफ़ों से भर देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार कुछ हड़बड़ाहट में थे. जनता को सम्बोधित करने में भी इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा. हमेशा खुलकर बोलने वाले अखिलेश इस बार काफ़ी शांत दिखे और अपने संक्षिप्त 12 मिनट के भाषण में इन्होंने सिर्फ़ अपनी सरकार का ही गुणगान किया.

मुख्यमंत्री के बाद समाजवादी पार्टी के क़द्दावर नेता एवं कैबिनेट मंत्री आज़म खान ने मंच संभाला. मुज़फ्फरनगर दंगों पर बीजेपी और कांग्रेस सहित बसपा को जमकर लताड़ा. इशारों में कहा कि हिन्दुस्तान को गुजरात बनाने वालों, मुज़फ़्फरनगर में आग लगाने वालों अब तुम्हारी खैर नहीं है. आज़म ने कहा कि आज यहां काशी में लोकतंत्र का कुंभ जमा हुआ है, जिसे वे फैसला करना है कि वो नरेन्द्र मोदी को वोट नहीं देंगे. मुज़फ़्फ़रनगर के लोगों को आईएसआई का दर्जा देने वाली कांग्रेस को भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं है और मस्जिद की जगह शौचालय बनाने की बात करने वाले कांशीराम की पार्टी बसपा को भी हम नहीं बख्शने वाले. इस बार पार्लियामेंट का चुनाव नए हिन्दुस्तान का चुनाव करेगा. जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पर लिखा होता है कि 'यह राष्ट्र की सम्पत्ति है, इसकी सुरक्षा करें,' इसी तरह से मुलायम सिंह यादव राष्ट्र की सम्पत्ति हैं. इन्हें संभालें और पीएम बनाएं. किसी के बहकावे में न आएं. लोग आपको बहुत सब्ज़बाग़ दिखाऐंगे. हमने हर क्षेत्र में काम किया है. शिक्षा के क्षेत्र में हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जो एक ऐसा चिराग़ रौशन करेगा, जिससे दुनिया सबक़ लेगी और हिन्दुस्तान का मुस्तक़बिल संवरेगा. सिखों को सम्बोधित करते हुए आज़म खां ने इन्हें पीलीभीत में हुए सिखों पर अत्याचारों की दास्तां सुनाई और कहा कि इस बुरे वक्त में भी सिर्फ़ मुलायम सिंह यादव सिख समुदाय के साथ थे. इसलिए पूरा हिन्दुस्तान यह क़सम खाए कि अबकी बार पार्लियामेंट पर झंडा मुलायम सिंह यादव के हाथ से फहरेगा. आज़म खान मीडिया से खासे नाराज़ दिखे. इन्होंने मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली. कहा कि आज का मीडिया देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है. ये मीडिया वाले समाज को आइना दिखाते हैं, लेकिन खुद कभी आइना नहीं देखते और ग़लत आइना दिखाने के चक्कर में कभी-कभी इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ 'तहलका' बन जाती है. एक अंग्रेज़ी चैनल की आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट ऑफ़ कंटेम्प्ट लागू होना चाहिए. सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अगर आप किसी को गाली देंगे तो ये ज़रूर याद रखें कि इसका मुक्का भी बहुत मज़बूत है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मंच संभालते ही जनसैलाब का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि युवा ही हमारी शक्ति हैं. इनके ज़रिए सपा देश से भेदभाव मिटाना चाहती है. सपा ऊंच-नीच और धर्म-मज़हब की खाई पाटने का काम करती है. कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में घोटाले अत्याचार, भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं किया है. महंगाई और भूख से देश की जनता बिलबिला रही है. इन सब के लिए कसूरवार कांग्रेस है. कांग्रेस ने गांधी के सपनों के हिन्दुस्तान को चौपट कर दिया है. आज चीन हमें हमारी सीमा के 19 किमी अंदर घुसकर आंखे तरेर रहा है. राजनारायण की धरती के वासियों 2014 चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, क्योंकि इसमें न कांग्रेस को बहुमत है और न ही बीजेपी को. इसमें सपा की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है. बस आप पूर्वांचल से सभी सीटें जिता कर देश बचा दें, हम देश बना देंगे. भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने की बात करते हैं. तुम यहां भी क़त्लेआम करवाना चाहते हो, औरतों को नंगा करना चाहते हो. हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे. बीजेपी के पास अफ़वाह फैलाने के सिवा और कोई काम नहीं है. इन्होंने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है. सपा सुप्रीमो ने जाते-जाते अपने कार्यकर्ताओं को शिष्टाचार का पाठ भी पढ़ाया. कहा कि कार्यकर्ता घर-घर विनम्रता से जाकर लोगों को सपा की नीतियां और विकास की गाथा बताएं. तब जनता इनके साथ होगी और फिर दिल्ली में सरकार बनाने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता.

मुलायम सिंह ने अपने भाषण में लोकसभा चुनाव का एजेंडा जल्द से जल्द तैयार करने की बात कहते हुए कहा कि गांधी के सपनों का भारत हम बनाएंगे. इन्होंने पूर्वांचल से लोकसभा मैदान में ताल ठोंक रहे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी मंच से की और जनता के सामने इनकी हाजिरी लगाई. इस सभा की अध्यक्षता हाजी लाल मोहम्मद ने की. धन्यवाद ज्ञापन चन्दौली सांसद रामकिशुन यादव ने किया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश सिंह, स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन, रोमगोविन्द चौधरी, नारद राय, अनीस मंसूरी, सैयदराजा विधायक मनोज सिंह डब्लू, राधेमोहन सिंह, नियाज़ अहमद, बाबूलाल यादव, प्यारेलाल अग्रहरी, मिर्ज़ापुर सपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव आदि समेत पूर्वांचल के सभी सांसद, विधायक एवं क़द्दावर नेता व पादाधिकारीगण मौजूद रहे. और रवाना हो गए. इससे चन्दौली की जनता को काफ़ी ठेस पहुंची है और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को इसका खामियाज़ा लोकसभा चुनाव में चन्दौली सीट गंवा कर भुगतना पड़े, क्योंकि चन्दौली से सपा सांसद रामकिशुन यादव भी जनता पर अपना प्रभाव छोड़ने में असफ़ल साबित हुए हैं. इन्होंने पांच बरस के अपने कार्यकाल को महज़ रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज बनवाकर जाम के जाम से मुक्ति दिलाने के लॉलीपॉप तक ही सीमित रखा है. जो आज तक सिर्फ़ काग़ज़ों तक ही सीमित है. इसे भी अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया है.

खैर चन्दौली की जनता तो इस बार बदलाव चाहती है. बशर्ते कि इसे कोई पंडित कमलापति त्रिपाठी और कल्पनाथ राय जैसा खेवनहार मिले. जिसे तलब हो कि धान का कटोरा, धान का कटोरा ही रहेगा और लोहिया और राजनारायण की सामाजिक संकल्पना से चन्दौली देश-प्रदेश के पटल पर स्थापित रहेगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

सीएम ने मुग़लसराय को बनाया नई तहसील

'देश बचाओ-देश बनाओ' रैली की समाप्ति के बाद सीढ़ियों तक पहुंचते-पहुंचते सूबे के मुखिया अखिलेश सिंह यादव के क़दम ठिठक गए. वह लौट कर माइक की तरफ़ वापस आए और चन्दौली सांसद व लोकसभा प्रत्याशी रामकिशुन यादव को बुलाया. दोनों ने कुछ खुसर-पुसर की और सीएम ने फिर माइक थाम लिया. सिर्फ़ एक लाइन में कहा कि मुग़लसराय को तहसील का दर्जा दिया जा रहा है. तहसील की घोषणा करने के बाद सीएम अपने उड़नखटोले की तरफ़ बढ़ गए. मुग़लसराय को तहसील बनाकर समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहां की जनता को जहां तोहफ़ा दिया है तो वहीं जाने-अनजाने में इसने नौगढ़ और बबुरी की जनता को रूठने का मौक़ा भी मुहैया कराया है, क्योंकि चन्दौली जनपद के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नौगढ़ को भी काफ़ी समय से तहसील बनाए जाने की मांग की जा रही थी. वहीं बबुरी के लोगों को उम्मीद थी कि इनका क़स्बा ब्लॉक का दर्जा प्राप्त करेगा. यही नहीं, इसके साथ ही चन्दौली की 17 साल पुरानी आस भी टूट गई. स्टेज के समीप ही लगे शिलापटों का शिलान्यास करने से भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चूक गए. इन्होंने चन्दौली जनपद के बरसों पुराने मुख्यालय निर्माण के सपने को फिर अधर में छोड़ दिया

कार्यालय नगर पालिका परिषद, जनपद महराजगंज

26 जनवरी 2014 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद महराजगंज अपने नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है तथा अपने नागरिकों से निम्न अपेक्षाएं करती हैं.

1. नगर को स्वच्छ रखने हेतु कूड़ा का निस्तारण निर्धारित स्थल पर ही करें.
2. जल ही जीवन हैं पेयजल की टोटियों को खुला न छोड़ें.
3. बकाया करों की अदायगी समय से करें.
4. जन्म एवं मृत्यु की सूचना कार्यालय नगर पालिका परिषद महराजगंज में समय से दर्ज कराएं.
5. सड़े गले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें.
6. नगर में स्थित विद्युत पोलो परल गे प्रकाश उपकरणों को क्षति न पहुंचाएं.
7. नगर पालिका की भूमि, नाला, नाली, पोखरियों में तथा सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण न करें.
8. पालिथीन का प्रयोग न करें.
9. गृहकर निर्धारण में सहयोग करें.

(पृथ्वीनाथ गुप्ता)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद महराजगंज
जनपद-महराजगंज

(रीता)
अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद
महराजगंज
जनपद-महराजगंज

एवं सम्मानित सदस्यगण

1. श्रीमति ज़रीं जायसवाल 2. श्रीमती दुर्गावती देवी 3. श्री बोलगोपाल 4. श्री सुग्रीव 5. श्री गामा प्रसाद 6. श्री ब्रहमावती देवी 7. श्री हीरा पासवान 9. श्री परमानंद गौतम 10. श्री ब्रजभूषण प्रसाद 11. श्रीमती फूला देवी 12. श्री दीपक 13. श्रीमती रमावती देवी 14. श्री प्रदीप गौड़ 15. श्रीमती प्रभावती देवी 16. श्री अफजल अब्बासी 17. श्री नीतू 18. श्री श्याम नरायन यादव 19. श्री सिद्धार्थ नाथ शुक्ला 20. श्री राघवेंद्र मिश्र 21. श्री पवन कुमार सिंहानिया 22. श्रीमती शाहजहां 23. श्री विजई 24. श्रीमती दुर्गावती पांडेय

मनोनित सदस्यगण : 1. श्री अशफाक अहमद 2. श्री अमितेश गुप्ता 3. श्रीमती सोनी यादव 4. श्री रामा प्रसाद 5. श्री रामबेलास यादव

पदेन सदस्य : श्री सुदामा प्रसाद (मा. विधायक), श्री हर्ष वर्धन सिंह (मा. सांसद), श्री गणेश शंकर पांडेय (मा.एम.एल.सी. / सभापति).

घुघली ब्लॉक के सभी सम्मानित बी.डी.सी. सदस्यों कर्मचारियों, शुभचिंतकों एवं सहयोगियों को गणतंत्र दिवस एवं महाशिवरात्री की अनंत शुभकामनाएं

श्रीमती सुशीला जायसवाल
ब्लॉक प्रमुख
विकास खंड घुघली,
महराजगंज

ओम प्रकाश जायसवाल
प्रमुख प्रतिनिधि
विकास खंड घुघली,
महराजगंज

गणतंत्र दिवस और महाशिवरात्री पर जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

संजय जी, वरिष्ठ समाजसेवी
जनपद-महराजगंज

गणतंत्र दिवस और महाशिवरात्री पर जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

रितेश सिंह श्रीनेत
युवा नेता एवं समाजसेवी
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, पेट्रोल पम्प, बरडाड, गोरखपुर
सीबीएस ब्रिक्स फिल्ड, गोरखपुर

बधाई संदेश

स्वस्थ बच्चा स्वथ देश

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आई.सी.डी.एस. विभाग की ओर से समस्त जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं.

विभागीय सेवाएं

अनुपूरक पोषाहार टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से स्कूल पूर्व शिक्षा संदर्भ सेवाएं एवं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा.

गायत्री सिंह
जिला कार्यक्रम अधिकारी
बस्ती

आई. पी. पांडेय
मुख्य विकास अधिकारी
बस्ती

अनिल कुमार दमेले
जिलाधिकारी
बस्ती

भतीजे सीएम की तारीफ से मंत्री चचा गदगद

खंदीप कश्यप

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने चचा और कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के कामकाज से काफी खुश नजर आ रहे हैं. एक कार्यक्रम के दौरान सिंचाई मंत्री शिवपाल की भूरी-भूरी तारीफ करके मुख्यमंत्री ने एहसास करा दिया कि वह अपने मंत्रियों के कामकाज पर पूरी नजर रखते हैं. भतीजे मुख्यमंत्री से तारीफ के बोल सुनकर चचा गदगद हुए तो सत्ता के गलियारे में यह चर्चा का विषय बन गई कि क्या ऐसी तारीफ अन्य मंत्रियों की नहीं हो सकती है. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारम्भ करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तभी इन्होंने शिवपाल का गुणगान किया. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी सरकार ने राज्य को ठोस विकास की राह पर ले जाने का काम किया है. प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है. पूरे देश में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है, जहां किसानों को नहरों व सरकारी नलकूप से मुफ्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है. देश व प्रदेश की खुशहाली के लिए किसान की खुशहाली आवश्यक है. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए सीएम बोले कि कृषि उपज में यदि थोड़ी भी अड़चन आती है तो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े बदलने लगते हैं. श्री यादव ने उम्मीद जताई कि इस परियोजना के पूरा होने पर बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ मिलेगा और असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा. उन्होंने देश व दुनिया में

गरीबी मिटाने व पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक के प्रयासों और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसके लिए सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव को बधाई दी. इन्होंने कहा कि विभाग के कार्यों को बेहतर बनाने व अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए सिंचाई मंत्री के प्रयास प्रशंसनीय हैं. इन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है. तारीफ से गदगद सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने भी अपनी उपलब्धियों को एक-एक कर गिना डाला और कहा कि समाजवादी सरकार ने लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने का फैसला लिया. इसके तहत डेढ़ वर्ष की अवधि में बाण सागर परियोजना को पूरा किया गया. लंबित सरयू परियोजना के साथ-साथ बुन्देलखंड क्षेत्र के अधूरे बांध व नहरों को पूरा कराने का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है. जिस कार्यक्रम में सिंचाई मंत्री की तारीफ की गई, उसमें स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन, कृषि मंत्री आनन्द सिंह, कारागार मंत्री राजेन्द्र चौधरी, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री कैलाश यादव, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक रंजन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राकेश गर्ग सहित सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी, कृषक व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

65वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आई.सी.डी.एस. परिवार जनपद कुशीनगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन व शुभकामनाएं

विभाग द्वारा महिलाओं व बच्चों के कल्याणार्थ हेतु संचालित योजनाएं

1. 07 माह से 03 वर्ष के बच्चों के लिए विनिंग फूड्स जनपद में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों में वितरित कर लाभान्वित किया जाता है.
2. 03 से 06 वर्ष के बच्चों को एमाईलेज रिच एनर्जी फूड्स के अतिरिक्त हाट कुक्ड योजना व मार्निंग स्नैक वितरित कर उन्हें लाभान्वित किया जाता है.
3. गर्भवती, धात्री, माताओं व किशोरी बालिकाओं को एमाईलेज रिच एनर्जी फूड्स का वितरण कर योजना का लाभ प्रदान किया जाता है.
4. किशोरी शक्ति योजना

इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 01 शाला पूर्व शिक्षा 02 पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा 03 स्वास्थ्य जांच एवं वृद्धि निगरानी 04 टीकाकरण/प्रतिरक्षण योजनाओं को संचालित कर सुविधा प्रदान की जाती है.

जिला कार्यक्रम अधिकारी, कुशीनगर

स्वास्थ्य व पोषण दिवस

सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत गांव के लोगों, खास कर गरीब लोगों, महिलाओं और बच्चों तक अच्छी व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुचाने के उद्देश्य से की है. इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु गांव के स्तर पर कई नए प्रयास किए गए हैं - जैसे ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति की स्थापना, इस समिति व स्वास्थ्य केंद्रों व मुक्त राशि का आबंटन, आशा की नियुक्ति व स्वास्थ्य व पोषण दिवस मनाया जाना इत्यादि.

हर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में कम से कम एक बार स्वास्थ्य व पोषण दिवस मनाया जाना चाहिए.

आशा को स्वास्थ्य व पोषण दिवस से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, जैसे -सभी घरों में मुलाकात के लिए जाना, सभी गर्भवती स्त्रियों की सूची बनाना, उन बच्चों की सूची बनाना जिनका अभी तक टीकाकरण पूरा नहीं हुआ या वे पोलियो चक्र से छूट गए हैं या कुपोषण से ग्रस्त है या फिर अपंग है तथा उन सभी टीवी ग्रस्त लोगों की सूची बनाना जिन्हें दवा की जरूरत है इत्यादि.

यह सुनिश्चित करना आशा की जिम्मेदारी है कि जो लोग सूची में है, वे स्वास्थ्य व पोषण दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्र में जरूर आएं.

स्वास्थ्य व पोषण दिवस के जरिए निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाएं गांव के लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए-

सुविधाएं	जानकारी व सलाह	रेफरल
जैसे - टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच इत्यादि	जैसे - गर्भ निरोधकों व नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए सलाह	यानि इलाज के लिए सही जगह पर भेजा जाना.

डॉ आर.एस. सिंह
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद महराजगंज